हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 अगस्त, 1978

खंड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 29 अगस्त, 1978

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	..(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	..(2)25
अतांराकित प्र न एवं उत्तर	..(2)36
ध्यानाकर्शण सूचनायें	..(2)41
मेज पर रखे गए कागज–पत्र	..(2)44
वर्श 1978–79 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त)– (1) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा (2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	 ..(2)46 ..(2)46
आधे घंटे की चर्चा तथा विवाद बंद करने के लिए समय बदलने संबंधी अध्यक्ष महोदय का निरूपण	..(2)76

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरांभ)	..(2)77
आधे घंटे की चर्चा	..(2)85
आधे घंटे की चर्चा का समय बढ़ाना	..(2)91
आधे घंटे की चर्चा (पुनरांभ)	..(2)91
औचित्य प्र न	..(2)93
आधे घंटे की चर्चा (पुनरांभ)	..(2)94

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 29 अगस्त, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहिबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 509

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, इस प्र न पर काफी डिसक ान हो चुकी है, इसलिए मैं इस प्र न को नहीं पूछना चाहता।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, इस सवाल पर कल थॉरोली डिसक ान हो चुकी है, इसलिए अच्छा रहेगा कि यह प्र न न पूछा जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

CONSTITUENCY-WISE PROVISION FOR APPROACH ROAD

*__522. Swami Aditya Vesh:__ Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the Constituency-wise number of villages which have been provided with the facility of approach roads during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the State;

(b) the number of villages in Haryana where the facility of approach roads has not been provided so far;

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide facility of approach road in the villages as referred to in part (b) above; and

(d) if so, the time by which the facility is likely to be provided?

लोक निर्माण मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी):

(ए) अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(बी) 1272।

(सी) जी, हां।

(डी) राज्य में प्रत्येक मान्यता प्राप्त गांव को सड़क सुविधा देना प्रस्तावित है। परन्तु इस के लिए निश्चित समय बताया नहीं जा सकता क्योंकि यह प्रोग्राम धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Statement.

Sr. No.	Name of Constituency	Number of villages connected
I.	**Ambala District**	
1.	Kalka	4
2.	Naraingarh	1
3.	Sadhaura	14
4.	Chhachhrauli	9
5.	Yamunanagar	1
6.	Jagadhri	2
7.	Mullana	2
8.	Ambala Cantoment	--
9.	Ambala City	--
10.	Naggal	--
	Total:	**33**
II.	**Karnal District.**	
11.	Inderi	24
12.	Nilokheri	8
13.	Karnal	4

14.	Jundla	2
15.	Gharounda	5
16.	Assandh	1
17.	Panipat	1
18.	Sambhalka	3
19.	Naultha	2
	Total:	**48**
III.	**Kurukshetra District**	
20.	Shahabad	8
21.	Radaur	6
22.	Thanesar	10
23.	Pehowa	6
24.	Gulha	9
25.	Kaithal	--
26.	Pundri	3
27.	Pai	2
	Total:	**34**
IV.	**Rohtak District.**	
28.	Hassangarh	1

29.	Kiloi	--
30.	Rohtak	--
31.	Meham	1
32.	Kalanaur	--
33.	Beri	--
34.	Salhawas	--
35.	Jhajjar	1
36.	Badli	1
37.	Bahadurgarh	--
	Total:	**4**
V.	**Sonepat District.**	
38.	Baroda	3
39.	Gohana	--
40.	Kaliana	3
41.	Sonepat	--
42.	Rai	2
43.	Rohat	--
	Total:	**8**
VI.	**Jind District.**	

44.	Kalayat	2
45.	Narwana	--
46.	Uchana-Kalan	4
47.	Rajond	--
48.	Jind	1
49.	Julana	7
50.	Safidon	2
	Total:	**16**
VII.	**Gurgaon District.**	
51.	Faridabad	--
52.	Meoal Maharajpur	1
53.	Balabgarh	1
54.	Palwal	3
55.	Hassanpur	6
56.	Hathin	2
57.	Ferozepur Jhirka	1
58.	Nuh	4
59.	Taoru	8
60.	Sohna	--

61.	Gurgaon	--
62.	Pataudi	2
	Total:	**28**
VIII.	**Bhiwani District.**	
63.	Badhra	1
64.	Dadri	--
65.	Mundhal Khurd	--
66.	Bhiwani	1
67.	Tosham	--
68.	Loharu	--
69.	Bawani Khera	--
	Total:	**2**
IX.	**Hissar District.**	
70.	Barwala	--
71.	Narnaund	1
72.	Hansi	--
73.	Bhatu Kalan	6
74.	Hissar	--
75.	Ghirai	--

76.	Tohana	3
77.	Ratia	8
78.	Fatehabad	3
79.	Adampur	1
	Total:	**22**
X.	**Sirsa District.**	
80.	Darba Kalan	4
81.	Ellenabad	4
82.	Sirsa	1
83.	Rori	6
84.	Dabwali	4
	Total:	**19**
XI.	**Mohindergarh District.**	
85.	Bawal	2
86.	Rewari	4
87.	Jatusana	1
88.	Mahindergarh	6
89.	Ateli	6
90.	Narnaul	1

	Total:	**20**
	G. Total:	**246**

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे दी गई है, उसके हिसाब से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 90 हल्कों में 26 हल्कों की उपेक्षा क्यों की गई है और जिन हल्कों को सड़कें दी गई है उनको किस आधार पर सड़कें दी गई है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, जिन गांवों को सड़कों की सहूलियत दी जाती है उस वक्त कई बातों का ध्यान रखा जाता है और तीन कैटेगरी की सड़कें होती है। जो 'ए' क्लास रोड्ज होती है उनका काम पहले देखा जाता है उसके बाद 'बी' क्लास व सब के बाद 'सी' क्लास रोडज का काम किया जाता है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, सरकार की पालिसी थी कि हरेक हल्के में एक स्कूल अव य दिया जाएगा क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उसी तरह से क्या हरेक हल्के को सरकार एक सड़क मुहैया करने का विचार रखती है ताकि लोगों को किसी प्रकार की आने जाने की दिक्कत महसूस न हा?

चौधरी मेहर सिंह राठीः सपीकर साहब, मैंने पहले बताया है कि हम यह कोि ा ा करेंगे कि हरेक मान्यता प्राप्त गांव को सड़क सुविधा दी जाए जिससे हमारे किसी भी माननीय सदस्य भाई को निरा ाा न हो।

श्री फतेह चंद विजः अध्यक्ष महोदय, करनाल जिले में 1961 में दरिया का रूख बदलने के कारण कुछ गांव जो कि लगभग 20 के करीब होंगे, इधर हरियाणा में भाामिल हो गए है और उन गांवों को आत तक एक भी सड़क की सुविधा नहीं दी गई है। क्या सरकार का उन गांवों की तरफ कोई ध्यान है और क्या उन गांवों को सड़क की सुविधा प्रदान करने का सरकार का कोई विचार है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य इसके लिए अलग से नोाटिस दें तो बता दिया जाएगा।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारी जनता पार्टी की सरकार बनी है उस वक्त से लेकर आज तक हिसार जिले में 350 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई जा चुकी है और केवल अकेले नारनौंद में 244 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, क्या यह बात सही है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः बिल्कुल गल्त है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, बहुत से ऐसे गांव है जो कि एक तरफ से तो सड़कों से मिले हुए है लेकिन उन गांवों को जिला हैड क्वार्टर्ज तक जाने के लिये जिन सड़कों से मिलाया हुआ है, वे सड़कें बड़ा लम्बा रास्ता काट कर जिलों तक जाती है। अगर ऐसे गांवों के साथ एक किलोमीटर लम्बी सड़क भी बना दी जाए तो गांवों का लिंक छोटा हो जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तरह की स्कीम सरकार के विचाराधीन है जिससे कि लोगों को ज्यादा दूर का चक्कर लगाकर जिला हैड क्वार्टरों पर न जाना पड़ें, क्या मंत्री महोदय के दिमाग में ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, मैं विचार कर रहा हूं कि इन को सड़कें दी जाएं।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार बनने के बाद हल्का पाई में कितने किलोमीटर लम्बी सड़के बनाई गई है? अगर नहीं बनाई गई तो क्या सरकार वहां पर सड़कें बनाने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः पोहलू साहब यह अलग सवाल है, आप पहले इस बारे में अलग से नोटिस दें तभी मिनिस्टर साहब बता सकेंगे (ाोर) क्या मिनिस्टर साहब पोहलू साहब के सवाल का जवाब देना चाहते है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, सरकार सभी गांवों में सड़कें बनाने का विचार रखती है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पी0 डब्ल्यू0 डी0 के मंत्री महोदय ने यह आ वासन दिया था कि जो सड़कें गांव वालों के श्रमदान के माध्यम से बनाएंगे उन सड़कों को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर साहिबा इसके लिये अलग से नोटिस दें तो बता दिया जाएगा।

श्री मूलचंद मंगलाः स्पीकर साहब, जिला गुड़गांव की तहसील नूह, फिरोजपुर झिरका और पलवल में काफी फ्लड आए थे ओर उसके बाद सरकार की तरफ से यह आ वासन दिया गया था कि उन इलाकों में सड़कों का काम सब से पहले किया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस साल में भी फ्लड आने की संभावना है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि फ्लड से पहले इन इलाकों को सड़कां का काम मुक्कमल कर दिया जाएगा?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, कोि ा ा की जाएगी कि उन सड़कों की मुरम्मत का काम सबसे पहले किया जाए।

कंवर राम पाल सिंहः स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से यह आ वासन दिया गसा था कि जो सड़कें स्टेट टू स्टेट

आपस में मिलाती है, उन सड़कों को सबसे पहले मुकम्मल किया जाएगा जैसे पहले कहा गया था कि राजस्थान पंजाब को मिलाने वाली सड़कों को पहले प्रायरिटी दी जाएगी। एक मेरठ रोड़ है जो करनाल से जाती है, वह वहीं की वहीं है उसको अभी तक प्रायरिटी नहीं दी गई हैं। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि डिपार्टमैंट की तरफ से इसस्कीम पर कोई ऐक ान लिया जा रहा है? क्या सरकार उस सड़क को प्रायरिटी देने के लिए तैयार है ताकि उस सड़क का काम पहले हो सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, सरकार ने इस काम के लिए 10 लाख रूपये की रा ाी पहले ही निर्धारित कर रखी है।

डा0 बृजमोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, अम्बाला जिला पिछले कई सालों से सबसे पीछे रहा है और अब की बार अम्बाला जिले में फ्नड भी आया है। जैसे हरेक जिले को कम से कम साढ़े चार या पांच किलोमीटर की सड़क प्रोवाइड की जाने की योजना है। उसी प्रकार क्या अम्बाला जिले को भी प्रैफरेन्स देने का सरकार कोई विचार रखती हैं। क्योंकि हमारा अम्बाला जिला हर लिहाज से पीछे है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः ठीक बात है। हम कोि ा ा करेंगे कि किसी भी जिले के साथ कोई ज्यादती न की जाए और हरेक जिले को सड़को की सहूलियत दी जाए।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, ये जो सड़के बनाई जा रही है, इनमें मार्किट कमेटियों और सोसायटीज की सड़कें भी है और वे यूं ही की यूं ही पड़ी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन सड़कों के लिये सरकार ने क्या काइटेरिया बना रखा है? क्या वे सड़कैं पी0डब्ल्यू0डी0 वाले बनायेंगे या कि वहीं की वहीं रहेगी।

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, इस बारे मैं अभी कुछ विचार हो रहा है।

चौधरी पीर चंदः स्पीकर साहब, हिसार जिला जो पिछले 20 सालों से सबसे पीछे है, हरेक लिहाज से बैक पर है, सड़कों में भी बैक पर है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस जिले में जहां–जहां पक्की सड़कें गांवों को नहीं दी गई है उन गांवों को भीघ्र ही पक्की सड़कों से मिला दिया जाएगा और हिसार को दूसरे जिलों के बराबर लाने की कोि ा ा करेंगे?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, हिसार जिले में 84.42 परसेन्ट सड़कें बनी है।

चौधरी खुर ीद अहमदः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि हरियाणा में तीन कैटेगरीज की सड़कें है। क्या उनके नोटिस में यह बात भी है कि हरियाणा मैं कई गांव ऐसे है जहां किसी भी कैटेगरी की सड़क नहीं है। जैसे पानीपत तहसील में बेसिक–गढ़ी, राना–माजरा, नवादा, जलालपुर और पत्थर गढ़ गांव है और करनाल जिला में मुंडी–गढ़ी गांव है जहां किसी भी कैटेगरी की सड़क नहीं है?

चौधरी मेहर सिंह राठीः ऐसी सड़को के बारे में मैंने मुख्य मंत्री जी सक बात की थी और यह फैसला किया गया है कि ऐसी सड़को को 'सी' कैटेगरी मैं भाामिल किया जाए।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमि ान है कि यह सड़कों का सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। यह सवाल कल भी आया था कि एक दो जिलों में तो सड़कें ज्यादा बन चुकी है और बाकी में नहीं बनी है। मेरे हल्के में बिल्कुल भी कोई सड़क नहीं बनी है। अभी मिनिस्टर साहब ने बताया था कि पाई में केवल दो गांवों में सड़कें बनी है जो कि गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर आधे घंटे की बहस रखी जाएं। इसके साथ–साथ मैं वजीर साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि कौन–कौन सी सड़क पर पत्थर और रोड़े अभी नहीं पड़े है?

श्री अध्यक्षः इस विशय पर मैं हाउस की सैंस को देख चुका हूं, मैंबर काफी एजीटेटिड है इसलिए मैं बिजनैस एडवाईजरी कमेटी के सामने यह प्वायंट रखूंगा कि इस विशय पर आधे घंटे की डिसक ान का मौका दिया जाए।

OPENING OF GOVERNMENT SHOPS AT BUS STANDS IN THE STATE

***550. Chaudhri Peer Chand:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open their own shops at the Bus Stands in the State?

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेंद्र सिंह ओजला): सरकार के पास राज्य के बस स्टैंडों पर अपनी दुकाने खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चौधरी पीर चंदः क्या चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की कृपा करेंगे कि जो दुकाने बस स्टैंडों पर है उन पर बिल्कुल रद्दी चीजें मिलती है और वे पैसे भी ज्यादा चार्ज करती है इस चीज को देखते हुए सरकार अपनी दुकानें खोलेगी जो कि बगैर मुनाफे के चलाई जाएं?

श्री सुरेंद्र सिंह ओजलाः हमने तीन बस स्टैंडों पर दुकाने खोली थी। अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट और पानीपत लेकिन पानीपत में हमें दो महीने के बाद ही दुकान बंद करनी पड़ीं। वह दुकान फर्स्ट फ्लोर पर थी इसलिये वहां पर यात्री

खाना खाने के लिये नहीं जाते थे। दूसरी दो दुकानें भी घाटे में चल रही है इसलिये सरकार अपनी दुकाने खोलने का विचार नहीं रखती।

चौधरी संत कंवरः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब के नोटिस में यह बात है कि बस स्टैंडों पर जितनी भी दुकानें है वे मार्किट रेट से ज्यादा मंहगी चीजें बेचती है? क्या सरकार कोई ऐसा इंतजाम करेगी कि उन दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई जाए और दोशी के विरूद्ध सख्ती की जाए ताकि ठीक भाव पर यात्रियों को चीजें मिल सकें?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः जिस वक्त इन दुकानों का ठेका दिया जाता है तो उस वक्त भाव भी तय किये जाते है। अगर हमारे पास कोई ि ाकायत आती है तो हम एक ान भी लेते है। जहां तक रेट लिस्ट लगाने का सवाल है, वह हम लगवा देंगे।

चौधरी उदय सिंह दलालः क्या चीफ मिनिस्टर सैक्रेटरी साहब के नोटिस में यह बात है कि करनाल बस स्टैंड पर जो रोडवेज का रैस्टोरैंट है वहां पर दूध की सप्लाई बंद की हुई है जबकि हरियाणा सरकार की यह नीति है कि हर जगह दूध की दुकानें हों। मैं उस रैस्टोरेंट पर खुद गया था और मेरे साथ मिल्टरी के एक मेजर भी थे, हमने दूध मांगा तो उन्होंने कहा कि हम दूध का बिल नहीं काट सकते क्योंकि हमें दूध सप्लाई न

करने की हिदायतें है। मैंने इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा था।

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः ऐसी कोई ि ाकायत हमारे नोटिस में नहीं आई है आज आपने मेरे नोटिस में यह बात लाई है, हम इसको एग्जामिन करवा देंगे।

स्वामी अग्निवे ाः मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हर बस स्टैंड पर और दुकानों के साथ–साथ किताबों की दुकानें भी खुली हुई है। उन दुकानों पर किताबों के नाम से बहुत ही अ लील साहित्य भी देखने को मिलता हैं। एक भारीफ आदमी अपनी बहिन बेटी के साथ वहां से एक अखबार भी नहीं खरीद सकता क्योंकि कुछ किताबों ऊपर बहुत ही अ लील चित्र अंकित होते हैं। ये किताबें हरियाणा के हर बस स्टैंड पर खुल्लमखुल्ला बिक रही है। इसके बावजूद भी सरकार बस अड्डों पर दुकानें निलाम कर रही है। अगर मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह चीज है तो ऐसी दुकानों को बंद करवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः अभी तक हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं थी लेकिन स्वामी जी ने जो बात कही है इसके बारे में हम फौरी तौर पर गौर करेंगे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अभी चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब ने बस अड्डों पर अपनी दुकानें न खोलनें का

कारण बताया कि एक तो दुकानें घाटें में चल रही है और घाटे का कारण उन्होंने दुकान फर्स्ट फलोर पर होने का बताया। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वे ग्राउंड फलोर पर दुकानें क्यों नहीं खोलते?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ तीन बस स्टैंडों पर दुकानें खोली गई थी। हम जो खाना देते है वह टूरिजम वालो के बराबर देते है लेकिन जो दूसरे दुकानदार है उनका खाना कुछ सब स्टैंडर्ड का होता है इसलिये हम उनका कम्पीटी ान नहीं कर सकते। इस वजह से हमैं घाटा रहता है। दूसरे जहां तक ग्राउंड फ्लोर पर दुकान खोलने का सवाल है इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

चौधरी पीर चंदः जैसे कि अभी चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब ने बताया कि तीनों जगह पर दुकानें घाटें में चल रही है। कहीं इसका कारण यह तो नहीं है कि उन दुकानों में जो स्टाफ लगाया गया है वह गड़बड़ करता हो? मैं सरकार को एक बार फिर यह सुझाव देना चाहता हूं कि गरीब आदमियों को रियायत देने के लिये वह अपनी दुकानें खोलें।

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः जो स्टाफ वहां लगा हुआ है उसमैं मेरा ख्याल है कोई भी अन–ट्रेंड आदमी नहीं है। जहां तक गड़बड़ी का सवाल है अगर हमारे नोटिस में कोई ि ाकायत आएगी तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री बलदेव तायलः जैसे घाटे के कारण इन्होंने दुकानें बंद कर दी है कहीं ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को तो बंद करने का इरादा नहीं है?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः हमारी रोडवेज में तो घाटा है ही नहीं इसलिए इसे बंद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

चौधरी हुक्म सिंहः क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैकेटरी साहब बताएंगे कि जो चीजें बस स्टैंडों पर बेची जाती है वे सिर्फ मंहगी ही नहीं होती बल्कि गंदी भी होती है तो क्या कभी आपने उनका सैम्पल भी भरवाया है?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः इसके बारे में हमने एक महीना पहले नोट लिखा था कि हर 15–20 दिन बाद डाक्टरों द्वारा चीजों की चैकिंग की जाए जोकि हो रही है।

Mr. Speaker: Next Question please. But before we take it up, I would like to congratulate the Chief Parliamentary Secreatary कि वह सवालों का जवाब बेहतरीन तरीक से तैयार करके आए है।

KULTANA, GANDHRA AND PAKSMA DRAINS

***553 Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the place from where the Kultana drain is being started in district Rohtak together with the time by which the said drain is likely to be completed; and

(b) the time by which the remodelling of Gandhra drain and Paksma drain are likely to be completed in Rohtak District?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री वीरेंद्र सिंह):

(क) यह ड्रेन जिला रोहतक में ि ामली गांव के झील वाले रकबे से भुरू होती है और उसे 30/6/79 तक पूरा करने की सम्भावना है।

(ख) 30/6/79 तक।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, रोहतक मैं सांपला रोड़ और घागरा रोड़ के बीच में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस पानी को कुलताना ड्रेन मैं डाला जाएगा या नहीं?

श्री वीरेंद्र सिंह: यह 41 किलोमीटर लम्बी ड्रेन है, ड्रेन की पूर तफसील बताना कि किस–किस इलाके का पानी इसमें लगेगा, मेरे बड़ा मु ि कल है। उस रकबे में मैं गया था और मैंने उस इलाके को खुद देखा था। भाायद सांपला का पानी यह ड्रेन ले लेगी।

चौधरी राम कि ान: जिस तरह से कुलताना ड्रेन के बारे में बताया गया है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट जींद में भंबेवा ड्रेन खोद रहे है लेकिन अभी तक वह ड्रेन पूरी नहीं हुई। कलौट और सफीदों का एरिया बैकवर्ड है और फलड इफैक्टिड इलाका

है। भंबेवा ड्रेन आधी खुद चुकी है आधी खुदनी बाकी रहती है जिसकी वजह से उस इलाके में बरसात का पानी भर जाता है और बड़ा नुक्सान होता है। क्या मंत्री महोदय इसको पूरा करने की कृपा करेंगे?

श्री वीरेंद्र सिंहः जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल हरियाणा में बड़ा भारी फ्लड आयां हरियाणा में जब से जनता सरकार बनी, इसने फ्लड की रोकथाम के लिए कदम उठाए और टौप प्रायरिटी दी। बहुत कुछ किया गया, इसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा हरियाणा जनता है कि कितना काम फ्लड की रोकथाम के लिए सरकार ने किया है। इस बार मुझे यह बताते हुए खु ाी है कि गुड़गावां जिले में जो इलाका मेवात का है, जिसमें कई सालों से फ्लड से तबाही होती चली आ रही है, उसकी रोकथाम के लिए उजीना डाइव र्न ड्रेन का निर्माण कर रहे हैं जिसका उदघाटन सी0 एम0 साहब ने कर दिया है और यह ड्रेन रिकार्ड टाईम में बनी है। मैं सदन को वि वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल की बरसात से पहले, यानि 30. 6.79 तक, तकरीबन–तकरीबन सारे हरियाणा को फ्लड से बिल्कुल महफूज कर दिया जाएगा।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः जहां तक ड्रेन बनाने का सवाल है, ड्रेन्ज की प्रोबलम को हल करने के साथ–साथ अगर उन पर पुल और वाटर कोर्सिज भी बना दिए जाएं तो सारी

समस्या हल हो जाएगी। क्या मंत्री महोदय ड्रेन्ज के साथ–साथ पुल और वाटर कोर्सिज बनाने का इन्तजाम करेंगे?

श्री वीरेंद्र सिंहः जो नई ड्रेन्ज बन रही है उन पर जो जरूरी रास्ते है, वे ज्यादा से ज्यादा बना दिए जाएंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में पिछले दिनों फ्लड से बड़ा नुकसान हुआ है और सरकार ने इस फ्लड को खत्म करने के लिए इस इलाके मैं ड्रेन मंजूर की थी, लेकिन पता नहीं अब उस इलाके मैं क्यों इतना भारी फ्लड आया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसको रोकने का इन्तजाम क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का संबंध मेन क्वै चन से नहीं है, अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो दे सकते है।

श्री वीरेंद्र सिहंः अगले 6 महीनों में इस ड्रेन को पूरा कर दिया जाएगा।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, रिट्ठल के फ्लड से बचने का एक ही रास्ता है और वह यह है कि रिट्ठल से किलोई और पाकिस्मा तक ड्रेन बनाई जाए। क्या मंत्री महोदय, पाकिस्मा ड्रेन को रिट्ठल तक एक्टैन्ड करने की कृपा करेंगे ताकि रिट्ठल के फ्लड का पानी पाकिस्मा ड्रेन में डाला जा सकें?

श्री वीरेंद्र सिंहः मैं रिटठल गांव गया था और चौधरी गंगा राम मेरे साथ थे, डेढ़ महीना पहले मैं मौका देख आया हूं, वहां पर कई सालों से तबाही होती आई है। पाकिस्मा ड्रेन को 30.6.79 को एक्सटैंड कर दिया जाएगा, इससे आपकी तकलीफ भी दूर कर दी जाएगी और (श्री मांगे राम गुप्ता की तरफ से विघ्न) आपकी तकलीफ भी दूर कर दी जाएगी।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब यह खु ाी की बात है कि सरकार ने हरियाणा को फ्लड की मार से बचाने के लिए हाउस को वि वास दिलाया है कि बहुत–सी ड्रेन्ज खोद कर पानी निकाला जाता है, बहुत काम हो रहा है। तहसील नारायणगढ़ से तकरीबन सारी नदियां निकलती है, लेकिन वहां पर पानी टिकता नहीं, कालका के आसपास गांवों के इलाकों को नदियों की टक्कर से काफी नुक्सान होता है।

श्री अध्यक्षः यह सवाल इससे संबंधित नहीं है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, कुलताना ड्रेन का सवाल हाउस में आया है और यह बहुत बड़ी समस्या है। जितनी एप्रोच ड्रेन्ज बनाई जा रही है उन सब का पानी ड्रेन न0 8 मैं चला जाता है जिससे बादली हल्का पानी में डूब जाता है, इसको बंद करना चाहिए। सारा पानी बादली हल्के में आ जाता है और सारे इलाके को खतरा पैदा हो जाता है। जब तक दिल्ली प्र ाासन इस पानी को निकालने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाता तब

तक इस ड्रेन में पानी न बढ़ाया जाए, इसको बंद किया जाए। क्या मंत्री महोदय इस समस्या पर विचार करेंगे?

श्री वीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, यह जो साहिबी नदी का एरिया है जिसमें जिला रोहतक, झज्जर तहसील और गोहाने का इलाका लगता है, इसकी जयोग्राफिकली सिचुए ान ऐसी है जिसके कारण इस इलाके का पानी जमुना में ही डाला जा सकता है। फिर भी मास्टर प्लान बकायदा तैयार है, नजफगढ़ ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दिल्ली की सरकार तैयार है लेकिन उनको फिनांसिज की डिफिकल्टी है। इस संबंध में मैं और दलाल साहब एग्जैक्टिव कौंसिलर से मिले थे और उस रकबे का दौरा किया था। मुझे उम्मीद है कि अगले साल इस ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी।

Loss due to Hailstorm

***563. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the villages Sangat Pura and Intal Kalan in district Jind were affected by the hailstorm in the recent past;

(b) if so, whether it is also fact that the assistance in the shape of loan or otherwise was given by the Government to the farmers of village Sangatpura more in comparison to the farmers of village Intal Kalan, especially when the latter village was much affected by hailstorm than former one;

(c) if so, the reason thereof; and

(d) whether it is also a fact that some of the persons got the assistance from the Government especially when they were not affected with the hailstorm?

राजस्व मंत्री(ठाकुर बीर सिंह):

(क) हां जी।

(ख) ग्राम संगतपुर के किसानों को ग्राम इन्ताकलां के किसानों के मुकाबले

(ग) कर्ज के रूप में अधिक सहायता आगे वर्णित कारणों से दी गई थी–

(1) ग्राम संगतपुर में नुकसान 61 प्रति ात तथा जबकि ग्राम इन्तालकलां मैं नुकसान केवल 38 प्रति ात था।

(2) पहले सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि जहां नुकसान 25 प्रति ात से 50 प्रति ात था वहां 50 रूपए प्रति एकड़ तथा जहां नुकसान 50 प्रति ात से अधिक था वहां 100 रूपए प्रति एकड़ की दर से तकावी दी जाए।

(3) इसके प चात् सरकार ने अपने निर्णय को सं ाोधित कर दिया और वर्श 1977 की बाढ़ तथा मार्च, 1970 की औलावृश्टि से जहां पर नुकसान 50 प्रति ात से अधिक था वहां 300 रूपए प्रति एकड़ की दर से तकावी देने की अनुमति दे दी।

इसलिए जिन गांवों में पहले तकावी नहीं बांटी गई थी वहां पर सं ाोधित निर्णय को कार्यान्वित किया गया और गांव संगतपुर में तकावी 300 रूपए प्रति एकड़ की दर से बांटी गई थी जबकि गांव इन्ताकलां में तकावी पहले बांटी जा चुकी थी। दूसरे अन्य गांव में बकाया तकावी देने के लिए उपायुक्त जींद ने सरकार को 10 लाख रूपए की मांग भेजी है।

(घ) नहीं जी।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैंने यह भी पूछा था कि क्या ऐसे लोगों को भी कम्पनसेट किया गया जिनके पास कोई जमीन नहीं थी?

ठाकुर बीर सिंहः वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई नुकसान न हुआ हो और पैसे दिए गए हों।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि हमारे हल्के में इस कम्पनसे ान के बारे में इतनी धांधली हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। जिन लोगों का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है उनको कम्पनसे ान मिल गया है। लेकिन जिन लोगों का 100 परसैंट नुकसान हुआ है उनको बिल्कुल महरूम कर दिया गया। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे हल्के में इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और जो जिम्मेवार है उनको सजा दी जाए।

ठाकुर बीर सिंहः यह तो जो अफसरान थे उन्होंने बकायदा इसको असैस किया था। उनकी असैसमैंट के मुताबिक ही तकावी और लोन बांटे गए है। ऐसा उदाहरण आज तक कभी एम0एल0ए0 साहब ने भी नहीं किया कि ऐसा हुआ है। अगर अब देंगे तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्षः अगर आपके नोटिस में कोई स्पैसिफिक केस आया है तो आप उसके बारे में सरकार को लिखें क्योंकि इस तरह से जैनरेलाइज करना ठीक नहीं है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः अध्यक्ष महोदय औन दी फ्लोर आफ दी हाउस चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि सारे हरियाणा में जहां भी इस तरह से नुकसान हुआ है 100 रूपया फी एकड़ के हिसाब से कम्पनसे ान दिया जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस ऐलान के बाद 300 रूपया फी एकड़ के हिसाब से कम्पनसे ान क्यों दिया गया?

ठाकुर बीर सिंहः जैसा मैंने अभी बताया जहां नुकसान हेल स्ट्रोर्म और फलड दोनों से हुआ वहां 300 रूपए फी एकड़ के हिसाब से कम्पनसे ान दिया गया और जहां नुक्सान एक ही चीज से हुआ वहां सौ रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से कम्पनसे ान दिया गया।

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, ओलावृश्टि से जहो फसलों को नुकसान होता है वहां किसानों के मवे ाी भी

मरते है। में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा प्रबंध किया जाएगा जिससे जिल किसानों के मवे ाी मरे है उनको भी कम्पनसे ान मिल सके?

ठाकुर बीर सिंहः अभी तक तो ऐसी कोई प्रोपोजल नहीं है लेकिन क्योंकि यह बात आज बताई गई है इसलिए इस पर गौर कर लिया जाएगा।

चौधरी गंगा रामः अध्यक्ष महोदय, पिछले साल ओलावृश्टि और बहुत जबरदस्त बाढ़ आने के कारण तहसील गोहाना, रोहतक और झज्जर बर्बाद हो गए थे। उस समय सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा लेकिन इस साल पिछला जो आबियाना था वाह भी और इस साल का आबियाना भी किसानों से गांगा जा रहा हैं इस साल भी किसान चूंकि फ्लड सक बर्बाद हो गए है इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस आबियाने को माफ किया जाएगा या सस्पैंड किया जाएगा?

ठाकुर बीर सिंहः जो पिछले साल नुकसान हुआ था उसकेस लिए ऐक ान पहले ही लिया जा चुका है और आबियाना वगैरह माफ किया जा चुका है। जहां तक इस साल का संबंध है, असैसमैंट करवा कर रिपोर्टस तैयार करवाई जा रही है। जो रूल्ज के मुताबिक रिलीफ दिया जा सकता है वह जरूर दिया जाएगा।

चौधरी संत कंवरः अध्यक्ष महोदय, तकावी जो दी गई थी उसको तो रिकवरी हो गई। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां ओलावृश्टि के कारण किसानों को नुकसान हुआ हैं वहां किसानों की मदद के लिए कोई ग्रांट दी गई है?

ठाकुर बीर सिंहः कुछ सबसिडी भी दी गई है। तकावी फर्टिलाइजर आदि की भाक्ल में दी गई। सबसिडी सब जगह दी गई चाहें वहां तबाही ओलावृश्टि की वजह से थी या फ्लड से थी।

श्री जयनारायण वर्माः माननीय अध्यक्ष जी, ओलावृश्टि, बाढ़ और अन्य दूसरे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण जमीदारों को और दूसरे लोगों को आबियाना की माफी सहायता के रूप में दी जाती है। यह बात तो ठीक है लेकिन गांव के अन्दर कुछ लोग ऐसे है जिनके पास जमीन नहीं है और वे गांव के किसानों के सहारे रहते है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग है, खेतीहर मजदूर है, उनको भी मदद देने की कोई बात सरकार के विचाराधीन है?

ठाकुर बीर सिंहः यह तो नुकसान फसलों और मकानों का हुआ है उसके बारे में सरकार ने निर्णय लिया है। जिनके पास जमीन ही नहीं है उनको कम्पनसे ान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हां जहां मकानों को नुकसान हो गया था उनको भी कम्पनसै ान दिया गया है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग खेती करते है और उनका उसमें पांचवा हिस्सा है क्या उनको उस पांचवें हिस्से के नुकसान का कम्पनसे ान दिया गया है? मेरे कहने का मतलब यह है कि फर्ज किया कोई पांचवें हिस्से मैं सीरी है उसको एक सौ रूपय कम्पनसे ान का मिल गया है या नहीं? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हरिजनों को भी उनका हिस्सा मिल गया है या नहीं?

ठाकुर बीर सिंहः मैंने पहले ही बता दिया है कि भोयर्ज को भी ओर टैनेन्टस को भी उनका प्रोपर भोयर दिया गया है।

श्री अध्यक्षः मैं सभी आनरेबल मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट करूंगा कि केवल मेन क्वै ाचन से संबंधित सप्लीमैंटरीज ही पूछे जाएं। जो सप्लीमैंटरीज मेन क्वै चन से संबंधित न हो उनको कृपया न पूछा जाए।

Area Affected by Floods During 1977-78

***592. Lala Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total area which was affected by the floods during the financial year 1977-78 together with the manner in which the total amount was spent by Govt. thereon?

राजस्व मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): 24 लाख एकड़ बाढ़ग्रस्त लोगों को राहत देने हेतु रा ि ा निम्नलिखित ढ़ंग से खर्च की गईः—

50 लाख रूपए के मूल्य की दवाइयां बांटी गई। पेयजल साफ करने हेतु बिलीचिंग पाउडर तथा हेलोगन गोलियां जिनका मूल्य 9.14 लाख रूपये था, बांटी गई। प ाुओं के ईलाज करने हेतु 50 लाख रूपये के टीके सप्लाई किए गए। रूपए 4.97 लाख हैण्ड पम्प लगाने, बोर होल लैटरिनज बनाने और पेय जल का प्रबन्ध करने पर खर्च किए गए। रूपए 9 लाख पानी निकासी पम्प खरीदने पर खर्च किए गए। रूनए 2.54 करोड़ सड़कों की मुरम्मत, मजबूत करना, ऊंचा करना तथा उन्हें लम्बा करने पर खर्च किए गए। रूपए 10.30 करोड़ ड्रेनेज तथा प्रोटेक ान कार्यों पर खर्च किए गए।

खाद तकावी (रूपए 1 करोड़), बीज तकावी (रू0 55 लाख), चारा तकावी (रू0 50 लाख) तथा बिजाई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने हेतु (रू0 30 लाख) स्वीकृत किए गए।

चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी स्टेट को जो रिलीफ दिया है उसकी तफसील दी है। रिलीफ तकरीबन 16 करोड़ 58 लाख रूपए का बनता है.....

श्री अध्यक्षः क्या आपने इतनी जल्दी हिसाब लगा लिया?

चौधरी खुरसीद अहमदः हिसाब लगा कर बैठा था। अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी रकम जब एक साल में फ्लड रिलीफ देने के लिए खर्च की जाती है तो मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं क्या इरीगे ान डिपार्टमै।अ के लिए ज्यादा पैसा लेकर फ्लड वर्कस को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा ताकि हर साल फ्लड रिलीफ फंड में इतना पैसा ने देना पड़े?

Mr. Speaker: A good question.

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, वैसे तो यह प्र न मेन सवाल से संबंधित नहीं है लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इरीगे ान मिनिस्टर साहब पहले ही बता चुके है कि 6 महीने के अन्दर सारा सिस्टम कंट्रोल कर लिया जाएगा और बाढ़ आएगी ही नहीं। इसके अलावा मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस 12 करोड़ रूपए के अलावा 215 करोड़ रूपए का प्रोजैक्ट इस साल के लिए और है जिसके तहत हरियाणा में फ्लड कंट्रोल के सारे काम कर लिए जाएंगे।

Construction of Bus Stand and Workshop at Hodel

***597. Chaudhri Gaya Lal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus Stand and workshop at Hodel; and

(b) If so, the time by which the afore-said proposal is likely to be materialized\

मुख्य संसदीय सचिव(श्री सुरेंद्र सिंह औजला):

(ए) हां।

(बी) इस के लिए कोई अवधि नि चत नहीं की गई है। भूमि का चयन कर लिया गया है तथा इस को अधिग्रहण किया जा रहा है।

चौधरी गया लालः अध्यक्ष महोदय, होडल कस्बा हरियाण की आखिरी सीमा पर है जैसे इधर कालका है। होडल की आबादी करीब 20–25 हजार के करीब है। लेकिन वहां पर बस अड्डा इतना भी नहीं कि पांच आदमी धूप मैं या बारि ा में भौड के नीचे बैठ सके। न ही वहां कोई वर्क ााप है। वहां तकरीबन 20–25 बसें रूकती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां कोई वर्क मिस्त्री भी नहीं है। इसलिए मैं चीफ पार्लियामैंटरी सकैट्री साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उचित नहीं समझते कि जब कालका में बस अड्डा और वर्क ााप है तो होडल में यह फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए जहां इतनी बस रूकती है?

श्री अध्यक्षः वे पहले ही स्वीकार कर चुके है कि बनाएंगे।

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः इस बस अड्डे के लिए पांच एकड़ और छ मरले जमीन एकवायर करने के लिए दफा चार के नोटिस जारी कर दिये गये है और जैसा गया लाल जी ने कहा सरकार वहां पर बस अड्डा बहुत पहले से बनाना चाहती है लेकिन इस बारे मैं टाईम निि चत नहीं है। यह मैं नहीं कह सकता हूं कि कब तक बस अड्डा बन जायेगा लेकिन बनाने का विचार जरूर है।

श्री मूलचंद जैनः जैसा कि अभी यहां पर कहा गया कि बस अड्डा सरकार बनाना चाहती है तो बस अड्डा बनने में वहां पर बीस दुकानें भी बन जाती है और एक दुकान से पांच हजार रूपये साल की आमदनी होती है। अगर सरकार वहां पर बस अड्डा बना दे तो तीन साल के अन्दर ही बिल्डिंग की कीमत वसूल हो सकती है। सरकार बस अड्डा बना देती है तो यात्रियों को ठहरने के लिए ठीक प्रकार की सुविधा मिल जाये। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पलवल के अन्दर बस अड्उा बनाने का कब तक विचार है?

(कोई उतर नहीं दिया गया)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि नारायणगढ़ तहसील अम्बाला जिले की सबसे पुरानी तहसील है। वहां पर हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की

बसें खड़ी होती है। वहां पर जमीन एकवायर की जा चुकी है इसलिए वहां पर बस अड्डा कब तक बना दिया जायेगा?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः इसके लिए सैपरेट नोटिस दें तो जवाब दे दिया जायेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिला जींद जब से हरियाणा बना है तभी से बना हुआ है, वहां पर अभी तक बस अड्डा नहीं बना है। कई तहसील हैडक्वार्टर्ज पर बस अड्डे बन चुके है और जो जिले साल भर पहले बनने थे वहां पर भी बस स्टैंड बनाये जा चुके है। क्या कारण है कि जिला जींद में अभी तक बस स्टैंड की बिल्डिंग नहीं बनी है?

Mr. Speaker: It is a separate question. But the Chief Parliamentary Secretary may answer it if he likes.

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः स्पीकर साहब, मैंने भी वही कहना था जो आपने कहा है कि यह सैपरेट क्वै ाचन है। इसके लिए नोटिस दें।

श्रीमती भाकुंतला भागवाड़ियाः स्पीकर साहब नारनौल के अन्दर बस अड्डा अभी तक नहीं बना है और महेंद्रगढ़ जिले के जितने भी कार्यालय है वे सभी नारनौल मैं है। नारनौल बस अड्डे पर अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ है। इसलिए मैं

मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि क्या वहां पर काम भुरू करने का सरकार का विचार हैं?

श्री सुरेंद्र सिंह औजलाः यह सैपरेट क्वै ाचन है।

श्री लहरी सिंह मेहराः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या रादौर में भी कोई बस अड्डा बनाने की सरकार की योजना है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, ये आपके सभी लाउड–स्पीकर खराब है। इनको ठीक करवाया जाये (विघ्न)। स्पीकर साहब, में आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो लाउड–स्पीकर के बारे में कहना चाहता हूं कि ये खराब है। (हंसी)

श्री अध्यक्षः एम्पलीफायर सिस्टम ठीक काम कर रहा है। जो साहिबान थोड़ा दूर से बोलते है उनकी आवाज ठीक आती है लेकिन जो नजदीक से बोलते है उनकी आवाज ठीक नहीं आती है अगर आप साहिबान ठीक फासले से बोलेंगे तो एम्पलीफायर सिस्टम ठीक काम करेगा।

श्री दीप चंद भाटियाः यह आपका भी खराब है। आपकी आवाज भी ठीक नहीं आती है।

श्री अध्यक्षः ठीक करवा देते है।

SETTING UP OF NEW INDUSTRIES AT SIRSA

***614. Chaudhri Jagdish Kumar Beniwal:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any new Industries at Sirsa, if so, the time by which the same are likely to be set up?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): जी नहीं, भोश प्र न उत्पन्न ही नहीं होता।

चौधरी जगदी ा कुमार बैनीवाल: स्पीकर साहब, सिरसे का क्षेत्र उद्योग में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री महोदय उसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोशित करने पर विचार करेंगे?

डा0 मंगल सैन: माननीय सदस्य ने अपने मूल प्र न में यह पूछा है कि सिरसे में सरकार कोई नया उद्योग लगाने जा रही है, मैंने कहा है कि 'जी नहीं' और फिर उसी का दूसरा हिस्सा है कि वे कब तक लगाये जायेंगे? जब पहले पार्ट में ही 'नही' कहा है तो दूसरा प्र न पैदा नहीं होता है लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सिरसा जिले को पिछड़ा हुआ जिला जरूर घोशित करना चाहते है। हमने भारत सरकार से कार्यवाही भाुरू कर रखी है।

चौधरी गुलजार सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सिरसे जिले के बारे में बताया है कि उसको पिछड़ा हुआ घोशित करना चाहते है लेकिन जींद जिला जो उद्योग के क्षेत्र में बहुत

पिछड़ा हुआ है। वहों पर कोई कारखाना नहीं है और खास कर जिला जींद में जनता सरकार बनने के बाद तो लक्षमण रेखा खींच दी गई है। वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए मैं उद्योग मंत्री महादेय से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर भी उद्योग लगाने के बारे में सोचेंगे?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे मोहतरिम दोस्त ने जिले जींद के बारे में जो बात फरमायी है उस बारे में मेरी मजबूरी है। माननीय सदस्य ने सिरसे जिले के बारे में जो पूछा है उसका मैंने उत्तर दे दिया है। मेरा हाफजा भी इतना तेज नहीं है कि मैं सारे सैक्रेटेरियट की फाइलें यहां उठा कर लाता। अगर वे अलग से सवाल करेंगे तो जरूर जवाब दूंगा। जहां तक लक्षमण रेखा खींचने की बात है उद्योग विभाग ने तो कोई लक्षमण रेखा नहीं खींची है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा कि सिरसे में कोई उद्योग नहीं लगाने जा रहे है और एक तरफ कह रहे है कि सैंटर का लिख रहे हैं कि बैकवर्ड डिक्लेयर करना चाहते है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि वहां पर उद्योग नहीं लगाये जा रहे है?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का आनसर दिया जा चुका है। वे मानते है कि बैकवर्ड है। सैंटर को लिखा जा चुका है।

सरदार सुखदेव सिंहः मैंने यह अर्ज किया है कि वह बैकवर्ड है लेकिन उसमें उद्योग क्यों नहीं लगाये जा रहे है?

डा0 मंगल सैनः मैं माननीय सदस्य का भ्रम दूर कर दूं। अद्योग स्वये सरकार नहीं लगाया करती है। बहुत कम क्षेत्रों में सरकार उद्योग लगाया करती है। पहले जो उद्योग लगाये गये है उन पह पहले ही कितने नोट फूंकें जा चुके है यह सब जानते है। उद्योगपति उद्योग लगाते है, हम तो उन्हें प्रोत्साहित करते है। हमने छोटे उद्योगों को लगाने में सिरसे जिले में लोगों को प्रोत्साहन दिया है और वहां पर 18 छोटे उद्योग इसी साल लगाये गये है।

चौधरी राम कि ानः स्पीकर साहब, जिला जींद को सरकार ने बैकवर्ड घोशित किया हुआ है और मेरा सफीदों का एरिया भी बैकवर्ड है लेकिन उसको बैकवर्ड एरिया करार नहीं दे रखा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था और लिख कर भी दिया है कि इस एरिया को बैकवर्ड एरिया करार दिया जाये। वहां पर इंडस्ट्री लगाने में सहानुभूति रखी जाए। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर उद्योग लगाने में सहानुभूति से गौर करेंगे?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, सहानुभूति से काम नहीं चलेगा, केवल हमदर्दी से बात नहीं बनती है। इंडस्ट्री लगाने

में तो हाथ काले करने पड़ते है, काम करना पड़ता हे, ऐन्टरप्राइज की कैपेसिटी चाहिए। (व्यवधान)

स्पीकर साहब, मैं बोल रहा था और मेरे दोस्त बीच में ही खड़े हो गये। मैं तो सफीदों के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे आदरणीय दोस्त श्री राम कि ान जी ने मेरे से एक अलग से सवाल पूछ रखा है और वह सवाल आने वाला है, उस वक्त सारी बात का जवाब मैं दे दूंगा।

कामरेड भांकर लालः मैं मंत्री महोदय से स्पीकर साहब आपकी मार्फत यह पूछना चाहता हूं कि सिरसा जिले के अन्दर जो 18 उद्योग लगाये गये है, वह कौन–कौन से है और कहां–कहां पर लगाये गये है? (व्यवधान) 18 करोड़ रूपये के जो उद्योग लगाये गये है, उनके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः 18 करोड़ के तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने यह कहा है कि 18 छोटे उद्योग लगाये है।

कामरेड भांकर लालः मैं तो ठीक कह रहा था लेकिन इन्होंने, विघ्न करने वालों ने मुझे गलत गाईड किया है।

डा0 मंगल सैनः इनका कसूर नहीं है। मैं और कामरेड भांकर लाल दोनों ही करोड़पति है, दोनों करोड़पति ही बनेंगे। (हंसी)

श्री बलदेव तायलः मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सिरसा जिला मैं किस आधार पर बैकवर्ड डिक्लेयर करने की कार्यवाही की जा रही है? क्या यह सत्य नहीं है कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट की पर–कैपिटा इन्कम हरियाणा मैं सबसे अधिक है?

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे से जो ओरीजनल क्वै चन पूछा गया था, वह मैंने आप के हाउस से निवेदन कर दिया कि कोई नई इंडस्ट्री सिरसा जिले में नहीं लगा रहे है, फिर मेरे एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि क्या आप सिरसा जिला को बैकवर्ड डिक्लेयर करने जा रहे है तो मैंने कहा हां जी करने जा रहे है। अब यह जानना चाहते है कि इस बात का क्या आधार है कि सिरसा जिला को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जा रहा है जबकि उसकी पर–कैपिटा इन्कम सबसे ज्यादा है, इसके लिये सैपरेट नोटिस दे दें, जवाब दे दिया जायेगा क्योंकि इसमें आंकड़ें आते है।

श्री बलदेव सिंह तायलः स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि जब एक मंत्री महोदय एक बात बताते है तो उसके आधार पर ही दूसरा क्वै चन होगा। या तो वे बैकवर्ड करने वाली बात भी नहीं बताते और कह देते है कि इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिऐं लेकिन जब उन्होंने यह कह दिया है कि इसको बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए मूव

किया हुआ है तो मैं आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मंत्री महोदय से यह कहें कि वे इसका जवाब दें।

Mr. Speaker: The Minister has replied that the Centre has been approached to declare it backward. सैंटर से निवेदन किया गया है कि उसे बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये। अगर आप आंकड़ें जानना चाहते है तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए सैप्रेट नोटिस चाहिये क्योंकि यह अलग सवाल बनता है कमपैरिटिवली हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पर–कैपिटर इन्कम के लिहाज से कोई डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है या नहीं है मेरे ख्याल में यह सैप्रेट क्वै चन है, जिसका अगर आप नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज में जितना स्टाफ होता है, वह सारा नॉन–टैक्नीकल स्टाफ होता है, मैं मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वे उसे इंडस्ट्री में कैसे लगायेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

LOANS FACILITY TO M.L.As. FOR PURCHASE OF CARS

***624. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the government to extend loan facilityes to

the Members of the Legislative Assembly also for the purchase of cars at par with Government Officers in the State; and

(b) if so, the details thereof?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क))

) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख))

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जो कर्जे देने का प्रबंध किया जा रहा है, उसमें आदमी की इन्कम भी देखी जायेगी या जो कोई भी एप्लाई करेगा, उसे दे दिया जायेगा?

चौधरी देवी लालः मैंने पहले भी कहा है कि अभी सारा मामला जेरेगौर है। लेकिन कर्जा देने की सरकारी कर्मचारियों को जो प्रथा है कि परमानैंट कर्मचारियों को जो कर्जा दिया जाता है वह 100 कि तों मैं वापिस लिया जाता है इसी प्रकार से जो टैम्पोरेरी कर्मचारी हैं, उनके लिये अलग से है। तो हम लोग अभी टैम्पोरेरी है, उस हिसाब से देखा जायेगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितने दिन तक यह मामला अभी और विचाराधीन रहेगा?

चौधरी देवीलालः इसका जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया जायेगा और कारें पहुंचाने की कोि ा ा की जायेगी।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः मैं अपने आनरेबल चीु मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जैसे कि छोटे कर्मचारियों को तहसील लैवल पर जीप और पैट्रोल मिलता है टूर वगैरा पर जाने के लिये, इस बात पर विचार करेंगे कि एम0एल0ए0 की पोजि ान बहुत ऊंची पोजि ान है, उनको भी अपने हल्के में टूर वगैरा पर जाने के लिये कुद पैट्रोल कारों के साथ–साथ दिया जायेगा?

चौधरी देवीलालः यह सवाल ऐसा किया है, जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता।

चौधरी गुलजार सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जैसे कि वर्मा साहब ने अपनी स्टेट के एम0एल0एज0 के लिये कारों के कर्जे के लिये पूछा है, कि एम0पीज0 जो हरियाणा के है, उनको भी इसमैं भाामिल किया जायेगा?

(कोई उतर नहीं दिया गया)

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब एम0एल0ए0 बनते है तब तो कहते है कि हम तो सेवक है जनता जनार्दन के, यहा आकर एम0एल0ए0 कारें मांगते है और नोट मांगते है।

इसलिए मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात को देख लें कि हमने आगे भी वोट मांगने है।

चौधरी देवी लालः इस किस्म की सुविधा एम0एल0ए0 साहिबान के लिये अपनी ड्यूटी को सरअन्जाम देने के लिये लाजमी है और कारों को होना जरूरी है और जिस तरह से सरकारी अफसरों को 100 कि तों मैं लोन वापिस देना पड़ता है, भाायद एम0एल0ए0 साहिबान से कुछ कम कि तों में वसूल किया जाये।

श्री भले रामः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एम0एल0ए0 को लोन लेने के लिए किसी आदमी की जमानत देनी होगी या नहीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी लाल सिंहः मैं मुख्य मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि यह तो आपने बड़ी मेहरबानी कर दी कि एम0एल0ए0 को कर्जा लेने के लिये सरकारी कर्मचारी के साथ जोड़ दिया है ताकि वह कर्जा लेकर अपना गुजारा कर सकै लेकिन इस विशयों में मैं एक बात पूछना चाहता हूं (व्यवधान) मैं यह बात साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी तो 32 साल तक नौकरी करता है 58 साल की उम्र में जाकर रिटायर हो जाता है और रिटायर होने पर उसकी नौकरी के मुताबिक उसके पास पैसा होता है, अगर कोई एम0एल0ए0 कर्जा वगैरा ले

ले और बाद में उसे न दे सके तो बाद मे उसे गिरफ्तार तो नहीं करेंगे?

(हंसी कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Mr. Speaker: The question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

***628. Shri Tek Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total expenditure incurred on the construction on Siwani, Jui and Loharu Canals, separately; and

(b) the amount of annual expenditure incurred on and income accrued from the afroesaid canals so far?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh):

(a) The total expenditure incurred upto 30-6-78 on these canals is as under:-

Sr. No.		Rs. in Lakhs
(i)	Siwani Lift Canal System	2131.56
(ii)	Jui Canal including increasing capacity and construction of additional	567.42

(iii)	Loharu Lift Canal System	1974.97

(b) The year wise expenditure incurred on maintenance and icome accured from these canals is as under:-

Schemes	**Annual Expenditure incurred on maintenance**	**in Rs.**	**Income accured in Rs.**
(i) Siwani Lift Canal System	1972-73	Nil	1666
	1973-74	Nil	44634
	1974-75	382250	286553
	1975-76	1011664	190089
	1976-77	3176000	316724
	1977-78	5106514	364464
	Total:	**9676428**	**1204130**
(ii) Jui Canal including increasing capacity and construction of additional minors.	1969-70	230218	Nil
	1970-71	851093	Nil
	1971-72	1653180	76791
	1972-73	1112175	158579
	1973-74	1868807	295118

	1974-75 1975-76 1976-77 1977-78	1940914 3255939 2643196 3399268	325242 339519 342557 339178
	Total:	**16954790**	**1876984**
(iii) Loharu Lift Canal System	1975-76 1976-77 1978-79	1685000 6551000 6783000	530000 430000 399000
	Total:	**15019000**	**1359000**

SUPPLY OF SUGARCANE TO CO-OPERATIVE SUGAR MILL KARNAL

***567. Kanwar Ram Pal Singh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the cooperative Sugar Mill, Karnal, had taken the whole of the bonded sugar-cane from the cane growers;

(b) whether there is any penalty-clause in the bond under which some penalty is imposed for not supplying the bonded sugarcane to the Mill; and

(c) if so, whether the Government is ready to include such a penalty clause for the Sugar Mills, which do

not take full supply of cane as agreed upon, from the growers; if not, the reasons thereof?

कृशि मंत्री (ब्रिगेडियर रण सिंह):

(ए) नहीं

(बी) हां

(सी) चीनी मिल तथा गन्ना उत्पादक के मध्य हुए इकरारनामे के फार्म के अनुसार यदिर मिल जान बूझ कर गन्ना नहीं लेती है तो उसे गन्ना उत्पादक को ऐसे गन्ने की मात्रा के मूल्य का कम से कम 50 प्रति ात मूल्य देना होगा और यदि गन्ना उत्पादक अनुबंधित गन्ने मात्रा का कम से कम 85 प्रति ात भाग जानबूझ कर गन्ना मिल को सप्लाई नहीं करता तो उसे चीनी मिल को कम सप्लाई किये गये गन्ने के मूल्य का 20 प्रति ात बतौर मुआवजा देना होगा।

SERVICE CONDITIONS OF H.C.S. (JUDICIAL) AND (EXECUTIVE)

***571. Shri Mool Chand Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the discrimination between the Executive and Judicial branches of H.C.S. Officers has been removed in the matter of-

(i) Pay-scales;

(ii) Selection grade;

(iii) Building for dwelling; and

(b) the percentage of H.C.S. Executive & Judicial Officer who are entitled for selection grade separately and whether it is the same in both cafres; if not, why this discrimination despite assurance given in the House in the Budget Session?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) तथा (ख) एच0सी0एस0 (कार्यकारी भााखा) तथा एच0सी0एस0 (न्यायिक भााखा) के वेतनमान समान है। सदन में दिए गए आ वासन की पूर्ति हेतु ऐसा किया गया है। रिहाय ाी मकानों की अलाटमैंट के बारे में भी दोनों सेवाओं के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जहां तक सिलैक ान ग्रेड पदों का संबंध है, यह एच0सी0एस0 (कार्यकारी भााखा) के लिए काडर संख्या का 20 प्रति ात है तथा एच0सी0एस0 (न्यायिक भााखा) के लिए काडर संख्या का 15 प्रति ात है। एच0सी0एस0 (न्यायिक भााखा) के बारे मैं सिलैक ान ग्रेड पदों की संख्या बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

UN-EMPLOYED EDUCATED AND PHYSICALLY HANDICAPPED EDUCATED IN THE STATE

***594. Rao Dalip Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the district-wise total number of un-employed Non-Matriculates Matriculates, B.As., M.A.s, J.B.Ts., and

B.Eds., separately in the State during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 to date:

(b) the total number of physically handicapped un-employed out of those referred to in part (a) above; and

(c) whether there is any proposal to give un-employment allowance to the unemployed and specially to the handicapped un-employed?

Educatiom Minister: (Shri Hira Nand Arya).

(a) & (b) Statement is laid one the table of the house.

(c) No please.

STATEMENT

(a) (i) The District-wise total number of un-employed non-matriculates at the end of December, each year is given below:-

Name of the District	Category of Educated applicants	1975	1976	1977
1	2	3	4	5
Ambala	Non-Matriculates	16739	21849	25066
Kurukshetra	-do-	3313	5352	8013
Karnal	-do-	11482	11218	11619

Rohtak	-do-	7938	8575	13365
Sonepat	-do-	4757	7604	8380
Jind	Non-Matriculates	4127	4246	6306
Bhiwani	-do-	6249	5756	7758
Gurgaon	-do-	15220	19684	24213
Mohindergarh	-do-	5948	1164	9504
Hissar	-do-	5508	10309	11639
Sirsa	-do-	1896	2694	3227
		82,837	**1,04,451**	**1,29,090**

Note:- (a) The statistic relating to above category are collected only on annual basis according to calendar year, and not financial year.

(ii) These include all registrants non-matriculates of various occupations.

(a)(ii) The district-wise total number of un-employed Matriculates, B.As., M.As., J.B.Ts., and B.Eds., separately in the state on the live Register of the Employment Exchange at the endo of each year is given below:-

Name of the	Category of educate	1975(on 30th	1976(on 30th	1977(on 30th	1978(on 30th

District	d applicants	June)	June)	June)	June)
1	2	3	4	5	6
Ambala	Matric& above but below graduates	18998	22672	22414	23801
Kurukshetra	-do-	6458	6072	6115	6987
Karnal	-do-	10515	12518	15049	17111
Rohtak	-do-	13414	14565	11643	13789
Sonepat	-do-	7110	7167	8764	8981
Jind	-do-	6205	5523	5323	5857
Bhiwani	-do-	7349	6215	5569	5733
Gurgaon	-do-	12868	13125	13338	15946
Mohindergarh	-do-	6954	6852	6549	8246
Hissar	-do-	11274	11016	11168	11649
Sirsa	-do-	-	2461	1871	2236

	Total:	**1,01,205**	**1,08,186**	**1,08,327**	**1,20,336**
Ambala	B.As.	4289	4466	4641	5301
Kurukshetra	-do-	1420	1920	1942	2403
Karnal	-do-	1742	2596	2780	3699
Rohtak	-do-	3255	4171	3947	3745
Sonepat	-do-	1106	1416	1657	2043
Jind	-do-	1316	1790	1576	1401
Bhiwani	-do-	1218	1384	1445	1681
Gurgaon	-do-	2651	3333	3251	3954
Mohindergarh	-do-	1382	1689	1718	2174
Hissar	-do-	2384	2442	2212	2539
Sirsa	-do-	-	690	726	788
	Total:	**20,763**	**25,897**	**25895**	**29,728**
Ambala	M.As.	383	478	509	625
Kurukshetra	-do-	276	308	307	337
Karnal	-do-	198	411	362	504

Rohtak	-do-	394	516	586	601
Sonepat	-do-	121	117	101	146
Jind	-do-	177	277	182	187
Bhiwani	-do-	101	105	96	127
Gurgaon	-do-	346	314	324	408
Mohindergarh	-do-	201	196	190	224
Hissar	-do-	235	261	258	353
Sirsa	-do-	-	65	89	130
	Total:	**2432**	**3048**	**3031**	**3642**
Ambala	J.B.Ts.	926	913	980	1201
Kurukshetra	-do-	615	605	752	749
Karnal	-do-	779	729	793	782
Rohtak	-do-	1467	1552	1406	1451
Sonepat	-do-	896	885	989	1163
Jind	-do-	401	450	432	438
Bhiwani	-do-	258	293	311	482
Gurgano	-do-	1855	1069	855	969

Mohindergarh	-do-	497	470	438	391
Hissar	-do-	1263	536	737	575
Sirsa	-do-	-	280	295	417
	Total:	**8957**	**7782**	**7988**	**8618**
Ambala	B.Eds.	821	812	923	1048
Kurukshetra	-do-	425	520	663	817
Karnal	-do-	464	545	687	659
Rohtak	-do-	916	1182	1742	1478
Sonepat	-do-	404	579	775	1023
Jind	-do-	358	542	556	568
Bhiwani	-do-	390	621	550	827
Gurgaon	-do-	1004	1340	1397	1601
Mohindergarh	-do-	528	682	775	947
Hissar	-do-	678	191	820	839
Sirsa	-do-	-	228	227	308
	Total:	**5988**	**7242**	**9115**	**10115**

Note:- (1) The statistic in regard to above categories are collected on behalf of yearly basis viz-June and December and as such the latest figures have been given.

(2) These include all registrants of various occupations.

(3) Sirsa district came inot existence w.e.f. September, 1975 and figures upto June, 1975 have been included in the Hisar district.

(4) The statistic relating to the physically Handicapped persons are not collected according to their educational qualifications. However, the district-wise total number of physically Handicapped un-employed persons on the Live Registers at the end of June each year is give below:-

Name of the District	1975	1976	1977	1978
Ambala	82	110	97	126
Kurukshetra	25	53	66	66
Karnal	59	76	77	115
Rohtak	149	130	135	164
Sonepat	68	94	99	113
Jind	42	56	49	64
Bhiwani	50	41	64	86
Gurgaon	104	109	99	127

Mohindergarh	49	66	65	77
Hissar	57	69	81	99
Sirsa	-	12	5	23
Total:	**685**	**816**	**837**	**1060**

Policy Regarding Transfer of Stipendiary Teachers

***601. Shrimati Shanti Devi Rathee:** Will the Minister of Education be pleased to state-

(a) the policy of the Government in regard to transfer of stipendiary teachers in the State; and

(b) whether the teachers as referred to in para (a) above have been transferred to their respective districts?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नंद आर्या):

(क) स्टाईपेण्डिअरी अध्यापक जिस जिले में मूल रूप से नियुक्त किए गए थे उस जिले के अन्दर किसी भी स्कूल में स्थानान्तरित किए जा सकते है। ऐसे स्टाईपंउिअरी अध्यापक जिनको अपने मूल जिले से रिक्ति उपलब्न न होने के कारण, किसी अन्य जिले में नियुक्त कर दिया गया था उन को भी उन के मूल जिले में पद रिक्ति की उपलब्धि होन पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(ख) पद रिक्ति की उपलब्धि पर ऐसा किया जा चुका है।

Opening of new Tourist Centres

***604. Shri Jai Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Tourist Centres at Kalanaur, Kherimor and Kahanaur in District Rohtak

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): जी नहीं।

————————

Non-Stopping of Buses to Carry School Children

***633. Shrimati Shakuntla Bhagwaria:** Will the Chief minister be pleased to state whether it is a fact that Haryana Roadways buses do not stop to carry the School Children in Bawal Constituency, if so, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): नहीं, बावल चुनाव क्षेत्र में हरियाणा राज्य परिवहन की बसें स्कूल जाने वाले बच्चों को बस स्टाप से उठाती है।

————————————

Flood Caused by Sahibi Nadi

***654. Capt. Mange Ram:** Will the Minister Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a number of villages in Jhajjar Constituency have been affected by the recent floods caused by SAHIBI NADI; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the details of the relief provided by the Government to the people of flood affected areas, togetherwith the steps taken or porposed to be taken by the Government to check the recurrence of the flood in future from the SAHIBI NADI?

Revenue Minister(Thakur Bir Singh):

(a) Yes.

(b) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

To mitigate the sufferings of the people of the flood affected areas, the following relief has been given-

(i) 17,700 empty cement bags for protection of Abadis.

(ii) 130 Sirkis for temporary shelter.

(iii) One allumium boat for relief and rescue purposes.

(iv) Hand Pumps have been installed to provide drinking water in the villages whose abadis have been affected.

(v) Anti-malaria and other medicine have been supplied.

(vi) Vaccination and treatment of deworming done to the cattle of all affected villages.

Steps taken or proposed to be taken to check the recurrence of flood in future from Sahibi Nadi.

Ring bunds around villages Surehti, Saloda, Gijaround Munda-Kheri, Kasni, Subana and Barsa falling in the course of Sahibi Nadi have been constructed. The strengthening and raising of left bank of drain. No.8, right bank of Bhindawas link drain, left bank of outfall drain No.8 R.D.O-63 and Surah cut off bund was done to protect the villages falling on left side of outfall of drain No. 8.

After the monsoon, it is proposed to complete the left bank of outfall drain No.8 below R.D.-63. The work of repairing the ring bunds and strengthening bank of drain No.8, bhindawas link drain and outfall of drain No.8 will also be taken up after the monsoon. The work of raising pucca road from Hassanpur to village Subana is also proposed to be taken up after the monsoon to check flooding in 15 villages of Bhindawas depression.

Sub-depot of Haryana Roadways at village Pai District Kurukshetra

***573. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Chief Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to open a sub-depot of Haryana Roadways at village Pai in Kurukshetra District; if so the time by which it is likely to be opened?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल):

इस समय गांव पाई जिला कुरूक्षेत्र में हरियाणा राज्य परिवहन का उप डिपों खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

———————

LOANS/GRANTS GIVEN TO THE IMPROVEMENT TRUSTS IN THE STATE

*__584. Chaudhri Birender Singh:__ Will the Minister for Local Govt. be pleased to state the district-wise total amount of loans/grants given to the Improvement Trusts in the State, separately, after the formation of Janata Government.

Local Government Minister(Chaudhari Ram Lal Wadhawa):

A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

1.	District Ambala	Rs. 2-00 lakhs
2.	District Hissar	Rs. 1-00 lakhs
3.	District Sirsa	Rs. 2-00 lakhs
4.	District Karnal	Rs. 2-00 lakhs
5.	District Rohtak	Rs. 2-00 lakhs
6.	District Bhiwani	Rs. 1-00 lakhs

7.	District Jind	Rs. 1-00 lakhs
	Total:	**Rs. 11-00 lakhs**

District-wise statement of grants given to the Improvement Trusts after the formation of Janata Government.

1.	District Rohtak	Rs. 25,000/-
2.	District Hissar	Rs. 20,000/-
	Total:	**Rs. 45,000/-**

PERSONS ELECTROCUTED IN THE STATE

***661. Swami Agni Vesh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the district-wise number of persons electrocuted in the State during the period from 15th August, 1977 to 15th August, 1978;

(b) the amount of compendsation paid to the families affected from such accidents in village Fatehpur (Pundri); and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken to avoid such accidents in future in the State?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

Sr. No.	(a) District	Total No. of persons electrocuted (fatal accidents)	Non-fatal accidents
1.	Ambala	10	10
2.	Bhiwani	1	13
3.	Gurgaon	9	18
4.	Hissar	4	15
5.	Jind	-	5
6.	Kurukshetra	16	19
7.	Karnal	13	23
8.	Mohindergarh	4	14
9.	Rohtak	3	8
10.	Sirsa	-	3
11.	Sonepat	1	4
	Total:	**61**	**132**

(b) Nil. The matter is under consideration.

(c) (i) All new entrants to the work force (Staff deployed on electrical installations) are being trained in the

handling of tools, making joints, use of safety devices like belts, rubber glove, helmets, earthing of metallic parts etc. and educated in the hazards of ignoring the safety rules. A training institute for Line Staff has been started at karnal on 22.3.78. The Board has sanctioned another training institute also which will be set up at Hissar shortly.

(ii) Each workman is given a set of tool, preferably in a kit bag, so that he is not apt to forget Tools and Plants.

(iii) Deteriorated service lines, where there is a possibility of leaking of current, are promptly replaced.

(iv) Audiovisual aids are used to impress upon the workmen and the Supervisors the need for safety. Posters with suitable safety slogans are exhibited prominently at generating stations, Sub stations etc.

AMOUNT FOR THE CONSTRUCTION OF CHAUPALS FOR HARIJANS IN MEWAT AREA.

165. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Revenue be pleased to state the Constituency-wise amount granted for the construction of chaupals for Harijans in Mewat area during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978.

Finance Minister (Shri Preet Singh):

Grant for construction of chaupals for Harijans is not given constituency-wise. Moreover, the Mewat area has not been defined specifically. Therefore, the requisite information cannot be supplied.

PRIMARY, MIDDLE, HIGH SCHOOLS AND COLLEGES FOR GIRLS IN THE STATE.

166. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Education be pleased to state the number of Primary, Middle and High Schools and Colleges for girls opened by the Government during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978, together with the steps taken by the Government to promote the female education in the State so far?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

Primary School	2
Middle School	Nill
High School	Nill
Colleges	Nill

Steps taken to promote femal education in the State.

1. There is provision of free education for all girsl students upto 8th class in Government schools.

2. Full freeship is provided for 33% of all girl students at High/Higher Secondary stage.

3. Tuition fee for girl students studying at High/Higher Secondary stage is Rs. 6/-p.m. only whereas it is Rs. 10-p.m. in case of boys.

4. Free uniform is given to 6,660 Harijan girl students studying in Primary and Middle classes at the rate of Rs. 15/per student.

5. 378 girls students are awarded scholarships at the rate of Rs. 10/-p.m. per student under Middle School Scholarship Scheme.

6. 411 girls students are awarded scholarship at the rate of Rs. 15/-p.m. per student under High School Scholarship Scheme.

7. 165 Scheduled Caste girl students of IX, X and XI classes are awarded scholarships on merits basis at the rate of Rs. 20/-, 25/- and 30/-p.m. per student respectively.

MANDIS IN THE STATE

167. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the total number of Mandis in the State at present ; and

(b) the amount spent by the Government during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 to develop each Mandi and the income accrued to the Government therefrom separately in the State?

Agriculture Minister (Brig. Ram Singh):

(a) In Haryana State, the Mandis are being developed by the Haryana State Agricultural Marketing Board

and the colonization Department of the Government. However, the total number of Mandis in the State is as under:-

(1) Principal Market Yards 86

(2) Sub-Market Yards 71

(b)The Colonization Department has spent Rs. 58,53,799/- on the development works of 35 mandis during the period from 4.7.1977 to 30.6.1978; as shown in Annexure "A". The income accrued to Colonization Department for the said period is Rs. 1,15,54,182,42 as shown in Annexure 'B'.

ANNEXURE 'A'

Statement Showing the amount spent by the Colonization Department through the PWD, B&R and P.H. Branches on the Development works of various Mandi townships during the Period from 4.7.1977 to 30.6.1978.

Sr. No.	Name of Mandi	P.H. Expenditure	B&R Expenditure	Total
1.	Naraingarh	1,58,865/-	-	1,58,865/-
2.	Ambala City	54,543/-	56,000/-	1,10,543/-
3.	Jhajjar	1,73,050/-	5,91,000/-	7,64,050/-
4.	Gurgaon	82,516/-	30,000/-	1,12,516/-
5.	Fatehabad	1,43,862/-	11,000/-	1,54,862/-
6.	Hathin	32,335/-	-	32,335

7.	Bhiwani	3,11,298/-	1,96,000/-	5,07,298/-
8.	Rewari	63,418/-	5,82,000/-	6,45,418/-
9.	Satnali(Old Mandi)	32,932/-	-	32,932/-
10.	Ellenabad	1,17,524/-	-	1,17,524/-
11.	Sirsa	3,75,065/-	39,000/-	4,14,065/-
12.	Rania	99,942/-	-	99,942/-
13.	Kalanwali	3,38,466/-	42,000/-	3,80,466/-
14.	Dabwali	1,81,122/-	70,000	2,51,122/-
15.	Hissar	2,97,093/-	4,000/-	3,01,093/-
16.	Barwala	25,959/-	-	25,959/-
17.	Tohana	70,295/-	10,000	80,295/-
18.	Adampur	43,748/-	1,42,000/-	1,85,748/-
19.	Ratia	93,469/-	70,000/-	1,63,469/-
20.	Bhattu	59,507/-	-	59,507/-
21.	Assandh	2,26,575/-	3,50,000/-	5,76,575/-
22.	Amin	1,97,950/-	-	1,97,950/-
23.	Kaithal	63,759/-	-	63,759/-
24.	Guhla	86,675/-	-	86,675/-

25.	Pundri	1,75,782/-	58,000/-	2,33,782/-
26.	Pehowa	62,728/-	-	62,728/-
27.	Kalayat	14,037/-	-	14,037/-
28.	Narwant	1,14,284/-	-	1,14,284/-
29.	Indri	-	1,00,000/-	1,00,000/-
30.	Kosli	-(-)	1,97,000/-(-)	1,97,000/-
31.	Hansi	-	3,000/-	3,000/-
	Total:	**36,96,799/-**	**21,57,000/-**	**58,53,799/-**

ANNEXURE 'B'

Statement Showing the Income received by the Colonization Department, Haryana, from the Various Mandi Townships with effect from 4-7-1977 to 30-6-1978

Sr. No.	Name of Mandi	Income Received
1.	Fatehabad	6,72,740.92
2.	Thohana	3,06,716.25
3.	Barwala	1,52,145.24
4.	Sirsa	19,56,558.83
5.	Indri	22,126.63

6.	Taraori	67,100.00
7.	Kaithal	3,68,367.33
8.	Pehowa	8,96,485.82
9.	Narwana	95,894.13
10.	Hissar	78,859.21
11.	Adampur	169,834.54
12.	Ratia	8,00,483.96
13.	Bhattu	40,366.58
14.	Hansi	15,390.93
15.	Bhiwani	8,63,754.69
16.	Ballabgarh	2,84,055.22
17.	Bhawani Khera	12,399.41
18.	Tosham	3,400.65
19.	Safidon	5,458.64
20.	Rewari	7,59,670.16
21.	Assandh	74,813.46
22.	Kosli	1,047.42
23.	Kalayat	1,933.54
24.	Gurgaon	2,88,406.87

25.	Kanina	174.03
26.	Jhajjar	8,258.38
27.	Amin	2,100.00
28.	Babain	2,140.00
29.	Kunjapura	11,600.00
30.	Dharsul Lalan	6,150.00
31.	Beri	4,045.00
32.	Pabra	3,195.00
33.	Smalkha	33,615.00
34.	Ambala	6,25,891.81
35.	Pundri	3,75,912.09
36.	Naraingarh	2,30,449.87
37.	Gulha	8,01,612.64
38.	rania	3,62,091.49
39.	Kalanwali	4,67,256.71
40.	Dabwali	2,95,953.58
41.	Ellenabad	3,85,726.39
	Total:	**1,15,54,182.42**

GRANT OF OLD AGE PENSION

168. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Finance be pleased to state the constituenc-wise number of persons who have been granted Ole Age Pension during the period from 4th July, 1977 to 30th June, 1978 in the State?

वित मंत्री (श्री प्रीत सिंह): राज्य में जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था पैं ान स्वीकृत की जाती है उनका रिकार्ड जिलवार रखा जाता है न कि निर्वाचन क्षेत्रानुसार। यद्यपि जिल व्यक्तियों को 4 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 तक वृद्धावस्था पैं ान स्वीकृत की गई है उनका जिलेवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है–

कम संख्या	**जिले का नाम**	**इस अवधि में कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पैं ान जारी की गई**
1.	अम्बाला	419
2.	महिंद्रगढ़	113
3.	करनाल	164
4.	हिसार	202
5.	भिवानी	84
6.	जीन्द	60

7.	सिरसा	113
8.	कुरूक्षेत्र	91
9.	रोहतक	164
10.	गुड़गांव	255
11.	सोनीपत	170
	कुलः	**1835**

ध्यानाकर्शण सूचनाएं

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received notices of Call Attention Motions by Swami Aditya Vesh, M.L.A. and Shri Sumer Chand Bhatt, M.L.A. regarding the havoc caused by the recent rains and floods in Palwal, Nuh and Ballabgarh sub-divisions of Gurgaon and the fury of floods in Ghaggar, Tangri and Markanda rivers in Ambala sub-division.

The motions are admitted.

The Hon. Members may pleased read their motions.

स्वामी आदित्य वे ा (हथीन): अगस्त माह 1978 के द्वितीय सप्ताह में गुड़गांव जिला के पलवल, नुह तथा बल्लभगढ़ सब–डिविजनों में मूसलाधार वर्शा हुई जिसके कारण पलवल

सब—उिवीजन के दो सौ ग्रामों में से 160 ग्रामों की सम्पूर्ण फसल जवार, बाजरा, मक्का तथा गन्ना की नश्ट हो गई। इसी प्रकार नुह सब—डिविजन के 275 ग्रामों मेें से 150 ग्रामौं की फसल नश्ट हो गई तथा बल्लभगढ़ सब—डिवीजन के दो सौ ग्रामों में से लगभग 100 ग्रामों की फसल नश्ट हो गई। केवल फसल ही नश्ट नहीं हुई बल्कि चारे के अभाव मेें पलवल सब—डिविजन में 1000, नुह में 2,000 तथा बल्लभगढ़ में 1000 प ाुधन मृत्यु के ि ाकार हो गए तथा हजारों मकान गिर गए। इतनी बड़ी बर्बादी से लगभग हरियाणा सरकार का 6 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है। इस क्षतिपूर्ति के लिए सरकार कृशकों को उनकी फसल का मुआवजा देन, मालिया माफ करने तथा विद्यार्थियों का ि ाक्षा भ्ाुल्क माफ करने की दि ाा में कदम उठाए तथा बाढ़ का पानी जो अब भी खेतों में भरा हुआ है उसके निकास की तत्काल व्यवस्था करें ताकि रबी की फसल की बिजाई हो सके तथा खाद, बीज, पैस्टीसाईड, बिजली की दरों मैं रियायत की जाए ताकि कृशको को वर्शा की तबाही से बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने यह प्रस्ताव रखा है। इसके विशय मैं मैं कुछ और कहना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुद और कहूं।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना मो ान पढ़ दिया है अब सुमेर चंद भट्ठ अपना मो ान पढ़ेंगे।

श्री सुमेर चंद भट्ठ(नग्गल): स्पीकर साहब, मो ान की जो कापी मुझे दी गई है वह रीडेबल नहीं हैं। मैं अपनी मो ान हिंदी में पढ़ना चाहता था लेकिन दी गई यह कापी पढ़ी नहीं जा रही है इसलिए मैं अंग्रजी में पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगर आपका इरादा इंगलि ा पढ़ने का है तो कोई एतराज नहीं है।

Shri Sumer Chand Bhatt (Naggal): Under Rule 73(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Vidhan Sabha, the attention of the State Government is hereby drawn to a matter of urgent public importance in so far as there are thousands of persons living in the villages of Ambala Sub-Division who have fallen victims to the fury of floods in Ghaggar, Tangri and Markanda rivers in the recent few days and are resigned to a state of misery and uncertainty. With the majority of their 'katcha' house collapsed and most of their belonging burried under the debris as the surging waters of these rivers surrounded these villages, the plight of these people who have thus been forced to take shelters in village schools or village chaupals, which by themselves are in no better shape, can better be imagined than explained.

Needless to emphasise that there has been an extensive damage to the standing crops in a large number of these villages, besides getting virtually the whole lands in a number of such Panchayats rendered quite unfit for any cultivation whatsoever for quite sometime to come.

Apprehensive of another on-slaught as and when the rainy waters again choose to visit them, these people in a large number of villages are living in a state of panic. This obviously calls for an immediate and effective action on the part of the State Government to save them. A statement outlining what the State Government proposes to do to meet such a situation on a short term as also on a long term basis may, therefore, please be made.

Mr. Speaker: The Hon. Minister may kindly make a statement.

राजस्व मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): स्पीकर साहब, ये दोनों काल अटैं ान मो ान मुझे आज सुबह ही मिले है। अगर मेरे लायक दोस्त इस माामले में डिटेल्ड रिपोर्ट चाहते है तो मुझे इसके लिए कुछ टाईम चाहिए। वैसे मैंने वायरलैस मैसेज भिजवा दिए है। अगर मेरे दोस्त वैसे ही इंफरमे ान चाहते है तो वह मैं दे सकता हूं लेकिन डिटेल्ड इंफरमे ान देने के लिए मुझे कुछ टाईम चाहिए।

श्री अध्यक्षः आपको कितना टाईम चाहिए जिससे आप तसल्लीबख्भा इंफरमे ान क्लेक्ट करके जवाब दे सकै।

ठाकुर बीर सिंहः स्पीकर साहब, कम से कम मुझे एक सप्ताह चाहिए लेकिन आप को जितना टाईम देना है वह दे दें। मैंने स्पे ाल मैसेंजर भिजवा दिया है। दो तीन दिन का टाईम आप दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः आपको तीन दिन का टाईम दिया जाता है।

ठाकुर बीर सिंहः बहुत अच्छा जी।

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay papers on the Table of the House.

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने एक प्रिविलेज मो ान दी थी, उसके बारे मुझे आज सुबह लिखित जवाब मिला है.....

श्री अध्यक्षः आपने जो प्रिविलेज मो ान दी थी वह रिजैक्ट हो गई है। उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री भाम ोर सिंहः.....

श्री अध्यक्षः आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। उसका जवाब आपको मिल चुका है।

श्री भाम ोर सिंहः.....

Mr. Speaker: Please sit down. I am on my legs. Now papers will be laid on the Table of the House.

श्री भाम ोर सिंहः.....

.....

Mr. Speaker: I would request you to please sit down and take your seat while I am on my legs.

श्री भाम ोर सिंहः.....

..

उद्योग मंत्री(डा0 मंगल सैन): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मैं आपकी इस मामले मैं रूलिंग चाहता हूं मि अध्यक्ष महोदय के समक्ष को विशय विचाराधीन आया हो और उन्होंने सब पहलुओं पर अच्छी प्रकार विचार करके अपनी रूलिंग दे दी हो तो क्या आपकी उस रूलिंग पर पुनर्विचार किया जा सकता है?

Mr. Speaker: The privilege motion was examined by me in detail. All the rules and precedents were considered और वह प्रिविलेज मो ान रिजैक्ट हो चुकी है। उसके विशय में सदन में कोई चीज नहीं आ सकती।

श्री भाम ोर सिंहः.....

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग के बाद जो कुछ कहा गया है वह ऐक्सपंज होना चाहिए और रिकार्ड से ऐक्सपंज कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः जो कुछ इस विशय में कोई बात हुई है उसको ऐक्सपंज कर दिया जाए। (Interruptiona) Now I will request the Ministers to lay the relevant papers on the Table of the House.

Shri Shamsher Singh: Mr. Speaker.....

Mr. Speaker: Mr. Shamsher Singh, I would request you to take your seat.

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, मैं समझता हूं कि हाउस के लिए यह एक बड़ी अ ाोभनीय बात है कि प्रोसीजर के मुताबिक एक प्रिविलेज मो ान हाउस के सामने आता है और अध्यक्ष महोदय द्वारा उसके सब पहलुओं पर विचार करके, अच्छी प्रकार से गौर करने के बाद उसको रिजैक्ट कर दिया जाता है लेकिन रिजैक्ट होने के बाद भी ये बराबर दबाव डाल रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चीज प्रिविलेज कमेटी में आनी चाहिए और वहां इस पर गौर होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे है।

Mr. Speaker: I have now given my ruling and there will be no further discussion. And nothing will be recorded. (Interruptions) कोई चीज इसके बारे में रिकार्ड न की जाए (व्यवधान)

————————

मेज पर रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: I will request the Minister to lay the relevant papers on the Table of the House.

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): (1) स्पीकर साहब, मैं फरीदाबाद में बैस्टोलाईट आफ इंडिया लिमिटिय के कारखाने में हरनाम सिंह फोरमैन की मृत्यु के मामले में सूरी जांच आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं (व्यवधान)।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, आप मेरी रिक्वैस्ट तो सुन लिजिए.....

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने कैसे बोलना भाुरू कर दिया। आप इन्हें भी बिठाइए।

चौधरी रामलाल वधवाः स्पीकर साहब ने पेपर रखने का आदे ा दे दिया है.....

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने सुबह एक एडजर्नमैंट मो ान दी है (व्यवधान)

Mr. Speaker: I have asked you time and again to please sit down. The Hon. Minister may please lay the papers on the Table of the House.

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): (2) स्पीकर साहब, मैं रिवासा घटना को जांच रिपोर्ट पर हरियाण सरकार द्वारा की गई अनुपरीक्षण कार्यवाही को द ार्ाने वाला ज्ञापन तथा मार्च के अन्तिम सप्ताह और अप्रैल, 1974 के प्रथम सप्ताह के दौरान तहसील तथा जिला भिवानी के गांव रिवासा में हुई कतिपय घटनाओं को देखने के लिए श्री न्यायमूर्ति एस0 बी0 कपूर, आई0सी0एस0 (सेवा निवृत), जांच आयोग की जांच रिपोर्ट मेज पर रखता हूं।

(3) स्पीकर साहब, मैं स्कूल ि ाक्षा बोर्ड अधिनियम 1969 की धारा 16(7) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार स्कूल ि ाक्षा बोर्ड, हरियाणा को भंग करने के संबंध में रिपोर्ट मेज पर रखता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने एजुके ान बोर्ड के बारे में सदन के पटल पर जो कागज रखें है उसके बारे में हम तीन सदस्यों ने नोटिस दिया है। उसके लिए हमको बहस का टाईम मिलना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवाः जब तक सदन के पटल पर कोई चीज न रखी जाए तब तक उस पर डिस्क ान का नोटिस नहीं दिया जा सकता है। कागज रखने के बाद ही डिस्क ान का नोटिस आना चाहिए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस बारे मैं मंत्री महोदय आपकी तरफ से रूलिंग नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्षः आज जो पेपर ऑन दी टेबल आफ दी हाउस ले हुए है उनके बारे में कोई मो ान मेरे सामने नहीं आया है। अगर ऐसा कोई मो ान मेरे सामने आएगा तो उस पर मैं पूरा गौर करूंगा और मैं सदन को यह वि वास दिलाना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल निश्पक्षता से उसके ऊपर विचार करूंगा।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि हमें इस बात का पता चला कि भाायद अधिवे ान कल को समाप्त हो जाएगा। (व्यधान)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्वै चन आवर खत्म हो चुका है और उसके बाद सदन के पटल पर कागज लाने के लिए कार्यवाही भी भुरू हो चुकी है। कृपया आप अपनी रूलिंग दें कि जीरो आवर के बाद भी यह कार्यवाही चालू रहेगी?

स्वामी अग्निवे ा: स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैसे कि हमने सुना है, पढ़ा भी है कि अधिवे ान कल को खत्म होने जा रहा है, तो फिर हमें यहां पर डिसक ान का मौका कब मिलेगा? आप कृपया इस बारे में अव य रो ानी डालें।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान, कल 6 बजे भाम को मैंने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रखी थी लेकिन किसी वजह से वह मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी। आज चार बजे भाम को बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी उस मैं यह फैसला किया जाएगा कि किस तरह से हाउस चलेगा। स्वामी जी मैं आपके प्वांयट आफ व्यू को एकोमोडेट करने की पूरी कोि ा ा करूंगा। अब हाउस को बिजनैस जारी रहेगा।

Chaudhri Ram Lal Wadhawa: On a point of order.....(Interruption)

Mr. Speaker: I would request the hon. Members not to interrupt the business of the House. Let the business of House proceed.

वर्श 1978–79 के अनुपूरक अनुमान(प्रथम किस्त)

(1) राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा

Mr. Speaker: Hon. Members who wish to raise discussion on Charged items, may please do so.

(No member rose to speak)

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker: According to the previous practice and in order to save the time of the House, all the Demands for supplementary grants appearing on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon. Members can raise discussion on the demands but while speaking, they will have to indicate the Demand No. on which they want to raise discussion.

Guillotine will be applied at 18.00 hrs.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 65,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of December No. 9-Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 14,98,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 12-Labour and Employment.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 17,72,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 17-Agrculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,72,100 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 20-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,50,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st march, 1979 in respect of Demand No. 5-Loans and Advances by State Government.

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): अध्यक्ष महोदय, अभी पीछे मार्च के महीने में 687 करोड़ रूपये का बजट सदन के सामने पे ा हुआ था और अब सदन के सामने 253.67 लाख रूपये के सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस रखे गये है तो मैं समझता हूं कि इन मांगों में से अधिकतर पैसा खर्च भी कर दिया गया है और खर्च करने के प चात् सदन के सामने रखने की एक प्रकिया चालू की जा रही है, यह प्रजातंत्र को कोई तरीका नहीं है कि पहले पैसा खर्च कर दिया जाए और बाद में उसकी स्वीकृति इस हाउस मे ंली जाए।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने भू–स्वामियों को सरकारी खजाने में से 4,15,270 रूपये की रा ाी का भुगतान किया जो कि मुकदमेबाजी में उन्हें दिए गए। अगर यह सरकार मुकदमेबाजी की यह प्रकिया ही समाप्त कर दे और पहले ही किसानों से बातचीत करके समस्याओं को हल कर ले तो सरकार इन खर्चों से बच सकती है और गरीब किसानों को भी भला हो सकता है और उन्हें कोर्ट के दरवाजे न खटखटाने पड़ेंगे। यह कस जो लगभग 17 साल तक कोर्ट में चलता रहा, कई ऐसे भू–स्वामी थे जो बेचारे आज इस संसार में नहीं है, इसलिए मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह ऐसी प्रकिया को बंद करे ताकि आगे से न सरकार को और न किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। इससे सरकार को भी

फायदा होगा, सरकार के हित में होगा और भू–स्वामियों को भी इससे लाभ होगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 8 पर आता हूं। इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि पहले तो सरकार ने एक कम्पनी से समझौता किया, समझौता यह किया कि जो पेसा है वह कम्पनी देगी लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस कम्पनी को पता ही नहीं है कि वह आज है कहां पर, इसी कारण सरकार को अपनी कंटिनजैंसी में से 1.55 लाख रूपये की रा ि ा देनी पड़ रही है। हम यह जानना चाहते है कि सरकार ने किस आधार पर सन् 1968 में उस कम्पनी से समझौता किया था, उस कम्पनी की छानबीन क्यों नहीं की गई। इतनी बड़ी रा ाी जो दी जा रही है मैं समझता हूं कि यह हरियाणा के किसानों के साथ हमदर्दी और न्याय की बात नहीं हैं।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से मांग नम्बर 9 जो कि ि ाक्षा के संबंध में है मार्च में 1 करोड़ 67 लाख रूपए के लगभग महर्शि दयानंद विद्यालय रोहतक को अनुदान के रूप में दिया गया था और अभी इस रा ाी को दिए केवल तीन महीने ही हुए हैं, भाायद यह रूपया खर्च भी नहीं हुआ होगा और अब फिर 65 लाख रूपये के लगभग उस वि वविद्यालय को दे दिया गया है और यह रा ि ा देने से पहले इस सदन को वि वास में भी नहीं लिया गया है और उस वि वविद्यालय में किस प्रकार का आदमी काम कर रहा है, उसको सारा हरियाणा तो जानता ही है बल्कि

सारे दे ा को उस आदमी के बारे में पता है। इस वि वविद्यालय में आज तक एक भी सेनिट की मीटिंग नहीं बुलाई गई है और फिर भी आज उस वि वविद्यालय को 65 लाख रूपये की रा ि ा और दे दी गई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इतनी बड़ी रा ाी के प्रयोग के लिए सदन को एक कमेटी बनानी चाहिए जोकि इस का सारा हिसाब किताब देखे। इसी प्रकार रोहतक जिलें में और सिरसा में दो आई0टी0आई0 सरकार खोलने जा रही है जिस पर कोई लगभग 14,98,000 रूपये की रा ि ा खर्च आने का अनुमान है। एक सिरसा जिले में खोला जाएगा और दूसरा रोहतक जिले के गोहाना सब–डिविजन में। इन आई0टी0आई0 को खोलते समय दूसरी जगह की आव यकताओं को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया। डिप्टी स्पीकर साहब, गुड़गांव में मेवात का जो इलाका है, वह सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वहां पर पांच लाख की आबादी है और वहां पर इस प्रकार का एक भी आई0टी0आई0 नहीं है जिसका नतीजा यह है कि वहां के नौजवान लड़के लड़कियां रोहतक, अम्बाला और करनाल में इस ि ाक्षा के लिए आते है लेकिन कई गरीब घराने के बच्चे जिनकी आर्थिक द ाा बड़ी दयनीय है, इस ट्रेनिंग से वंचित रह जाते है। इसलिए सरकार को जगह की आव यकता को देखते हुए ऐसी जगहों पर इन आई0टी0आईज0 को खोलना चाहिए जहां पर कि कोई भी आई0टी0आई0 नहीं है। जिन स्थानों पर ये आई0टी0आईज0 खोले जा रहे है वे तो पहले से ही ऐजुके ान के बड़े भारी सैंटर्ज है। इसी प्रकार से वाटर सप्लाई की स्कीमज जो है वह 48 में से

32 केवल हिसार जिले के लिए ही रखी गई, भिवानी और सिरसा इन में 32 वाटर सप्लाई स्कीमज रखी गई है बाकि सभी जिलों के साथ पक्षपात किया गया है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी मामलों में सरकार ने पक्षपात से काम लिया है। यह ठीक है कि ये सारी मांगें पास हो जाएंगी लेकिन जो दूसरे लोग है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि गरीब लोगों को भलाई के लिए ने कोई मांग बजट सै ान में रखी गई थी और न ही इन अनुपूरक मांगों में ऐसा कोई प्रोवीजन किया गया है।

इसी प्रकार से मांग नं0 13 है। इसमें दो स्कीमें है एक तो बाल विकास सेवा स्कीम है जिस पर 8 लाख 86 हजार रूपये खर्च होने जा रहे है। यह स्कीम अम्बाला जिला और जींद जिलें में खोल रहे है और सोनीपत में आलरेडी खोली हुई है। समझ में नहीं आता की महेंद्रगढ़ भी जिला है, गुड़गांव भी जिला है और कुरूक्षेत्र भी जिला है और भी जिले है उन जिलों की तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहली सरकार ने भी तमाम हरियाणा के साधन एक तरफ डाइवर्ट कर दिए थे और आज की सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। चाहे बच्चों के लिए केंद्र खोलने की बात हो और चाहे उद्योग केंद्र खोलने की बात हो अगर वे इस तरह से खोलें जाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह बाकी सारे हरियाणा के साथ न्याय की बात नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरी स्कीम है वह है सामूहि बीमा की स्कीम। आज डैथ रेट बढ़ जाने के कारण एल0आई0सी0 को पैसा देने के लिए यह डिमांड

रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट के अधिकारी कहते है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने डैथ रेट 12 प्रति ात कर दिया है। अगर डैथ रेट कम हो गया है तो यह रा ि ा किस लिए दी जा रही है? जब हम लोग आवाज उठाते है कि बीमारियों से ज्यादा लोग मर रहे है तो ये कहते है कि हमने बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया है। अगर महामारी का नाम लिया जाता है तो ये कहते है यह तो नेचुरल क्लैमिटी है। तो इस बारे में भी सरकार को पोजि ान साफ करनी चाहिए।

इसी प्रकार से मांग नं0 16 है। यह ठीक है कि उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस मांग के जरिये गांवों के लोगों तथा पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है जोकि एक बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन जो पिछड़े हुए जिले है जैसे गुड़गांव जिला है वहां परइस प्रकार की कोई स्कीम नहीं दी गई है। हमारे हथीन के क्षेत्र के लोगों ने कर्जे के लिए फार्म भर कर दिए लेकिन बैंक वालों ने उन्हें यह कह कर रिजैक्ट कर दिया कि यह तो हमारी सीमा में ही नहीं आता। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए भी ऐसी सहूलियत दी जाए। जितने उत्साह के साथ स्कीमें चालू की गई थी आज उनसे नौजवानों में बहुत निरा ाा हैं क्योंकि उनको दस हजार रूपये का कर्जा लेने के लिए बहुत भाग–दौड़ करनी पड़ती है और दो तीन हजार रूपया खर्च करना पड़ता है। इसलिए इस

तरु अगर गौर किया जाए तो लोगों का बहुत फायदा हो सकता है।

इसी प्रकार मांग नं0 17 है जोकि कृशि से संबंधित है। यह दस हजार रूपए की मांग है। यह खर्चा इसलिए हुआ कि कृशि वित निगम लिमिटिड बम्बई को ऐसे वि ोशज्ञ दल भेजने के लिए कहा गया था जो हरियाणा वित्त विभाग और कृशि सहकारिता, प ाुपालन, सिंचाई और बिजली इत्यादि जैसे राज्य सरकार के अन्य संबंध विभागों के परामर्ा से 1978–83 की योजनावधि के दौरान कृशि और संबंध सैक्टरों को अधिक सांस्थानिक ऋण देने के लिए सर्वेक्षण करेगा। इसके लिए खर्चा तो सरकार मांग रही है लेकिन उसकी रिपोर्ट से संबंधित सारी बातें सदन में नहीं रखी गई है। मैं चाहता हूं कि इस खर्चे की डिमांड के साथ–साथ उसकी रिपोर्ट भी हाउस की टेबल पर आनी चाहिए थी ताकि हम यह देख सकते कि यह खर्चा जायज है या नहीं।

इसी प्रकार से मांग नं020 है। इसमैं भी 1 लाख 72 हजार एक सौ रूपये की मांग की गई है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि जितनी भी स्कीमें बनी है उनका पैसा हिसार से रोहतक तक ही खर्च होता है। यह जो पैसा है यह भी हिसार में ही खर्च होगा और कहीं नहीं होगा। इस प्रकार से सारे हरियाणा के साथ यह भेद–भाव किया जा रहा है।

इसी प्रकार से मांग नं0 25 है जोकि 1.50 करोड़ रूपये की है। यह रा ाी गन्ने के मिल मालिकों को कर्जे के रूप में दी जाएगी। मैं समझता हूं कि जहां जहां गन्ने के मिल है और उस एरिया का जितना गन्ना मिल ने बाउंड किया होगा और वह पूरा क ा नहीं हुआ होगा उनको यह कर्जा दिया जाएगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में गन्ना मिल नहीं रहा है और वहां किसानों का गन्ना तबाह हुआ है उनके लिए सरकार ने अनुपूरक मांगों में कोई बात नहीं रखी। इसलिए जो क्षेत्र गन्ना मिल के क्षेत्र से दूर है उनके साथ यह बेइंसाफी है। इसलिए उन किसानों का भी नुकसान पूरा किया जाए जिनका गन्ना मिल के क्षेत्र से दूर बोया हुआ था। मुझे मालूम है कि ये 2 करोड़ 53 लाख की डिमांडज पास तो हो जाएंगी लेकिन मैं प्रार्थना की भावना से कहता से कहना चाहता हूं कि इस रा ि ा में से काफी रा ाी तो पहले ही खर्च कर ली गई है और अब उसकी स्वीकृती ली जा रही है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक प्रकिया के अनुकूल नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(महिम): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो सप्लीमैंटरी डिमांडज के ऊपर बहस चल रही है मैं भी अपने आप को उसमें भारीक करते हुए मांग नम्बर 12 के बारे में दो भाब्द कहना चाहता हू। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे मुल्क की स्थिति ऐसी दयनीय है कि सब को एम्पलायमैंट देना गवर्नमैंट के बस की बात नहीं रही है लेकिन गवर्नमैंट बच्चों को ट्रेंड करने के लिये एक तरीका तला ा कर रही है ताकि वे ट्रेंड होने के बाद

अपनी सैल्फ एम्पलायमैंट कर सकें। उसका तरीका है कि जितने भी इंस्टियल इंस्टीच्यु ांज है वे ज्यादा से ज्यादा खोलें जाएं। आज डिमांड नम्बर 12 के अन्दर दो आई0टी0आईज0 एक सिरसा में और दूसरी गोहाना मैं खोलने के लिये कुछ रा ि ा मांगी जा रही है। मैं सरकार को इस बात के लिये मुबारिकबाद देना चाहता हूं और साथ में यह भी गुजारि ा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आई0टी0आईज0 खोली जाएं। अभी पीछे सी0एम0 साहब ने महिम के अन्दर एक आई0टी0आई0 खोलने के लिये अनाउंसमैंट की थी, मुझे मालूम नहीं कि वह केस कहां तक पहुंचा है। इसलिये सरकार से मेरी गुजारि ा है कि अगर कागजात पूरे हो गये हो तो इस सै ान के 15–20 दिन के अन्दर अन्दर उस आई0टी0आई0 को मंजूरी दी जाए। इससे जहां उस इलाके को फायदा तोता है वहां सब से बड़ी बात यह होती है कि नौजवानों को इनि ायेटिव भी मिलता है। आज के नौजवान नौकरी के पीछे भाग रहे है। आज नौजवानों को नौकरी क्यों प्यारी लगती है क्योंकि वे हाथ से काम करने से हिचकिचाते हैं। इसका कारण यहीं है कि कोई भी काम करने से पहले सोचते है कि इससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगां आज कल हर एक धंधें में इंसान की दिक्कत यही होती है कि वह खुद ट्रेंड नहीं होता, उसको अपना धंधा चलाने के लिए ट्रेंड आदमियों की जरूरत होती है। आज लेबर की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम ठीक ढ़ंग से चला नहीं सकता। अगर हर एक आदमी खुद ट्रेंड हो जाए तो वह अपना काम खुद चला सकता है

इसलिये इसका तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा आई0टी0आईज0 खोली जाएं। यह जो दो आई0टी0आईज0 खोलने के लिये पैसा मांगा गया है यह कोई ज्यादा पैसा नहीं है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस मांग को पास कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब में डिमांड नं0 16, जो इंडस्ट्रीज के बारे में है, दो भाब्द कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह ने नारा दिया था कि भारत का भविश्य गांवों में है। गांव का भविश्य उजला होगा तभी भारत का भविश्य उजला हो सकता है। गांवों को उजला करने का तरीका एक ही है और वह यह है कि गांवों में इंडस्ट्रीज सेट–अप की जाएं। अगर गांवों में इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएंगी तो गांव के लेाग इस बात को समझेंगे कि सरकार गांवों का उत्थान चाहती है और देहातों में स्माल स्केल इंउस्ट्रीज खोलने का जो इरादा सरकार का है, गांव के लोग उसकी सराहना करेंगे। गांवों में उद्यमकर्ताओं को कुछ दिक्कत पे ा आ रही है। मै। सरकार से गुजारि ा करूंगा कि जहां सरकार ने रूरल डिवैल्पमैंट के काम को हाथ मै लिया है वहां कर्जा देने की जो स्कीम है, इसमें कर्जा लेने का जो प्रोसीजर है, उस को सिम्पलीफाई किया जाए ताकि सारे रूरल एरियाज में डिवैल्पमैंट हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 25 के बारे मैं सरकार का खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस साल गन्ने की फसल बुरी तरह से पिटी। इसमें कोई भाक नहीं कि

सरकार ने मिल मालिको से गन्ने का भाव किसान को साढ़े तेरह रूपये दिलवाया और किसान के साथ बड़ी हमदर्दी दिखाई, यह बात ठीक है। जहां पर मिल का बोंडिड एरिय है वहां किसान को फायदा जरूर हुआ है और बोंडिड एरिए के बाहर के जो किसान है, उनको इतना फायदा नहीं हुआ है। सरकार ने जो काम अच्छा किया है, उसको भूलना नहीं चाहिए, मैं मानता हूं कि सरकार अच्छे काम कर रही है। अगर ये मिल गन्ने को न उठाते तो जो हालत और लोगों की हुइ, वह इनकी भी होती। डेढ़ करोड़ रूपया सरकार ने मिल मालिकों को लोन के रूप में जमींदारों का एरियर देने के लिए दिया है। कुल एरियार पौने चार करोड़ रूपये का बैठता है जिस में से डेढ़ करोड़ का इन्जाम सरकार ने किसान को बचाने के लिए किया है और मैं समझता हूं कि यह सराहनीय कदम है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं जो आपने बोलने का समय दिया।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आपने मुझे टाईम दिया। खु ाी की बात यह है कि हरियाणा के सबसे पापुलर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे है। तकरीबन–तकरीबन पांच महीने हुए हैं जबकि इस हाउस में 210 करोड़ रूपये का बजट पास किया गया था और उस वक्त मैंने यह खद ाा जाहिर किया था कि यह पैसा तुम थोड़े से इलाके में ही खर्च करोगे और सारे हरियााणा में बराबर नहीं बंटेगा। मैंने सी0 एम0 साहब से रिक्वैस्ट की थी कि

सब इलाकों में बराबर बराबर पैसा खर्च किया जाए। चौधरी बंसी लाल ने सारे का सारा पैसा अपने इलाके में बरबाद किया था। बरबाद इस सैंस में किया कि उस पैसे से फूल और फुहारे ही लगाते रहे, गरीब जनता की रोटी का प्रबंध नहीं किया। मैं अपने सी0 एम0 साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि बंसी लाल की तरह न करे। हमारे सी0 एम0 साहब ने हाउस को अ योरेंस दिलाई थी कि 20 परसैंट रूपये को छोड़ कर, क्योंकि कई बार किसी जगह कोई मिनिस्टर किसी बात का एलान कर देता है, इसलिए 20 परसैंट छोड़ कर बाकी 80 परसैंट रूपया हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में बराबर–बराबर खर्च किया जाएगा, लेकिन कल जो सै ान भाुरू हुआ, उसकी डिसक ान से साफ जाहिर होता है कि सड़कों के मामलों में, वाटर सप्लाई स्कीम्ज चालू करने के मामले में हमारे इलाके के साथ सौतेली मां जैसा सलूक हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट पास करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अगर पास ही करना है तो और कर देते है, आप और ले आओ, सरकार को और पेसा दे देते हैं, लेकिन इतना ख्याल अव य रखा जाना चाहिए कि कम से कम वह पास किया हुआ पैसा सारे हरियाणा में खर्च होना चाहिए। इसके सिवाय हमारे पास और कोई पैमाना नहीं है जिससे हरियाणा का सुधार हो सके। पैमाना यही है कि हर एक हल्के में बराबर–बराबर बांट दिया जाए। 90 हल्कों में बराबर–बराबर खर्च कर देते तो हमें कोई आपति नहीं थी पास करने में, बल्कि खु ी की बात होती, हम और पैसा पास करते।

इसके बाद डिमांड नं0 17 एग्रीकल्चर के बारे में है। एग्रीकल्चर महकमें पर करोड़ों रूपया खर्च हो रहा है। हमें खु ाी होती है कि खर्च होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कल एग्रीकल्चर की सब स्कीमें कागजों पर ही रहती है, प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा, कोई भी महकमा प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देहात से इलैक् ान लड़ कर आये है, दूसरे वजी साहिबान भी बैठे है, ये भी देहात में गये है, आपने देखा होगा, खेती बाड़ी का महकमा कहीं भी खेती के बारे में प्रचार करता हुआ दिखाई नहीं दिया, कहीं भी नजर नहीं आएगा जो यह कह रहा हो कि खेती बाड़ी किस तरह से चलानी है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस महकमें ने पहले–पहले लोगों में खाद के बारे में प्रचार किया और लोगों को मजबूर किया कि देसी खाद को छोड़ दो और सरकारी खाद इस्तेमाल करो। आज वे लोग बिना सरकारी खाद से गुजारा नहीं कर सकते, उनके अपने बच्चे पालने मु ि कल हो रहे है। जो गोबर की खाद तैयार करते थे उसको तैयार करना छोड़ दिया, अब यूरिया डालते है और यूरिया को खरीदने के लिए जगह–जगह किसान को कर्जा लेना पड़ता है। मैं सरकार से कहूंगा कि वह एग्रीक्लचर डिपार्टमैंट को जागृत करे, उन कर्मचारियों से काम ले, घर में न बैठाएं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस मांग के तहत हरियाणा में एक एक्सपर्ट टीम आई है प्लानिंग करने के लिए, जिसके लिए यह पैसा मंजूर किया गया है। हम ऐसी टीमों के लिए और भी पैसा मंजूर कर देंगे लेकिन कम

से कम खेती बाड़ी करने का ढ़ंग तो लोगों को बताये, दे ा के लिए कोई अच्छा काम करें, पैसा तो हम और भी दे देंगे। खेती बाड़ी हरियाणा का जीवन है और आज खेती बाड़ी को फ्लड ने तबाह कर दिया। पिछले बजट सै ान में श्री वीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया था कि अगले साल हरियाणा को फ्लड से बचा लिया जाएगा लेकिन हरियाणा फ्लड से बचा नहीं। यह ठीक है बरबादी कम हुई है लेकिन हुई जरूर है। कम होने का कारण एक ही है कि इस तरफ काफी पैसा खर्चै हुआ है। मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फसल मरने के और भी कारण है, केवल फ्लड ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि एक्सटैं ान आफ ड्रेनज का जो महकमा है, वह ड्रेन्ज की अलाइनमैंट ठीक नहीं करता। जो जमीन एक्वायर की जाती है वह गलत तरीके से की जाती है। मेरे इलाके में दो गांव है अहरसेला और भुटड़ी, इन में ड्रेन्ज अलाट हो चुकी है लेकिन इनकी अलाइनमैंट ठीक होनी चाहिए वरना नुकसान होगा। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो प्लानिंग करने की टीम आई है, उन के साथ चीफ इंजीनियर साहब मौका पर जाकर देखें और सही तरीके से अलाइनमैंट करें। अलाइनमैंट उस एक्सपर्ट टीम से बनवा दें, एस0 डी0 ओ0 वगैरा के बास का काम नहीं, वे असर में आ जाते है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से कहना चाहता हूं कि दो–चार एम0एल0एज0 की कमेटी बना लें और खुद जाकर चीफ इंजीनियर साहब से अलाइनमैंट करवाएं और जहां से पानी ठीक तरह से

निकल सके वहां से निकलवाने का प्रबंध करे। वरना हरियाणा आज बरबाद हो रहा है, लुट रहा है और सारी फसलें बरबाद हो रही है।

डिमांड नं0 25 में लिखा हुआ हे कि किसानों को पैसा दिलवाने के लिए सरकार भूगर मिल्ज को पैसा एडवांस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सी0एम0 साहब से गुजारि ा करूंगा कि हर एक तहसील में एक–एक भूगर मिल होनी चाहिए क्योंकि आज कोई गुड़ नहीं खाता, सब चीनी खाते है। मुझे मालूम है, चौधरी साहब ने कैथल में एक भूगर मिल्ज मंजूर करवाई है। हमारे पास गन्ने की कमी नहीं है, बहुत गन्ना पैदा होता है और गन्ना पैदा करने के सिवाये और कोई चारा नहीं लेकिन जब तक भूगर मिल नहीं होगी, तब तक वहां पर गन्ना कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए सी0एम0 साहब से रिकवैस्ट करूंगा कि कैथल में जो मिल मंजूर की है, उसको पक्का मंजूर कर दें, हम उसको चला भी अपने आप लेंगे, गन्ना भी पैदा कर लेंगे आप एक बार लगा दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

इसके बाद डिमांड नं0 12 है जिसमैं लेबर एंड एम्पलायमैंट के लिए पैसा मांगा गया हैं। गवर्नमैंट ने दो आई0टी0आई0 मंजूर किए है। अच्छी बात है, इस तरह के इंडस्ट्रियल ट्रैनिंग इंन्स्टीच्युट होने चाहिए, लेकिन मैं सी0 एम0 साहब से अर्ज करना चाहता हूं डा0 मंगल सैन जी तो उठ कर चले गये, कैथल में आई0टी0आई09 की एक बिल्डिंग बनी हुई है,

डा0 मंगल सैन जी को एक महीना पहले मैंने दिखाई थी, वे सरपराईज चैकिंग पर वहां गये थे, उसमे म ाीनरी बहुत कम है, ट्रेड थोड़े है लड़के ज्यादा है। मैंने डाक्टर मंगल सैन जी से चार ट्रेड मंजूर करवाए थे। वे ट्रेड थे ड्राफ्टसमैन, रेडियों मैकेनिक, टी0 वी0 मैकेनिक और इंगलि ा स्टैनो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को मंजूरी के बाद भी आफिसर साहिबान उनको चलने नहीं देते। बड़े गजब की बात है कि मिनिस्टर साहब तो आर्डर करे लेकिन उसको इम्पलीमैंटे ान न हो। मैं जब वजीर था तो पांच मिनट में इम्पलीमैंटे ान होती थी। (हंसी) इसलिए मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन चार ट्रेड्ज की मंजूरी उन्होंने दी है, वे भाुरू हो जाने चाहिए। पैसा हमारा है, छोरे हमारे है, सरकार ने उसकी मंजूरी दे दी है। अब भला उसमें रूकावट क्यों हो?

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आज हमारे यहां बच्चों को रोजगार देने का ढ़ंग बड़ा गलत है। उन्हें ऐड–हाक बेजि पर लगाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उन्हें बकायदा पब्लिक सर्विस कमी ान और एस0एस0एस0 बोर्ड के थ्रू लगाया जाए। इनमें भी सिलैक ान में देर नहीं लगनी चाहिए। एस0 एस0 एस0 बोर्ड में पी0 टी0 आई0 का इन्ट्रव्यू हुआ था लेकिन आज 6 महीने होने लगे है मगर रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चौधरी साहब, से रिक्वैस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही नहीं, जो अप्वायंटमैंटस हो रही हैं, वे

किसी हिसाब–किताब से नहीं हो रही है। उनमें प्र ार चल रहा है। पैसा चल रहा है और कई दूसरे कई ढ़ंग चल रहे है। इसके बारे में मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि हम आपके साथ है, थोड़ा तगड़े हो कर चलो। (विघ्न)

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई जरिया होना चाहिए। आज सरकार रोजगार देने की जगर बेरोजगारी बढ़ा रही है। पहले सिपाही की 27 साल तक भर्ती हो सकती थी लेकिन अब भर्ती होने की उमर घटा कर 21 साल कर दी गई है। 21 साल की उमर में तो हमारे छोरे दसवीं पास भी नहीं होते क्योंकि 8–10 साल तक तो वे पाली का काम करते रहते है। (विघ्न) इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि सिपाही की भर्ती के लिए वे 27 साल की ही उमर कर दें। इसके अलावा मैं यह भी रिक्वैस्ट करूंगा कि पुलिस में तो तगड़े छोरे चाहिएं। उनके लिए पढ़ाई की भी ज्यादा आव यकता नहीं है। (विघ्न) एक सिपाही के लिए तो आठवीं तक की पढ़ाई ही काफी है। (विघ्न) तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि सिपाही की भर्ती के लिए ये जो दो कंडी ांज रखी गई है इनमें सुधार लाया जाए एक तो क्वालिफिके ान दसवीं पास की जगह आठवीं पास कर दी जाए और दूसरे भर्ती की उमर 21 साल से बढ़ाकर 27 साल कर दी जाए ताकि अपने लड़के पुलिस में भर्ती हो सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अब ऐजुके ान की डिमांड की तरफ आता हूं। ऐजुके ान बड़ी जरूरी है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि गांव–गांव में कन्या पाठ ाला होगी। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन पांचवी जमात तक की पढ़ाई के लिए लड़कियों के स्कूल गांव में जल्दी से जल्दी खोल दिए जाएं। (विघ्न) इसके अतिरिक्त मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह भी कहूंगा कि चूंकि हर गांव वाले अपने गांव में मिडल और हाई स्कूल चाहते है इसलिए सब जगह मिडल और हाई स्कूल बना दो क्योंकि मास्टर हमारे पास है। इससे एक तो आपका नाम होगा, रैपुटे ान बढ़ेगी और लोग पढ़–लिख जाएंगे। (विघ्न)

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): क्या जमीन पर लगान चार रूपये बढ़ा दें?

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: लगान अलग से लगा दो, जमीन का नाम न लो। आमदनी का क्या है, आमदनी तो बहुत हो सकती है। आमदनी बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं ब ार्ते कि आप उसे मानें। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि मास्टर्ज जो है, टीचर्ज जो है वे बिल्डर्ज ओफ दी ने ान है। इनका वि ोश ख्याल रखा जाए। इनको उचित वेतन दिया जाए और यथा समय प्रमो ान दी जाए। हां, एक बात का जरूर ध्यान रखा जाए। जो मास्टर अच्छा पढ़ाते है उनका

वि ोश ध्यान रखा जाए, जिनका रिजल्ट गंदा आता है उनको बे ाक मुअतल कर दो या नौकरी से निकाल दो क्योंकि ऐसे मास्टरों की हमें जरूरत नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं स्कूलों की बिल्डिंगज के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के के जखौली गांव में स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स होने को है। उसकी दीवारें गिर रही हैं, उसके छत की कड़िया टूट चुकी है, बच्चों के मरने का खतरा है। आप चाहे उसका मौका दिखा लें। इसके बारे में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि या तो जल्दी से जल्दी उसकी मुरम्मत करवाई जाए या वहां नई बिल्डिंग बनवाई जाए। वह फ्लड अफैक्टिड इलाका है।

अंत में, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं जिसे मैं पहले भूल गया था। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि यह ऐग्रीकल्चर इं ाोरैंस स्कीम भुरू करा दे ताकि लोगो को पूरा मुआवजा मिल सके। डिप्टी स्पीकर साहब, तकावी तो माफ कर दी गई है, मालिया रैवन्यू मिनिस्टर साहब माफ करके आए है लेकिन अगर कर्जा भी माफ कर दें तो सरकार की बड़ी कृपा होगी।

चौधरी हरि चंद हुड्डा(किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, मांग 12, 16 और 17 इन्टर–रिलेटिड मांगे है। मांग नं0 12 आई0टी0आईज0, मांग नं0 16 इंडस्ट्रीज और मांग नं0 17

ऐग्रीक्लचर की है। दरअसल देखा जाए तो there are only two factors for the failure on the economic front. The wrong allocation of the money of the country between the industry and the agriculture and more stress on large scale industries are the main factors. सिर्फ ये दो ही फैक्टर्ज ऐसे है जिन्होंने हिन्दुस्तान के ऐग्रीकल्चर को हिट किया और ऐग्रीकल्चर को हिट करके इंडस्ट्रीज को ऊपर ले गए बड़ी म ीनों से। इससे दो बातें हुई। आम जनता मर गई और बीस फीसदी आदमी तर गए। यह दुनिया का असूल है, किसी भी मुल्क को आप ले लें उसका यह असूल है कि–

जिस के खेत में हरियाली उसके मुंह पर लाली

जिस दे ा किसान कंगाल उस दे ा का हाल निढ़ाल।

यह दुनियां का असूल है कि किसी कंटरी की इंडस्ट्री को ऊपर उठाने से पहले ऐग्रीकल्चर को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। जो मुल्क एग्रीकल्चर को ऊपर उठा ले जाएगा उसकी इंडस्ट्रीज और दूसरी डिवैल्पमैंट साथ ही साथ होती चली जाएगी। तो डिमांड न0 17 के बारे में मैं यह कहूंगा कि अगर हरियाणा के एग्रीकल्चर को ऊपर उठाने के लिए सारा बजट भी लगाना पड़े तो लगा लिया जाए। इससे यह होगा कि जहां ऐग्रीकल्चर ऊपर उठ जाएगा वहां साईड बाई साईड इंडस्ट्रीज भी चलती आएगी और जहां इंडस्ट्रीज चलती आएंगी वहां आई0टी0आइज0 वाला सिस्टम भी चलता जाएगा। आज

आई0टी0आइज0 वाला सिस्टम जैसा स्वामी जी ने कहा थोड़ा गलत है। आई0टी0आई0 आप चाहे कहीं भी खोल लो लेकिन इस गलत सिस्टम को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। हमारे जितने गांव हैं, जिनकी आबादी 10 और 12 हजार की है वहां आपको आई0टी0आई0 की ब्रांच देनी पड़ेगी, उनको वहां डिवैल्पमैंट करना पड़ेगा और वहां से तैयार हुए बच्चों को इंडस्ट्रीज में आपको लेना पड़ेगा। आज आप देखें इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट में नौन–टैक्निकल स्टाफ भरा पड़ा हैं यह नॉन टैक्निकल स्टाफ इंडस्ट्रीज के महकमे को कहां ले जाएगा यह मेरी समझ में नहीं आता। इंडस्ट्री के महकमें में तो सारा स्टाफ टैक्निकल होना चाहिएं टैक्निकल ऐजुके ान को बढ़ावा देने के लिए हमारे गांव–गांव में आई0टी0आइज0 खोले जाने चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एग्रीकल्चर को पहले ऊपर ले जाएं क्योंकि ऐग्रीकल्चर ऐसी चीज है जिसके बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ा है, न ही हिंदुस्तान आज तक आगे बढ़ पाया है और न ही आयंदा आगे बढ़ पाएगां तो डिमांड नं0 17 पर मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा का सारा बजट ऐग्रीकल्चर पर लगा दें तो हरियाणा हिन्दुस्तान के अन्दर इस दि ाा में पहला कदम उठा सकता है।

इंडस्ट्रीज के बारे में मेरी प्रार्थना यह है कि इंडस्ट्रीज का भी थोड़ा सा सिस्टम बदल दिया जाए। कौटेज इंडस्ट्री गांव–गांव के अन्दर हो जाए और इंडस्ट्रीज आफिसर की आप यह

जिम्मेवारी लगा दो कि हर गांव के अन्दर छोटी–मोटी इंडस्ट्री लोग अपने दिमाग से खोल दे। अगर ऐसा हो जाए तो काम अच्छा बन सकता है क्योंकि सिस्टम आज ऐसा है कि इंडस्ट्री आफिसर तो हमने बना दिए लेकिन वे जानते कुद नहीं है। गांव के लोग जब उनसे इंडस्ट्री लगाने के बारे में पूछते है तो वे कहते है कि तुम इंडस्ट्री लगा लो, हमे आप अगर कहोगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, गांव के लोगों को एक और बड़ी तकलीफ है। गांव के लोग लोन लेना चाहते है लेकिन उनके पास घर की रजिस्ट्री होती नहीं। (विघ्न) ऐसा है कि जब इंडस्ट्री लगाने के लिये पैसा लेने जाते है तो जिस घर में इंडस्ट्री लगानी हो उसकी रजिस्ट्री देनी पड़ती है। गांव में रजिस्ट्री कहां होती है? अब लोगों को बैंकों से लोन कैसे मिले? पिछला बजट तो ऐसे ही चला गया, अगला बजट भी चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सिस्टम को हमैं थोड़ा बदलना पड़ेगा।

गांवों मे इस बात की बड़ी चर्चा है। अगर गांवों में किसी तरह से रिकार्ड मेनटेन करवा दिया जाये, रिकार्ड ऑफ राईट्स हो जाए तो गांवों के गरीब लोगौं को आसानी हो जाये। हर गांव का नक ा ठीक बना दिया जाए तो बैंकों से पैसा लेने में उनको तकलीफ नहीं होगी। वे अपना घर का नक ा दिखा कर पैसा ले लें।

जहां तक इंडस्ट्री लगाने का संबंध है इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर के बिना नहीं चलेगी। हरियाणा में जितना भी ज्यादा

से ज्यादा पैसा एग्रीकल्चर पर लगाया जायेगा उतनी ही ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लेबर को पैसा मिलेगा और अन–एम्पलायमैंट दूर होगीं। एग्रीकल्चर पर पैसा ज्यादा लगेगा तो फूडग्रेन बढ़ेगा जिससे भूखमरी दूर होगी।

पिछले तीस साल में मेरे दे ा ने जो रैपुटे ान कमाई है वह कोई अच्छी नहीं कमाई। हम एक पेटैन्ट बगैर दूसरे दे ाों मे माने गये है। बेसिक डिवैल्पमैंट एग्रीकल्चर की होनी चाहिए। बेसिक डिवैल्पमैंट का सिद्धांत जो हर मुल्क में रहा है वही हरियाणा में भी होना चाहिए। हरियाणा में भी एग्रीकल्चर पर अधिक से अधिक पैसा दिया जाना चाहिए। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता परन्तु जितना अमाउन्ट किया गया है वह कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर को एक्सप्लाएट न किया जाये। जो भी हाउस में मैंम्बर खड़ा हेाता है वही किसान को लेकर एक्सप्लाएटे ान करता है। एक्सप्लाएटे ान नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक का भी सिद्धांत है और दुनिया के जितने भी डिवैल्पड कंट्रीज है उनका भी सिद्धांत है कि एग्रीकल्चर बढ़ जाएगी तो मुल्क में इंडस्ट्री भी बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगी तो इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ी तो रोजी–रोटी लेगों को नहीं मिलेगी, दे ा में स्टारवे ान रहेगी। तो हमको इस सिद्धांत को हरियाणा में पहले नम्बर पर लाना चाहिए। हमारा जितना भी बजट है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर पर

खर्च होना चाहिए। इसलिए यह जो डिमांड नम्बर 17 है यह दे ा के गरीब लोगों के हित में है।

श्री मांगे राम गुप्ता(जींद): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मेरे को सप्लीमैंटरी डिमान्डज पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

डिमांड नम्बर 9 ऐजुके ान के बारे में है। हमारा दे ा प्रजातंत्र दे ा है और हरियाणा में भी डैमोक्रेसी है। डैमोक्रेसी सही मायनों में वही है जिसमें अपोजी ान के साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि रूलिंग पार्टी के सदस्यों के साथ होता है क्योंकि अपोजी ान कबे सदस्य भी अपने हल्के की नुमाइन्दगी करते है। अपोजी ान के सदस्यों का भी यह कर्तव्य होता है कि वे अपने हल्के की डिमान्डज को सरकार के सामने रखें तो रूलिंग पार्टी उन मांगों पर विचार करके स्वीकार करे। इस प्रकार से डैमोक्रेसी अच्छी प्रकार से चल सकती है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा कि आपको मालमू है और मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में जिला जींद में सही मायनों में डैमोक्रेसी है। वह सरकार के पीछे लगने वाला जिला नहीं है। कांग्रेस राज मैं भी यही बात रही है। वहां पर अपोजी ान के मैम्बरों की तादाद हमे ाा फर्स्ट रही हैं। वे हमे ाा अपनी मांग पूरी करवाने की कोि ा ा करते है। जनता सरकार के टाईम पर भी जिला जींद से सबसे अधिक मैंबर बन

कर आये है। इसका मतलब यह हुआ कि जिला जींद आपोजी ान के रोल को डैमोक्रेसी में जरूरी समझता हैं जिला जींद अपोजी ान में सबसे ज्यादा मजबूत होकर आपके सामने बैठा है। जनता पार्टी ने यह वि वास लोगों को दिलाया था कि पिछली सरकार ने जो डैमोक्रेसी का गला घोंट दिया था, लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया था उसको दूर किया जाएगा। कांग्रेस राज में अपोजी ान के मैम्बरों को इतनी भारी तकलीफ हुई जिसके बारे में ब्यान नहीं किया जा सकता। जनता पार्टी ने वि वास दिलाया था कि इस भेदभाव को समाप्त किया जाएगा।

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैम्बर साहब डिमान्ड पर बोल रहे है या जनता पार्टी पर बोल रहे है।

श्री उपाध्यक्षः आप डिमान्डज पर बोलिए। समय थोड़ा है। आपको केवल पांच मिनट दिए गए है।

श्री मांगे राम गुप्ताः डिप्टी स्पीकर साहब, आज हमें आ ाा है कि जनता पार्टी पिछली रिवायात को छोड़ते हुए हमारी मांगों को जिस हल्के की हम नुमाइन्दगी करते है उनको ध्यान में रखते हुए पूरा करने की कोि ा ा करेगी।

डिमांड 9 के तहत 65 लाख रूपया रोहतक यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा है। हमें यह पैसा देने में कोई नराजगी नहीं हैं। हमें तो नाराजगी यह है कि जो लड़के कालेज में

एजुके ान लेना चाहते है उनके अंदर कितनी ज्यादा अन–एम्पलायमैंट बढ़ चुकी हैं, जिसके विशय में ध्यान नहीं किया जा सकता है। एम0ए0, एल0एल0बी0 करने के प चात भी छोटी–छोटी नौकरियां मिलती हैं। दो सौ रूपए की नौकरी के लिए मारे–मारे फिरते है। म्युनिस्पैलिटी की नौकरियों के लिए मोहरिर की पोस्ट के लिए एम0ए0, बी0ए0 पास लोग मारे–मारे फिरते है। जब तक नौजवानो को टैक्नीकल एजुके ान नहीं मिलेगी तब तक उनका भला होन वाला नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज के दिन नौकरी मिलनी बड़ी कठिन हो गई है। आज कोई चाहे ला की डिग्री ले ले, चाहे ओवरसियर बन जाए, चाहे एम0फिल0 की डिग्री ले ले, चाहे पी0एच0डी0 की डिग्री ले लें लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। किसी भी कालेज में या सूनिवर्सिटी में जहा पर हायर एजुके ान के लिए क्लासिज लगती हैं वहां पर उसी कालेज के स्टुडैंटस को एडमी ान के समय पांच परसैंट मार्क्स एक्सट्रा मिलते है। मैरिट के हिसाब से एडमि ान नहीं हो पाता हैं क्योकि उस कालेज के स्टुडैंट को पांच परसैंट की रियायत मिल जाती है इसलिए मेरे जिले में कोई ऐसी डिग्री नहीं है और न ही कोई ऐसा टैक्नीकल कालेज है, जिसमें लड़के एडमि ान ले सकें रोहत यूनिवर्सिटी में जिला जींद के स्टुडैंट ने एम0फिल0 में दाखिला लेना था। उसका मैरिट में 14वां नम्बर था लेकिन पांच परसैंट का कनसै ान मिलने से 22वां नम्बर हो गया। अभी तक उस लड़के को दाखिला नहीं मिला है। यह लड़का हिंदी एम0ए0 का स्टुडैंट है और कालेज के अन्दर फर्स्ट स्टैंड

किया था। पांच परसैंट की रियायत देने से जिन जिलों में कोई भी टैक्नीकल लाईन का कालेज नहीं है उन जिलों के लड़कों को एडमि ान नहीं मिल पाता है। मेरे जिला जींद के लड़के ऐसे कालेजों मैं दाखिला लेने से महरूम रह जाते है। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, आपके जरिए निवेदन करूंगा कि सरकार को कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और बहुत छोटी सी बात है हमारे यहां गवर्नमैंट कालेज में हिंदी एम0ए0 की क्लासिज लगती है वहां पर एम0फिल0 की क्लासिज खोल दी जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। वहां पर न कोई बिल्डिंग की जरूरत है और न ही सरकार पर कोई खर्च पड़ेगा वहां पर ये क्लाजिस चालू की जानी चाहिए ताकि दूसरी जगहों से महरूम न रहें

डिप्टी स्पीकर साहब, एग्रीकल्चर की डिमांड परमेरे से पहले बोलने वाले मानलीय सदस्य काफी रो ानी डाल चुके है। मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा कि मेरे हल्के में ओलावृश्टि के कारण 25–30 गांवों को बहुत नुकसान हुआ है। यह किसी का किया हुआ नुकसान नहीं है, यह तो भगवान की मर्जी है। मैं इसमें सरकार को दोश नहीं बताता हूं। औलों के कारण उनकी सारी की सारी फसल बरबाद हो गई और मकान भी बरबाद हो गए है। वहां पर बारि ा इतनी हुई है कि बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब पिछले सै ान में हमारे मिनिस्टर महोदय ने वि वास दिलाया था कि छोटी–छोटी ड्रेन्ज गांवों में बनाई जा रही है ताकि फ्लड से गांवों को नुकसान न

पहुंचे। मैंने प्र न भी पूछा है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह काम छः महीने तक पूरा हो जाएगा। मैं तो यह कहूंगा कि यदि सरकार को गांवों के लोगों की हैल्प चाहिए तो वे भी हैल्प करने के लिए तैयार है। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से ड्रेनों की वजह से मेरा इलाका इग्नोर हुआ है अगले साल भी इग्नोर न हो जाए। इन 20 गांवों की फसल बिल्कुल बरबाद हो गई है। उनके पास कोई सहारा नहीं है। अगर यह ड्रेन नहीं बनायी गई चाहे बारि ा थोड़ी हो या ज्यादा हो, तो ये 20 गांव बरबाद हो जाएंगे। यहां पर मुख्य मंत्री महोदय भी बैठे हुए है। वे भी किसानों के हमदर्द है, मैं उनसे भी दरखास्त करना चाहता हूं कि जब भी किसी हल्कें की डिमान्ड हो उसके बारे में उस हलके के नुमाइन्दे को कान्फीडैन्स में लिया जाए। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हाई लैवल आफिसर्ज है जिनके हाथों में ला एंड ऑर्डर है या कोई किसानों की भलाई का काम है उनको हिदायत करें कि वहां के नुमाइंदे से सलाह अव य करें। जैसे कई गांवों ओलावृश्टि से बरबाद हो गए या कोई ला एंड आर्डर की सिचुए ान खराब है तो ऐसे मौके पर तो अव य हिदायत कर कि आफिसर्ज वहां के नुमाइंदे से अव य सलाह करें

16.00 बजे मुझे यह वि वास है कि वह हरेक हलके के अंदर चाहे वहां का एम0 एल0 ए0 किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसको कान्फीडैंस में लेकर हलके के लोगो की जो तकलीफे हैं उनको दूर करने में आप हमारे लोगों से सहयोग लेने

की कोि ा ा करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, आप समय देख रहे है, मैं पहल ही जल्दी कर रहा हूं। मुझे कल भी समय नहीं मिला था और आज मैं आपके हुक्म के अनुसार ही चलने की कोि ा ा कर रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं और यह आ ाा करता हूं कि जो दो–तीन बातें मैंने एजुके ान और एग्रीकल्चर के बारे में कहीं है, उनकी तरफ पूरा–पूरा ध्यान देंगे। मैं इस वि वास के साथ अपना स्थान लेता हूं।

स्वामी अग्निवे ा(पुडरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुमानों की मांग संख्या 8, 9, 12 और 13 के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। इस प्रकार की जो अनुपूरक मांगे और बजट आदि रखा जाता है, इससे ने केवल कुछ काम करने के लिए पैसे की मांग पूरी की जाती है बल्कि इससे किसी भी सरकार के चरित्र का पता चलता है कि सरकार किन नीतियों पर चल रही है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार किन चीजो पर किस प्रकार से और कितना जोर डालना चाहती है। मुझे यह सारा कुछ पढ़कर कुछ थोड़ी निरा ाा हुई है। मांग संख्या 8 के अन्तर्गत हमारी सरकार मुआवजा देना चाहती है। जहां भी हमारी सरकार ने कुछ सार्वजनिक कार्य करने का फैसला किया और वह सार्वजनिक कार्य करने के लिए उसने भूमि अधिग्रहण की, वहां पर उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा दिया था, भूमि स्वामी उसके खिलाफ न्यायालयों के अन्दर चले गये और न्यायालय में जाकर

उन्होंने उस मुआवजे की रकम कुछ अधिक बढ़वा ली। आप सब को पता है कि जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आयी और प्रान्तों में आयी तो जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोशणा–पत्र में यह वायदा किया था कि संविधान के अंतर्गत जो सम्पत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसे समाप्त किया जाएगा। उसको समाप्त करने के लिए अब 45 वां संविधान सं ाोधन विधेयक आन जा रहा है जो लोक सभा में इसी सत्र में पारित हो जाएगा। उसके अन्तर्गत सम्पति का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। जब सम्पत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से हमें मुआवजा देने की बात समाप्त हो जाती है जिस प्रकार से हमें न्यायालय बाधित करते है कि हम मार्किट रेट पर ही मुआवजा दें। हालांकि वह कार्य सार्वजनिक हित के लिए होता है, जनता की भलाई के लिये होता है। हमें अभी तक कामि र्यिल रेट्स पर मुआवजा देना होता है। मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार को फिलहाल कोई भूमि सार्वजनिक कार्य के लिए अधिग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे ही यह मौलिक अधिकार समाप्त हो जाये तो उसके बाद सार्वजनिक कार्यों को करने की जिम्मवारी लेकर कम से कम मुआवजा या बिना मुआवजा दिए, भूमि अधिग्रहण करने का हमें पूरा अधिकार होगा। सार्वजनिक कामों के लिये तो मेरा यह सुझाव है। दूसरी बात ि ाक्षा के बारे में मैं यहां पर कहना चाहूंगा। 65 लाख रूपया हमारी सरकार महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी को देने जा रही है। (एक आवाजः दे दिया गया है) हां जी, दे दिया गया है। अब यह प्र न पैदा होता है

कि वि वविद्यालयों की जो ि ाक्षा है, वह सब से ऊपर की ि ाक्षा हैं। ि ाक्षा के मामले में जो हमारे अपैक्स इंस्टीच्यू ान्ज है इनको प्राथमिकता दी जाये या कि प्राइमरी एजुके ान को। ि ाक्षा के विशय में जितने भी पिछले कमी ान बैठे है आप किसी की रिपोर्ट पढ़ लें, कोठारी कमी ान की रिपोर्ट चाहे आप पढ़ ले या चाहे आप तारकुण्डे कमी ान की रिपोर्ट पढ़ लें। हर एक रिपोर्ट के अन्दर यह दिया हुआ है कि अगर प्राइमरी स्कूल के अन्दर 100 विद्यार्थी दाखिल होते है ते एक बच्चा ही पोस्ट ग्रेजुएट लैवल तक पहुंच पाता है। 100 मेें से एक को वहां तक पहुंचाने के लिए आप हर दो–तीन महीनें के बाद करोड़ों रूपया खर्च करने की मांग पे ा करते है। आज जहां से बच्चे पढ़ाई भाुरू करते है, यानि प्राइमारी स्कूलों की हालत बड़ी दयनीय है। इतनी बुरी हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी गांव मैं जाकर देखें। एक कमरे के अन्दर 5 कक्षाओं के विद्यार्थी बिठाए गए है। यानी सिंगल रूम स्कूल है, एक कमरे में स्कूल चल रहा हैं और मास्टर भी वहां पर पढ़ाने वाला एक ही है। वही टीचर पहली को पढ़ाता है, वही टीचर दूसरी को पढ़ाता है, वहीं तीसरी को पढ़ाता है, वहीं चौथी को पढ़ाता है और वही पांचवी को पढ़ाता है। उसके साथ ही स्कूलों की बिल्डिंगे आप जाकर देखिये। ऐसी है कि 90 प्रति ात बरसात में टपकती है। जो हमारे प्राइमारी स्कूलों की बिल्डिंगें है, वे अकसर बरसात में टपकती आपको मिलेंगी। बैठने के लिए फ ा ठीक नहीं है। बरसात अच्छी खासी हो जाए तो मास्टर जी छुट्टी कर देते हैं। गर्मी की छुट्टियां अभी होकर

हटी है।, उसमें पहले दो अढ़ाई महीने खराब गये। अब बरसात में अनऔफिि ायल ढंग से उनकी छुट्टी हो जाती है क्योंकि बरसात में बच्चों के बैठन के लिए कोई जगह वहां पर नहीं हैं। मेरे दे ा के फूल से कोमल बच्चे, किसान मजदूर के छोटे–छोटे बच्चे जिनका सबसे पहला हक बनता है कि वे भारतीय नागकि होने के नाते संविधान के अन्तर्गत उनके लिए जो ि ाक्षा अनविार्य की गई है कि 6 साल से लेकर 14 वर्श तक की आयु के बच्चों के लिए ि ाक्षा अनिवार्य होगी उनका यह हाल हो रहा है। इतना कुछ संविधानिक गारंटी होने के बावजूद उनके लिये सुविधायें क्या है? सुविधायें उनके लिए बिल्कुल नहीं के बराबर है। दूसरी तरफ आप वि ववविद्यालय में जायें। आप कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैम्पस को जाकर आप देखें। आप हिसार यूनिवर्सिटी के कैम्पस को जाकर देखिये। उसी की नकल पर आप रोहतक यूनिवर्सिटी का कैम्पस तैयार करवाना चाहते है। मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान में तो क्या इन यूनिवर्सिटीयों के कैम्पस को अगर आप किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से कम्पेयर करेंगे तो वह भी इतनी अधिक सुन्दर नहीं है, भाानदार नहीं है। यह बड़े–बड़े ि ाक्षाविदों की राय है जो विदे ाों में कई बार घूमकर आये है। आखिर हम चाह क्या रहे है? मैं यह नहीं कहता हक आप भाानदार बिल्डिंग न बनाओ। पहले हमने यह देखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है? प्राइमरी स्कूलों के अन्दर तो पीने का पानी भी नहीं है और आप प्राथमिकता देते हो हायर एजुके ान को। मुझे कुछ समय तक ि ाक्षा बोर्ड के अन्दर सेवा करने का अवसर

मिला था। उस दौरान में मैंने जब भी जाकर गांव में देखा, बड़ी ही दयनीय परिस्थिति थी। इन स्कूलों के अन्दर बच्चे कड़कती सर्दी के अन्दर, जब हम बिना जूते के वाहं पर खड़े नहीं हो सकते ाि, उस समय हमारी छोटी–छोटी बहिनें बेचारी नगे फ र्ा पर बैठ कर पढ़ाई करती थीं, बैठने के लिए हम उनको फटा हुआ टाट नहीं दे सकते, पीने का पानी हम नहीं दे सकते, खेलने का सामान हम नहीं दे सकते, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पंखे नहीं दे सकते, जो वहां प्राइमरी सुविधायें होनी चाहिए जैसे यूरिनल की, वे हम नहीं दे सकते, बाउंडरी वाल हम नहीं दे सकते। इतनी दयनीय स्थिति होने के बावजूद हम अपनी सूनिवर्सिटीज को ग्लैमर का सैंटर बना दे, एक आकर्शण का केंद्र बना दें और उन पर बेतहा ाा पैसा खर्च करते चले जायें, इसका कहां तक औचित्य है? यदि हमारे यहां पर प्राइमरी स्कूलों की हालात अच्छी हो, फिर तो हम बे ाक कालेजों पर खर्च करते जायें, बे ाक यूनिवर्सिटज एजुके ान पर खर्च करते जायें। वरना क्या होगा? जो आप उल्टा पिरामिड तैयार करते जा रहे है, जो आप उल्टा खड़ा करना चाहते है, वह खड़ा नहीं रह सकता, वह ढ़ह जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कलकता यूनिवर्सिटी अव य देखी होगीं वहां पर मुझे दस–बारह साल तक ि ाक्षा ग्रहण का अवसर मिला है। भाहर के बीच में वह एक छोटी सी बिल्डिंग है। भारत की वह सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है लेकिन उसके पास अपना

कोई कैम्पस नहीं है। आखिर यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का काम यह नहीं है कि वहीं पर सारे कालिज हों और वहीं पर पढ़ाई हो। हरियाणा के जितने कालिज है वे सब रोहतक और कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ऐफिलेटिड है, इनसे संबंधित है। फिर क्या जरूरत है कि इन यूनिवर्सिटियों के इतने भाानदार कैम्पस बनाए जाएं, इनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जाए। इनका केवल मात्र कार्य एग्जामिने ान लेना तथा रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। आप देखिए जैसे हरियाणा ि ाक्षा बोर्ड है वह प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी कक्षाओं की परीक्षाएं लेता है और उनका रिजल्ट डिक्लेयर करता है। उसके पास कोई कैम्पस नहीं है, एक छोटा सा दफ्तर है। यूनिवर्सिटी का तो काम केवल एग्जामिने ान लेना और रिजल्ट डिक्लेयर करना है। पढ़ाई का काम तो कालिजिज में होता है। हां अगर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासिज चलानी हों तो कुछ किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी इतनी भाान भौकत की कोई आव यकता नहीं है। आज एक प्रौफेसर और स्कूल मास्टर की तनख्वाह में कितनी असमानता है। एक प्रौफेसर को अढ़ाई हजार रूपया तनखाह मिलती है। अढ़ाई हजार रूपया लेने वाला प्रौफेसर अढ़ाई या तीन घंटे पढ़ाता है और दूसरी तरफ एक स्कूल का मास्टर है जो सुबह से लेकर भाम तक लगा रहता है। उसकी तनखाह एक प्रौफेसर के मुकाबले में बहुत कम है। मेरा कहना तो यह है कि अखिर कोई समानता तो होनी चाहिए। एक जो स्कूल का टीचर है उसने बच्चों का निर्माण करना है, उनके संस्कारों को

बदलना है। उन्हीं बच्चों ने दे ा का भावी नागरिक होना है। तो जहां पर बच्चों के संस्कार बदलने का काम होता हैं, बच्चों को सुधारना है वहों पर तो बहुत कम पैसा खर्च किया जा रहा है और ऊपर वि ववि्यालय पर बहुत खर्च किया जा रहा है। आज ि ाक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। यह जो अनुपूरक मांग आई है उसको देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई है। इस मांग द्वारा 65 लाख रूपया देने की मंजूरी मांगी गई है। यह 65 लाख रूपया दिया जा चुका है। यह रूपया किस चीज पर खर्च किया होगा। अगर वहां जाकर देखें तो पता लगेगा कि यह सारीा पैसा फर्नीचर, बिल्डिंग और वाईस चांसलर के आफिस को एयर कंडी ांड करने के ऊपर खर्च किया गया होगा। इस पैसे मैं से आम विद्यार्थी के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया गया होगा। जनता सरकार के बनने के बाद आखिर क्या परिवर्तन आया। अगर हम भी उसी ढांचें पर चलते रहे तो उस सरकार और हमारी सरकार में फर्क ही क्या रहा। पहली वाली सरकार और आज की जनता सरकार में कोई अन्तर नहीं रह जाता(ाोर)। मैं ि ाक्षा के सन्दर्भ में बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ि ाक्षा का सारे का सारा ढांचा बदलना चाहिए और यूनिवर्सिटी पर कम से कम खर्च करना चाहिए और उसके प चात् जो पैसा बचे उसे यूनिवर्सिटी पर खर्च करना चाहिए। लोक नायक श्री जय प्रका ा जी ने ि ाक्षा के बारे में आना एक सुझाव दिया है कि हायर एजुके ान में तो जो धनी लड़के है वे अपना खर्चा अपने आप बर्दा ात कर लेंगे। जो बहुत गरीब विद्यार्थी है उनके लिए

स्कौलरि ाप की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में तीन हजार से अधिक प्राइमरी और हाई स्कूल है और इनमें लाखों बच्चें पढ़ते है। मुझे पता लगा है कि इनके खेल–कूद के लिए, इनके भाारीरिक विकास के लिए लगभग एक करोड़ रूपए की व्यवस्था बजट मैं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राई में मोती लाल नेहरू स्पोट्र्स स्कूल है वहां पर दो सौ या अढ़ाई सौ अमीर घरानों के बच्चें पढ़ते है। मुझे पता लगा है कि इस एक करोड़ में से 75 लाख रूपया तो इस स्कूल के बच्चों पर खर्च कर दिया जाता है और बाकी 25 लाख रूपया सारे हरियाणा के लाखों बच्चो पर खर्च कर दिया जाता है। कैसी अजीब बात है कि जहां पर अमीर घरानों के बच्चे पढ़ते है और वे भी केवल दो सौ या अढ़ाई सौ वहां पर तो 75 लाख रूपया खर्च करते है और जहां हरियाणा के किसान के बच्चें, मजदूरों के बच्चे, आम गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते है वहां केवल 25 लाख रूपया खर्च होता है। इससे बड़ा अन्याय उन गरीब बच्चों के साथ और क्या हो सकता है। मैं चाहता हूं कि ि ाक्षा मंत्री इस मांग के बारे में जवाब देते समय इसके संबंध में बताएं और सदन को वि वास दिलाएं कि हरियाणा की धरती पर इस प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

अगली डिमांड नं0 12 है जो श्रम तथा रोजगार के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आप किसी भी गांव में घुस जाइए, जब हम फक्कड़ थे तो उस वक्त तो कोई नहीं पूछता था लेकिन आजकल कहीं चले जाते है तो एम0 एल0 ए0 के नाते लोग समझते है कि हम लोग कोई सिफारि ा कर देंगे तो नौकरी लग जाएगी। आजकल बेरोजगारी कि बहुत बुरी हालत है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे–जैसे हम ि ाक्षा का विस्तार कर रहे है और उच्च ि ाक्षा दे रहे है बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वर्श के अन्दर इन आई0टी0आईज0 में सौ अथवा दो सौ बच्चों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होगी लेकिन क्या इससे हम बेरोजगारी की समस्या को हल कर पाएंगे। क्या हमारे बच्चे इन आई0टी0आइज0 से ि ाक्षा ग्रहण करने के प चात् अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन जाएंगे? क्या उनके पास ऐसे साधन है जो ट्रैनिंग ली है बेकार फिर रहे है। उनके पास अपने काम आरम्भ करने के लिए साधन नहीं है अगर वे कोई काम आरम्भ भी करते है तो उनकी चीज के लिए मार्किट में भी कही थी और आज सदन में भी कना चाहता हूं कि जब तक हम अपनी इकौनौमी में अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं लाएंगे, कुछ सैक्टर्ज को ईयरमार्क करके ग्रामीण धंधों के लिए अथवा कुटीर उद्योगों के लिए नहीं रखेंगे तब तक रोजगार की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता। आज बेरोजगारी की कितनी भयंकर समस्या है। अभी कुरूक्षेत्र जिले में कौआप्रेटिव सोसायटिज में क्लबों और मिनि बैंकों में

मैनेजरों की चालीस पोस्टें थी। उपाध्यक्ष महोदय, इन चालीस स्थानों के लिए 15 हजार ऐप्लीके ांज आई। इतनी गम्भीर समस्या बेरोजगारी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हम तमाम बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकेंगे बल्कि इन लोगों के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है.....

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डरर, डिप्टी स्पीकर साहब,* * * * * * * * * * * * * * * मिनि बैंक्स में बैंक मैनेजरों के लिए 15 हजार ऐप्लीके ांज नहीं आई है। ये गल्त कह रहे है (ाोर)।

स्वामी अग्निवे ाः उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस बारे में हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा। गरीब, निर्धन विद्यार्थियों और नौजवानों को हम रोजगार दे पाएंगे ऐसी आ ाा दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार सब को नौकरी, जिसे हम व्हाइट कालर जोब कहते है, नहीं दे पाएगी। इनको रोजगार देने का एक ही तरीका है कि इन लोगों को मार्किट प्रोवाइड कर दें। कपड़े की मार्किट, साबुन की मार्किट और जूते की मार्किट इन तीन चीजों की मार्किट हम इनको प्रोवाइड कर दें। इन तीन चीजों के लिए हम यह आर्डर कर दें कि लार्ज स्केल की इन चीजों के लिए जो इंडस्ट्रीज है उनकी चीजें हरियाणा के अन्दर नहीं आएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें। मैं यह चाहता हूं कि यदि हम कानून बना दें कि हरियाणा के अन्दर मिलों का बना हुआ कपड़ा

इस्तेमाल नहीं होगा, फैक्टरी या कम्पनी के बने हुए जूते की दुकानें नहीं होगी। जो भी जूता यहां बिकेगा वह गांव के लोगो के हाथ का बना हुआ होगां जो साबुन होगा वह हिन्दुस्तान लिवर कम्पनी का नहीं होगा बल्कि गांव के लोगों द्वारा बना साबुन हरियाणा में बिकेगा। मिल का कपड़ा हरियाणा में नहीं बिकेगा बल्कि हाथ की खड्डी से बुना हुआ कपड़ा बिकेगा। अगर आप इस बात को प्रोटैक ान नहीं देते है तो किसान का लड़का, हरिजन का लड़का उन मिलों के द्वारा बनाए हुए माल का मुकाबला नहीं कर सकेगा और मुकाबला न करने की वजह से उसका माल नहीं बिकेगा और बड़े–बड़े इंडस्ट्रीयलिस्टस, बड़े–बड़े सरमायेदार उनको निकाल कर बाहर कर देंगे। इसलिए मेरी आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार से प्रार्थना है कि अगर हम वास्तव में रोजगार की समस्या का समाधान करना चाहते है तो हमें कोई कठोर निर्णय करना पड़ैगा तभी यह रोजगार की समस्या का हल हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जो नौकरियों के लिये इंटरव्यू का सिस्टम चल रहा है, कम से कम मेरी तो उससे तसल्ली नही हो रही है। आज हरेक जगह पर सिफारि ाों के बल पर नौकरियां मिल रही है। आज भी उसी पूंजीवाद के ढ़ांचें से ये लोग चल रहे है इसलिये हमें सारा सिस्टम ही बदलना होगा तभी इस दे ा की भलाई हो सकती है और मैं यह चाहूंगा कि नौकरियों में बिल्कुल मैरिट के आधार पर ही चला जाए तो बेहतर होगा, वह भी केवल नम्बर और किताबों की पढ़ाई के ऊपर ही नहीं बल्कि श्रम और उत्पादक श्रम का भी नौकरी देते समय ध्यान

रखा जाना अनिवार्य होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ हमें ि ाक्षा के स्तर को, ि ाक्षा के कनटैन्ट को बदलना होगा। जो ि ाक्षा हम पढ़ा रहे है उससे हम बच्चों को मिलावट खोर बना रहे है, मुनाफाखोर बना रहे है। डिप्टी स्पीकर साहब, आने भी अपनी कालेज की ि ाक्षा के दौरान यह अनुभव किया होगा और आज भी कीन की इकनामिक थ्यूरी हमारे कालेजों के अन्दर पढ़ाई जा रही है, कीन की थ्योरी जो प्रोफिट मैक्सीमाईजे ान से भाुरू होती है, अनलिमिटेड वान्टस की थ्यूरी से जो भाुरू होती है और वह यह मानकर चलते है कि अधिकाधिक मुनाफा कमाना ही किसी मूल एक्टिविटी का मूल आधार है। आप ही देख सकते है कि ऐसी ि ाक्षा हमें कहां पर लाकर खड़ा कर देगी और हम किस प्रकार के समाजवादी ढ़ांचें की रचना कर पाएंगे।

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, आपका समय समाप्त हो रहा है।

स्वामी अग्निवे ाः उपाध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को उपसंहार की तरफ ले जाते हुए आदरणीय मुख्य मुंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम कुछ मौलिक परिवर्तन की आकांक्षाएं लेकर आये है तो इन अनुपूरक मांगों के रूप में चरित्र उभर कर सामने आना चाहिये। मुझे यह पढ़कर उपाध्यक्ष महोदय ऐसा लगा कि जैसे पहले 30 सालों में यह अनुपूरक मांगें आईज नोज कहकर पास होती रही, अगर अब भी ऐसा ही कह कर हम

बैठ जाएं तो जो जनता की आकांक्षाएं है, जो जनता ने इस सरकार से उम्मीदें लगा रखी हैं, वे पूरी नहीं होंगी और जिस काम के लिए जनता ने हमें यहां पर भेजा है, वह काम भी पूरा नहीं हो पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाज कल्याण और पूनर्वास के बारे में कुछ कहना चाहता हू। इस में हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा योजना का जिक किया है जिसके अन्तर्गत तमाम सरकारी कर्मचारियों का बीमा किया जाएगा। अच्छी बात है, इस बारे में मेरे या किसी और के दो मत नहीं हो सकते। लेकिन फिर वही सवाल प्रायरिटी का उत्पन्न होता है, सेन्स आफ प्रायरिटी का सवाल पैदा होता है और यह जब तक हमारी सरकार के अन्दर नहीं होगा तब तक हम किसी का भी भला नहीं कर पाएंगे। किस का बीमा पहले होना चाहिये, किस का बीमा नम्बर दो पर होना चाहिये, किस का बीमा नम्बर तीन पर होना चाहिये, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे देहातों में हमारा गीब किसान जो सर्दी गर्मी में अपनी हड्डिया गलाता है, फसल पैदा करता है और जब औले पड़ जाते है तो उसकी सारी फसल बरबाद हो जाती है उस किसान के लिये कभी हमने सोचा है कि इस का भी बीमा होना अनिवार्य है? उसके प ाुओं का कभी सोचा है? गरीब किसान के प ाु मर जाते है, बीमारियां फैल जाती है, और हर साल बाढ़ भी आती है जिसके ऊपर गरीब किसान का कोई जोर नहीं कि इसकी रोक

कर सके उस बेचारे किसान को प्रकृति के प्रकोप के साथ इस विना ा लीला का प्रकोप भी सहन करना पड़ता है, कभी सरकार ने इन गरीब किसानों की तरफ देखा है कि उन बेचारों का भी बीमा होना चाहिये, इन मेहनतक ा लोगो की तरफ भी सरकार को खास ध्यान देना चाहिये, इन लोगों के जीवन रक्षा के लिये भी सरकार को कोई न कोई उपाय करने चाहियें। उधर जो दफ्तरों मैं पंखों के नीचे, टेबल के ऊपर कलम चलाकर जो काम करने वाला सरकारी कर्मचारी है, मेरा उनके प्रमि कोई ऐसा विचार नहीं है, उन कर्मचारियों के लिये सरकार ने बहुत सी सुविधाएं प्रदान कर रखी है, मैं तो केवल उन लोगों का जैसे गरीब किसान, गरीब मजदूर से जो किसान हल चलाता है, जो मजदूर हथौड़ा चलाता है, जरा मुकाबला करता हूं। जैसे आज से 30 साल पहले अंग्रेज जाने से पहले जी चाहते थे, वही हम सब में एक दूसरे के प्रति व्हाईट कालर्ज और मेहनत करने वाले मजदूर के दरमियान दूरी कायम है इसलिये मैं यहां पर अपनी बात को समाप्त करते हुए यह चाहूंगा कि जहां पर हम राज्य के सरकारी कर्मचारियों के जीवन के बीमे का प्रावधान करें वहां पर मैं यह भी चाहूंगा कि किसान की फसल का, उसके पु ाुओं का भी बीमा करना नि चत रूप से अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसा लगेगा कि जो वर्ग पहले से सुविधा प्राप्त है, जो पहले से आर्गेनाइज्ड लोग है, केवल उन्हीं की आवाज हम सुनने के लिए तैयार है पीड़ित और भाोशित जो गरीब लोग है उनके प्रति हमें कोई सहानुभूति नहीं हैं, हम

उनकी आवाज बिल्कुल सुनने के लिये तैयार नहीं है, और न ही उनके लिये हम कुछ करना चाहते है। धन्यवाद।

श्री रघुनाथ गोयल(कैथल): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा ही धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सब से पहले मैं अपने हल्के के गांवों की सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहता हूं कि वहां पर जो एक–एक किलामीटर की छोटी–छोटी सड़क है, वे बहुत ही खराब हालत में है, लोग उनके ऊपर चल फिर नहीं सकते, इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी प्रायरिटी बेसिज पर पहले बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा न हो।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि हमारे कैथल में आई0टी0आइज0 है जिनके लिये हमने डाक्टर साहब से भी कहा था कि वे हमारी चारों की चारों फिर से खुलनी चाहिये। ि ाक्षा के बारे में जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि हमारे वक्त में एक धर्म ि ाक्षा का पीरियड लगा करता था जिससे बच्चों का चरित्र बहुत उज्ज्वल और ऊंचा होता था, वैस स्थिति भी आजकल स्कूलों में होनी चाहियें मतलब कि हरेक स्कूल में एक पीरियड धर्म ि ाक्षा का अव य लगना चाहिये ताकि जिस से बच्चों का चरित्र ऊंचा हो सके लेकिन आजकल स्कूलों में सिवाये झगड़े और हो–हुल्लड़ के और कुछ नहीं सिखाया जाता। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें स्कूलों में

बंद करवाई जाएं जिससे कि बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और ि ाक्षा का स्तर जो है, उसको और ऊंचा उठाया जाए ताकि बच्चों का अपना स्तर भी ऊंचा हो। धन्यवाद।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में सप्लीमैंट्री बजट पर बहस चल रही है। मांग नम्बर 8 जो कि एक चाजर्ड आईटम है मेरी राय मैं उस पर बहस करना ज्यादा वांछनीय नहीं होगा इसलिये जो वोटिड आईटमज है उनमें से कुछ के ऊपर मैं अपने ख्यालातों को इजहार करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मांग नम्बर 9 पर बोलना चाहूंगी जोकि ि ाक्षा से संबंधित है उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सदन के साथी स्वामी अग्निवे ा जी ने बड़ी ही बखूबी के साथ एक प्र न को यहां पर उठाया है जिसको भाायद मैं सब से पहले इस सदन में रखना चाह रही थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी होती है यह कहते हुए कि पिछली बार बजट निर्धारित करते समय तमाम हरियाणा के स्कूलों की मुरम्मत के लिए 20 लाख रूपये की रा ाी का प्रावधान न किया गया और आज केवल मात्र एक महर्शि वि वविद्यालय, रोहतक के लिये सीमा निर्धारित करते समय 65 लाख रूपये दिये जा रहे है और फिर इसके बाद अगली सप्लींमैंट्री ऐस्टीमेंट्स में इसी के कम के साथ इसी तरह के और रूपये का प्रावधान होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह मसला पहले ही सदन के सामने रखा जा चुका है कि आज हमारे प्राईवेट स्कूलों की हरियाणा में क्या द ाा है। स्वामी जी ने तो भाायद

किसी एक स्कूल के एक कमरे में पांच कक्षाएं लगती देखी है लेकिन मैं बताती हूकि हमारे हरियाण के देहात में इस तरह के स्कूल्ज भी है जहां एक भी कमरे के अन्दर अध्यापकगण बच्चों को देखते हुए कतराते है क्योंकि पता नहीं किस वक्त, किस क्षण उस स्कूल की छत गिर जाएं और बच्चों का खातमा हो जाए, इसी कारण वे बेचारे बच्चे आका ा की छत के नीचे बैठते है और जब–जब बरसात आती है तो उन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। इतनी बुरी हालत आज हरियाण में स्कूलों की है और जब तमाम हरियाणा के स्कूलों में ऐसी हालत है तो इसी लिये हम वहां पर बच्चों को अच्छा वातावरण पढ़ाने के लिए नहीं दे पा रहे है। और जब हमारे हरियाणा के स्कूलों की ऐसी हालत हो तो ऐसे वक्त मैं हम महर्शि दयानंद वि ववविद्यालय को 65 लाख रूपये की रा ाी देकर एक प्राथमिकता निर्धारित करने जा रहे है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि यह 65 लाख रूपये की रा ाी वि ववविद्यालय को न दी जाए बल्कि मुझे खु ाी होती है अगर इस रूपये के साथ हरियाणा के तमाम स्कूलों की मुरम्मत के लिये रा ाी दी जाती और जिन गांवों में स्कूल नहीं हैं, वहां पर स्कूलों को बनाये जाने के लिये सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेटस में प्रावधान किया जाता। इसके साथ–साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं ि ाक्षा विभाग में हुई अनियमितताओं की रतफ आपका और ि ाक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्शित करना चाहती हूं जिसके कारण पैसे की बरबादी भी हो रही है और लोगों को काफी असुविधा भी हो रही है। सब से पहले उपाध्यक्ष महोदय, मैं टीचर्ज की तरफ आपका ध्यान

दिलाना चाहूंगी कि आज हरियाणा में कम से कम 200 टीचर्ज ऐसे है जहां पर हिंदी टीचर्ज के स्थान पर एस0 एस0 मास्टर लगाये हुए है। उपाध्यक्ष महोदय मेरा कहना केवल यह नहीं कि एक कैटेगरी के टीचर वहां पर न लगाकर दूसरी कैटेगरी के टीचर्ज वहां लगाये है। मैं आपको बताती हूं कि हिंदी टीचर्ज का ग्रेड 125–5–250 का है और सिलेक ान ग्रेड 250–350 का है जबकि एस0 एस0 मास्टर्ज को हिंदी टीचर्ज की जगह लगाया है। उसका ग्रेड 220–8–300–10–400 का है और सलेक ान ग्रेड 420–500 का है यानि कि एक वह जगह जहां पर कि एक हिन्दी टीचर 125 रूपये में काम कर सकता है वहां पर एस0 एस0 मास्टर काम कर रहा है जिसको हम 220 रूपये देते है। इस से केवल मात्र पैसे की बरबादी तो हो ही रही है बल्कि यह भी हो रहा है कि ट्रेन्ड हिंदी टीचर जो है जो ट्रेनिंग लेकर आए है आज वे हरियाण की सड़कों पर घूम रहे है और वे एस0 एस0 मास्टर्ज जिन्होंने केवल मैट्रिक तक हिंदी पढ़ी है उनमें से भाायद किसी एक दो ने बी0 ए0 तक हिन्दी पढ़ी हो जो कि इस प्रकार की ि ाक्षा देने में माहिर भी नहीं है, वे लोग आज नौकरियों मैं विराजमान है, इस प्रकार से सरकार के पैसे की बरबादी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से साईंस टीचर्ज की जगह भी एस0 एस0 मास्टर लगाए हुए है। मैं मानती हूं कि दोनों टीचर्ज का ग्रेड सेम है, दोनों कैटेग्रीज में पैसे का कोई फर्क नहीं है.....।

Development Minister(Shri Lachhman Singh): On a point of Order. Is the Hon'ble Member speaking on the demand on University grant? There can be no general discussion.

Mr. Deputy Speaker: I would request the Hon. Member to speak on the demands under discussion.

श्रीमती सुशमा स्वराजः सरदार लछमन सिंह जी जरा सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस की किताब को उठा कर देखें, उनको पता लग जाएगा कि जो 277 हैड है वह ि ाक्षा विभाग का है। मैं ि ाक्षा विभाग से संबंधित ग्रांट पर बोल रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इसलिए कि यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम आ गया इसलिए ये समझ बैठे कि मैं यूनिवर्सिटी की ग्रांट के ऊपर बोल रही हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रही थी कि साईंस टीचर्ज की जगह एस0 एस0 मास्टर्ज लगाए हुए है। मैं मानती हूं कि जो ग्रेड साईंस टीचर का है वहीं एस0 एस0 मास्टर्ज जो साईंस की ि ाक्षा से पारंगित नहीं है, साईंस जिन्होंनें पढ़ी नहीं वे हमारे हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को साईंस पढ़ा रहे है। यह बात भी नहीं है कि साईंस मास्टर्ज अवेलेबल नहीं है बल्कि साईंस की ि ाक्षा में पारंगित साईंस टीचर्ज आज हरियाणा की सड़को पर घूम रहे है और उनकी जगह एस0 एस0 मास्टर्ज लगाए हुए है। मैं ि ाक्षा मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि अगर यह धांधली खत्म हो जाएगी तो बच्चों को सही पढ़ाई मिल पाएगी और वे बेरोजगार लोग जो आज ट्रेंड होने के बाद भी सड़कौं पर घूम रहे

है उनको भी रोजगार मिल जाएगा। इसके साथ–साथ जो ि ाक्षा विभाग में पैसें की बरबादी हो रही है वह बर्बादी भी बच जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, ि ाक्षा विभाग के बारे में दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहती हूं कि आज के समय में हरियाणा प्रदे ा के टीचर्ज की वौलंटरी रिटायरमैंट की ऐज 25 वर्श की नौकरी से पहले नहीं ले सकता। जबकि पंजाब और राजस्थान यह अवधि घटा कर 20 वर्श कर दी गई है। मैं ि ाक्षा मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि अगर वे भी इस अवधि को घटाकर 20 वर्श कर दें तो आप यह देखिए कि एक तो उनको पैं ान कम जाएगी दूसरे जो जगह खाली होगी उन पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि इच्छा से कोई आदमी जाना चाहता है तो उसको यह अवसर क्यों न प्रदान किया जाए? सरकार का इसमें कोई हर्ज नहीं होगा बल्कि सरकार को तो और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और ज्यादा अवसर मिलेंगे बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के और उपाध्यक्ष महोदय, वे जो नए लगे हुए लोग होंगे उनको तनखाह भी कम देनी पड़ेगी क्योंकि 25 साल की सर्विस के बाद इंक्रीमेंट लगने के कारण आदमी ज्यादा तन्खाह पाता है। इसलिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अगर वे वौलंटरी रिटायरमैंट की अवधि 25 वर्श से घटा कर पंजाब और राजस्थान के पैटर्न के ऊपर 20 वर्श कर दें तो उससे सरकार को पैसे की भी बचत होगी और बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के अवसर प्रदान कर सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो ि ाक्षा के संबंध में मैं कहना चाहती हूं

वह टीचर्ज के मैडीकल अलाउंस के बारे में है इस वक्त हमारे यहां एक ऐसा प्रावधान है कि टीचर्ज मैडीकल बिल दिखाकर रि–इम्बर्सनैंट लेते है। ठीक है यह प्रावधान दूसरी नौकरियों में भी चल रहा है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें प्रैक्टीकली भी देखना पड़ेगा कि इसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। आज हरियाणा में हालत यह है कि भाहरों में रहने वाले टीचर तो मैंडीकल रि–इम्बर्समैंट लेते है और यहां तक भी देखने में आया है कि एक–एक महीने में डाक्टरों से बिल बनवा कर तीन–तीन सौ रूपए का मैडीकल रि–इम्बर्समैंट भाहरों में रहने वाले टीचरों ने लिया है जबकि देहात में रहने वाले टीचर इससे बिल्कुल वंचित हो जाते है ओर कोई भी मैडीकल रि–इम्बर्समैंट उनको नहीं मिल पाता। इसलिए मैं ि ाक्षा मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि वे अगर इस मैडीकल अलाउंस को फिक्स कर दें, पे के साथ दे दें तो जो तीन–तीन सौ और चार–चार सौ रूपए महीने के उनको फिजूल में फर्जी बिलों के देने पड़ते है उनसे बच जाएंगे और भाहर और देहात दोनों के टीचर यह मैडीकल अलाउंस वसूल कर सकेंगे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं0 12 को लूंगी जो कि श्रम और रोजगार से संबंधित है। जो आई0टी0आई0 सैंटर्ज यहां खुलने वाले है वह ठीक है और बड़ी अच्छी बात है। इनसे रोजगार के लिए ि ाक्षा दी जाएगी, तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा। अगर कोई साधन सम्पन्न नहीं होगा तो बाद में उनको अगर कर्जे

इत्यादि दिलवाए जाएं तो वे लोग अपना काम करने मैं भी दक्ष हो जाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ये केवल दो सैंटर्ज खुल रहे है 14 लाख 98 हजार रूपए की लागत सें न मालूम किस प्रकिया से इन सैंटर्ज को खोलने के लिए जिला सिरसा और सोनीपत चुने गए है। आप ने देखा कि सदन में यह सवाल बार–बार उठता है चाहे वह सड़कों का हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो और चाहे बिजली की समस्या हो और चाहे बिजली की समस्या हो यानी किसी भी तरह के अगर प्रौजैक्ट देने की बात आती है तो सदन के सभी लोगों के मन में इस तरह की भावना आ जाती है कि बाकी जिलों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। बार बार कोई न कोई ऐसा प्रोजैक्ट सामने आ जाता है जिससे भेदभाव की भावना की ज्यादा गंध मिलती है। इस बार भी हमने देखा कि 14 लाख 98 हजार रूपए की लागत से सैंटर्ज खुल रहे है केवल सिरसा और सोनीपत में और उसमें भी आप देखें कि जो सिरसा में सैंटर खुल रहा है वह तो 9.67 लाख रूपए से खुल रहा है और जो सोनीपत में खुल रहा है वह 5.31 लाख रूपए की लागत से खुल रहा है यानी इन दो सैंटर्ज में भी दुभाव किया गया है कि बड़ा सैंटर तो सिरसा जिला में खुल रहा है और छोटा सैंटर सोनीपत जिला मैं खुल रहा है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इन सैंटर्ज के खुलने से हमें किसी तरह का कोई एतराज नहीं है लेकिन इस तरह के सैंटर्ज खोलते वक्त हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय आप जानते है कि न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए बल्कि लोगों

को यह लगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। इसलिए इस चीज को सामने रखते हुए बाकी हरियाणा के जिलों को भी मद्देनजर रखा जाए और इस तरह के सैंटर्ज और जगह भी खोलने का प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहती हूं कि श्रम और रोतगार की मद के तहत एक चीज जो मैं चाहती थी कि भाायद सप्लीमैंटरी एस्टीमेट्स में आए, वह नहीं आई है। आपको मालूम है कि काफी दिनों से डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड में हड़ताल चल रही है। वहां 33 दिनों की हड़ताल चली और 19 दिनों का धरना भी चला। वहां के मजदूरों को तनखवाह नहीं दी गई, उनको बोनस नहीं दिया गया। उन मजदूरों की डिमांड है कि उन को पुराने पैसे की अदायगी की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहूंगी कि किस तरह से वह दादरी सीमेंट लिमिटेड बंद हुई, किस तरह से उसमें घपला हुआ, किस तरह से वहां के उद्योगपति पैसा निकालकर केवल मात्र लाइबिल्टी सरकार पर छोड़कर चले गए। इस तरह की तफसील से मैं अगर चली गई तो सदन का काफी समय लग जाएगा। इसलिए सदन के समय का पूरा ध्यान रखते हुए मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहती। लेकिन एक बात मैं ि ाक्षा मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगी क्योंकि वे लेबर मिनिस्टर भी है कि बार–बार केंद्र की तरफ से हरियाणा सरकार को अगाह किया गया है, केंद्रीय उद्योग मंत्री जार्ज फर्नांडीज ने स्वयं इस बात से अगाह किया है पैसा देना है वह दे कर के इन मजदूरों की हड़ताल और धरने को

समाप्त करवाया जाए। इन लोगौं को पूरे पैसे की अदायगी की जाए। आज मैं अपने श्रम मंत्री महोदय से दर्खास्त करूंगी कि उस पैसे को जल्दी से जल्दी प्रावधान करवाएं। यह तो परम्परा है कि पैसा पहले दे दिया जाता है और उसकी मंजूरी हम से बाद में ले ली जाती है इसलिए इस चीज को सदन में रखन की जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन मजदूरों का जो बरेनस और पुरानी तनखाह रूकी पड़ी है उसकी अदायगी की जाए ताकि हम वास्तव में रम हित कर सकें। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय सो ाल वैल्फेयर की दो डिमांडज है मैं इन दोनों डिमांडों के बारे में कुछ खास नहीं कहूंगी। इनमें से एक तो 8 लाख 86 हजार रूपए की इंटेगरेटिड चाइल्ड डिवैल्पमैंट स्कीम है और एक 8 लाख 86 हजार रूपए की ग्रुप इं ाोरेंस की स्कीम है। इनके बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगी और भाायद समाज कल्याण मंत्री जी ने भी इस बात को देखा हो कि हमारे यहां एक पैं ान स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत जो विधवाएं होती है, जिन लोगों का कोई वाली–वारिस नहीं होता उनके लिए पैं ान का प्रावधान किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय पहले यह पैं ान 25 रूपए महीना दी जाती थी लेकिन बाद में बढ़ा कर यह 50 रूपए कर दी गई लेकिन यह नहीं देखा गया कि अगर 25 रूपए दिए जाते है तो वह 500 आदमियों को मिलेंगे और 50रूपये कर दिए जाएंगे तो वह 250 आदमियों को मिलेंगे। इसलिए इन्होंने पैं ान की अगर रकम बढ़ाई है तो उसके साथ–साथ टोटल रकम को भी बढ़ाएं ताकि वह रकम उतने लोगों को ही मिल सके। मैंने खुद समाज

कल्याण मंत्रालय का भार संभाला था और देखा था कि 800 से भी ज्यादा एप्लीके ांज ऐसी पड़ी है जो मंजूर भाुदा है लेकिन उनको पैं ान नहीं मिल रही है अब आप यह देखें कि एक आदमी जब अपनी एप्लीके ान देता है तो सरकार की स्कीम को सामने रख कर देता है। अर्जी मंजूर होने के बाद पावती की रसीद आ जाती है और उसको लिख दिया जाता है कि तुम्हें पैं ान दे दी जाएगी। यह सूचना पाकर वह सरकार का बड़ा गुण्गान करता है कि उसे सरकार से पैसा प्राप्त होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है वह दो–दो, तीन–तीन साल तक प्रतीक्षा करता रहता है लेकिन उसक कोई पैसा नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया है, आप समाप्त करें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैं बोलते समय सदन के समय का पूरा ध्यान रखती हूं और सारा सदन इस बात को जानता है कि मैंने कोई प्वायंट ऐसा नहीं कहा जिसको दोहराया गया हो। मैं कह रही थी कि एक आदमी जिसकी अर्जी मंजूर हो जाती है, उसको पैं ान मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिलती। मैं श्रम मंत्री से गुजारि ा करूंगी कि इनके लिए जल्दी से जल्दी पैसे का प्रावधान करें और जो अर्जिया मंजूर पड़ी है उनका भुगतान फौरी तौर पर करने का प्रबंध करें।

इसके अतिरिक्त मांग संख्या 25 के अन्तर्गत सरकार ने डेढ़ करोड़ रूपया मिल मालको ं को ऋण के तौर पर दिया ताकि वे गन्ना उत्पादकों के पैसे की अदायगी कर सकें। जनता सरकार के आने के बाद, सरकार ने गन्ने का भाव साढ़े 13.50 रूपए नियत किया था और यह जानकर किसान को बड़ी भारी खु ाी अनुभव हुई थी कि उनको गन्ने का मूल्य अधिक मिलेगा लेकिन बाद मैं उनके चेहरे पर निरा ाा के चिन्ह आ गए क्योंकि उनकी सारी की सारी पेमैंट आउटस्टैंडिंग हो गई। मिलों के पास देने के लिए पैसा नहीं था। मुझे यह जानकर खु ाी हुई कि हमारी सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए डेढ़ करोड़ रूपए का ऋण मिल मालिको ं को देने का प्रावधान किया। अगर सरकार किसान के कश्ट का निवारण करने के लिए पूरी की पूरी रकम की अदायगी किसानों को कर देती तो मुझे और खु ाी होती और किसान जो निरा ाा के वातावरण में चल रहे है उसका समाधान होता।

कामरेड भांकर लाल(सिरसा): डिप्टी स्पीकर साहब, सदन में जो चर्चा चल रही है और जो मामला जेरगौर है, उस पर मैं एक दो बातें ही कहना चाहूंगा। आज ि ाक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। मैं आपको सिरसा की मिसाल देना चाहता हूं। सिरसे में काफी प्राइमरी स्कूल ऐसे है जिनमें बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, दरखतों के तले स्कूल लगता है। यह एक बहुत बड़ी मिसाल है जो यह बताती है कि स्कूलों की क्या

दुर्द ाा है। सिरसे की रेलवे कालोनी के पास, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है और डाकखाना है, उसके पास एक प्राइमरी स्कूल मंजूर हो चुका है, मास्टर लोग तन्खाह लेते है लेकिन बच्चे दरख्तों के नीचे बैठते है, एक पीपल के पेड़ के नीचे स्कूल लगता है। सरकार को फौरी तौर पर ऐसे स्कूलों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि घग्घर नदी के नजदीक कुछ गांव है। इन गांवों में मिडल स्कूल है, पांचवीं तक प्राइमरी स्कूल है। इन गांवों के बच्चे ि ाक्षा के लिए एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकते। तकरीबन तीन–चार महीने तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, ि ाक्षा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि घग्घर नदी का पानी भर जाता है। मिसाल के तौर पर मल्ला गांव है, अली का गांव है, झोल नली है, अहमदपुरियां है, इनसे कोई बच्चा दूसरी जगह पर ि ाक्षा लेने के लिए नहीं जा सकता, चाहे बच्चे पांचवीं में पढ़ते हो, चाहे आठवीं में पढ़तें हों, चाहे कालेज मैं पढ़ते हों, वे तीन–चार महीनें कहीं नहीं जा सकते क्योंकि घग्घर नदी का पानी जोरों पर रहता है। वहां पर कोई भी स्कूल अप–ग्रेड नहीं हुआ, कोई सड़क भी नहीं जाती क्योंकि आज तक कोई सड़क नहीं बनाई गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि सड़क जल्दी से जल्दी बनाई जाए। सी0एम0 साहब चौधरी देवी लाल जी इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते है, इन्होंने खुद इन गांवों में इलैक ान लड़ा है। चौधरी देवी लाल का हलका है वह मेरे

हलके के साथ लगता है, इनको खुद पता है कि आजकल इन गांवों के बच्चे घग्घर नदी पार करके स्कूल नहीं जा सकते, उनकी पढ़ाई बंद रहती है। धनूट गांव के बच्चे बाहर नहीं जा सकते, रास्ता बहुत खराब है, चारों तरफ पानी ही पानी भरा पड़ा है। सिरसा भाहर के अन्दर स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं है, पीपल के दरख्त के नीचे स्कूल लगता है। मैंने यह बात इसलिए बताई कि हमारी ि ाक्षा आज अधूरी है और सरकार पूरी तरह से इस पर काबू नहीं पा सकी है। अगर सही मायनों में बच्चों को ि ाक्षा देनी है तो सरकार वहां पर पक्का रोड़ बना दे ताकि बच्चे स्कूल आ जा सकें। ऐसा करने से घग्घर नदी के पानी सै स्कूल के बच्चे बच सकते है और उनके लिए आने जाने के साधन हो जाएंगे और ि ाक्षा हासिल कर सकेंगे।

तीसरी बात यह है कि सिरसा के अंदर एक प्राइवेट कालेज हैं। जब तक सरकार उस कालेज को अपने अंडर नहीं लेगी तब तक उसका सुधार नहीं हो सकता। उसका इन्तजाम, उसमे टीचर्ज को तन्खाहैं देने का तरीका बड़ा गल्त है, जब तक सरकार इसको अपने हाथ मैं नहीं लेगी तब तक इसमें ि ाक्षा का तरीका ठीक नहीं हो सकता। टीचर्ज को तन्खाह तीन–तीन महीने तक नहीं मिलती। प्राइवेट कालेजिज का सारे हरियाणा में यही हाल है। प्राइवेट कालेजिज की मैनेजमैंट कमेटी बनी हुई है, ट्रस्ट बने हुए है लेकिन उनमें झगड़े होते है और इसी वजह से बच्चे पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पाते। इसलिए मेरी सरकार से

प्रार्थना है कि जहां सरकार ि ाक्षा के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च कर रही है वहां इन प्राइवेट कालेजिज को अपने अंडर लेने के बारे मैं भी सोच विचार कर ताकि ि ाक्षा का स्तर ऊंचा हो सके।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बढ़िया स्कूल्ज है, माडल स्कूल है, उनमैं अमीरों के बच्चें, आफिसरों के बच्चे पढ़ते है और ये स्कूल भाहरों के अन्दर ही होते है। सरकार उन स्कूलों को बंद करे। उन स्कूलों में बराबरी का, समानता का दर्जा होना चाहिए। स्कूल मैं पढ़ाई समानता की होनी चाहिए। एक गरीब हरिजन का बच्चा, एक मंत्री का लड़का, एक सेठ का लड़का और बड़े कारखानेदार का लड़का उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए और उनकी ि ाक्षा एक होनी चाहिए, बैठने का तरीका एक होना चाहिए। उनको अच्छा बनाने के लिए, बैठने के लिए टाट बोरी देने के लिए डैस्क देने के लिए, प्राइमरी स्कूलों के अंदर सरकार पैसा खर्चें। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। (विघ्न) मैं ज्यादा न कहते हुए इतनी बात कहूंगा कि आज के जमाने में जो हमारी ि ाक्षा का तरीका है वह समानता का हो और ि ाक्षा के ऊपर पैसा समानता से खर्च हो।

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्षः श्री फतेह चंद विज।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। यह सै ान तीन

दिन का है। दो दिन हो चुके है, एक दिन बाकी है लेकिन अभी तक हमें टाईम नहीं मिला। मेरा ऐसा विचार है कि भाायद टी0 ए0, डी0 ए0 लेकर हम ऐसे ही चले जाएंगे।

श्री उपाध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं हैं लेकिन इनके बाद आपको टाईम मिलेगा।

चौधरी लाल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अगर आप टाईम दें तब तो बैठें वरना कोई और काम करते है।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री फतेह चंद विज(पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट के खर्च करने के लिए मांग 16 और 25 में जो पैसा मांगा गया है मैं उसकी सराहना करता हूं। क्योंकि एक अच्छे काम के लिए सरकार पैसा मांग रही है।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुर ाीद अहमद पदासीन हुए)

चेयरमैंन साहब, हम सबको पता है कि हमारी सरकार ने देहात की जिन्दगी को ऊपर उठाने के लिए, देहात में पढ़े लिखे बच्चों और जो बच्चे किसी वजह से पूरी तरह पढ़ लिख न सकें यानी थोड़े पढ़े हुए है, उन्हे बेरोजगार बनाने के लिए देहात में इंडस्ट्रीज फैलाने का एलान कर रखा है और सरकार ने इसके

लिए खुद भी लोन दिया है तथा बैंकों से भी लोन दिला रही है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि देहात के बच्चे जो सर्विस मैं नहीं लिए जा सकते वे अपना कारोबार भुरू करके अपने परिवार का और अपना पेट पाल सकेंगे लेकिन सरकार को मैं एक सुझाव जरूर दूंगा। हमारे बच्चे एक–एक या दो–दो मिल करके इंडस्ट्रीज लगा तो लेंगे लेकिन जब तक उनके उत्पादन की सेल का कोई साधन नहीं होगा, जब तक कोई ऐसा आर्गेनाईजे ान नहीं होगा जो उनके तैयार किए हुए माल को बेच सके तब तक यह काम फायदेमंद नहीं होगा। वे बच्चे आहिस्ता–आहिस्ता, जो रूपया आप देंगे या बैंको ंसे लोन दिलाएंगे उसे वापस करने की हैसियत में न होने के कारण, क्योंकि जो माल वे तैयार करेंगे वह न बिकने के कारण स्टॉक होता जाएगा, मजबूर होकर वे गांव से भागेंगे। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप ऐसा सैल कायम कीजिए, आर्गेनाइजे ान कायम कीजिए, जो उनके माल की सेल कर सके। तब तो इसका फायदा है वरना जैसे दूसरे लोगों की कई जगह भाहरों में भी और देहातों मैं भी इंडस्ट्रीज फेल हुई है वे भी फेल होंगी।

चेयरमैन साहब, एजुके ान डिपार्टमैंट के बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि भाहरों के अन्दर बहुत से प्राइमरी और मिडिल स्कूल म्यूनिसिपल कमेटीज के पास है। ये जिस वक्त पार्टि ान हुई इवैक्यू प्रोपर्टी के मकानों को किराए पर लेकर भुरू किए गए थे। किसी स्कूल का किराया दस रूपये है और किसी

का पंद्रह रूपये है। कई जगह तो लोग उन मकानों को खाली कराने के लिए कोर्ट में गए है।

श्री सभापतिः कृपया एक ख्याल रखिए कि यह यूनिवर्सिटी एजुके ान की डिमांड है और आप इसे प्राइमरी एजुके ान पर ला रहे है।

श्री फतेह चंद विजः कई जगह तो देखा गया है कि लोग बारि ाों का फायदा उठा कर मकानों पर चढ़ ताजे है और उनकी छतों की मिट्टी उखाड़ते है ताकि बच्चे वहां से निकले और वे अपना मकान ज्यादा किराए पर चढ़ाएं या बेचे। चूंकि सरकार के लिए इतने नये स्कूल बनाना मु कल होगा इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यह इस प्रोपर्टी को ऐक्वायर करके अपने कब्जे में ले लें और उन स्कूलों की मुरम्मत करा के बच्चों के बैठने योग्य बनाए। मुझे आ ाा है कि एजुके ान मिनिस्टर साहब इस तरफ जरूर ध्यान देंगे। बस इतना कह कर मैं अपना स्थान लेता हूं।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

(इस समय बहंत से सदस्य सदन में बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्षः श्री लहरी सिंह।

श्री लहरी सिंह मेहरा (रादौर अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय–

चौधरी गंगा रामः अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी यह कह कर गए है कि विज साहब के बाद मुझे समय मिलेगा। मैं दस दफा बोलने के लिए खड़ा हुआ परन्तु मुझे समय नहीं मिला। मैंने डिप्टी स्पीकर साहब से यही प्रार्थना की थी। अब चूंकि आप चेयर पर बैठें है इसलिए मुझे आप से फिर निवेदन करना पड़ेगा कि मुझे बोलने का टाईम दिया जाएं।

श्री अध्यक्षः अगर डिप्टी स्पीकर साहब, यह प्रोमिस कर गए थे तब तो पहले आपको टाईम मिलेगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः अब तो आप मुझे खुद कह चुके है।

श्री अध्यक्षः चूंकि डिप्टी स्पीकर साहब इनसे प्रोमिज कर गए है इसलिए आप पहले इन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री लहरी सिंह मेहराः अब तो मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ी सी सैक्रीफाइस कर दीजिए। अभी आप इनको पांच मिनट बोलने दीजिए उसके बाद आप बोल लेना।

श्री लहरी सिंह मेहराः बहुत अच्छा जी।

.....

आधे घंटे की चर्चा तथा विवाद बंद करने के लिए समय बदलने संबंधी अध्यक्ष महोदय का निरूपण

Mr. Speaker: After the voting on the Demands for Supplementary Estimates there will be half-an-hour discussion on the construction of roads in general and village apprach roads in particular. If the House agrees, I will apply the guillotine at 5.30 p.m. instea of 6 p.m.

श्री लहरी सिंह मेहराः आप आधा घंटा समय बढ़ा लें।

श्री अध्यक्षः अगर हाउस टाईम ऐक्सटैंड करना चाहता है तो वह हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि गिलोटींन साढ़े पांच बजे लगनी चाहिए तो वैसा कर लेंगे। (विघ्न)

श्री बलदेव तायलः ऐनफ डिस्क ान हो चुकी है।

श्री अध्यक्षः अगर एनफ डिस्क ान हो चुकी है तब तो इस डिस्क ान पर गिलोटींन साढ़े पांच बजे लग जाएगा।

आवाजेंः ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः उसके बाद आधे घंटे का डिस्क ान रोडज के बारे में होगा।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे उसके जवाब के लिए तैयारी कर लें।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनराम्भ)

चौधरी गंगा राम (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड नं0 16 पर अपने विचार रखूंगा। मैं पहले तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इसने पिछड़े हुए इलाके, जिसको तीस साल तक किसी सरकार ने नहीं सम्भाला था, का ख्याल किया है। ऐजुके ान और इंडस्ट्री के लिहाज से गोहाना पिछड़ा हुा इलाका था। वहां इस सरकार ने आई0टी0आई0 की स्थापना की। इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन इस साल इसमे दाखिले में जो कमियां रही है उन्हें भी मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई0टी0आईज0 देहात में इसलिए खोले जाते है ताकि देहात के लड़के इनमें एडमि ान लेकर अपना रोजगार चलाएं क्योंकि वे सबसे ज्यादा बेरोजगार होते है लेकिन इस बार जो मैरिट लिस्ट बनी थी उसके लिहाज से 40 परसैंट देहात के लड़के भी नहीं आ सके क्योंकि रोहतक, जींद और दिल्ली के काफी पढ़े लिखे लड़कों ने भी वहां पर ऐप्लाई कर दिया था। इसलिए मैं चाहूंगा कि आई0टी0आइज0 वगैरा में या जितने भी टैक्निकल ऐजुके ान के कालेज है उनके लिए जब कभी भी मैरिट लिस्ट बनें उसमें देहात के 80 परसैंट लड़कों की मैरिट लिस्ट अलग से बननी चाहिए और भाहरों के 20 परसैंट लड़कों की मैरिट लिस्ट अलग से बननी चाहिए तभी देहात को

उनके अन्दर रिप्रैजैन्टे ान मिल सकता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि इस समय आई0टी0आइज0 में जो 20 परसैंट रिजर्वे ान हरिजनों के लिए और 5 परसैंट रिजर्वे ान फौजी भाइयों के लिए रखी गई है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन इसके बारे में एक बात जरूर में हरियाणा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। हरियाणा सरकार ने कुछ महीने पहले ऐलान किया था कि बैकवर्ड क्लासिज की **(17.00 बजे)** रिजर्वे ान दो परसैंट से पांच परसैंट कर दी गई हैं। लेकिन आज तक उसकी नोटिफिके ान या इतलाह किसी भी कालेज या किसी भी संस्था मैं सरकार की तरफ से नहीं गई है। अब जितने भी दाखिलें हुए है वे चाहे मैडिकल कालेज में हुए है, या एजुके ान कालेजिज में हुए है या आई0टी0आई0 में हुए हैं सभी में दो परसैंट के लिहाज से हुए है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि पांच परसैंट बैकवर्ड क्लासिज के लिए जो रिजर्वे ान की गई थी उसकी इतलाह सभी संस्थाओं में जानी चाहिए और उसी के हिसाब से पांच परसैंट उनको सीटें मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर महोदय भी यहां पर बैठे हुए नहीं है लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी कारखाना नहीं है, दस्तकारी नहीं। यह इलाका हमे ाा फ्लड से डूबा रहता है, बरबाद होता रहता है। वहां पर न खेती होती है, वहां के लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे है। इसलिए मैं आपके जरिये मिनिस्टर महोदय से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वहां पर भी

कोई नयी दस्तकारी लगाई जाए और नयी इंडस्ट्री लगायी जाए। नयी इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाई जानी चाहिए जहां पर फ्लड के कारण लोगों को नुकसान हुआ हो, रोटी रोजी का कोई साधन न हो ताकि उन गरीब लोगों को उन कारखानों में रोजगार मिल सके।

इसके बाद में डिमांड नं09 जो ऐजुके ान के विशय में है, उस पर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी को 65 लाख रूपया दिया गया है। मुझे इस डिमांड को देख कर बड़ा ताज्जुब और दुख हुआ कि हरियाण सरकार सबसे ज्यादा पैसा महर्शि दयानंन यूनिवर्सिटी को दे रही है। यह पैसा कहां खर्च किया जा रहा है, किस तरह से खर्च किया जा रहा है उसके बारे में हरियाणा सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपके जरिए सदन के नोटिस में नाना चाहता हूं कि पीछे दस लाख रूपये का यूनिवर्सिटी ने फर्निचर खरीदा परन्तु उसकी सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई चैकिंग नहीं हुई। किस फर्म से वह फर्नीचर खरीदा गया, कहां से रसीदें बनवायी गइ, सरकार की तरफ से कोई चैकिंग नहीं की गई। लाइब्रेरी की किताबें और कितने ही लाखों रूपये का दूसरा सामान खरीदा गया परन्तु कोई हिसाब नहीं पूछा गया। मैं किसी इन्डीविजुअल आदमी को नहीं कहता हूं। मैं यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूं। सरकार पैसा देती है तो उस पैसो पर सरकार का कंट्रोल भी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की परचेज कमेटी है उसमें सरकार का भी

नुमाइंदा होना चाहिए। वैसे ही करोड़ों और लाखों रूपया उसको दे दिया जाए और उसका मिस–यूज होता रहे, कोई चैकिंग न हो तो इस प्रकार से जनता का पैसा बरबाद होता है।

इसके प चात् मैं एग्रीकल्चर पर आना चाहता हूं। आज के दिन सबसे ज्यादा जोर हरियाणा में खेती पर देना चाहिए। पिछले दिनों ओलों के कारण काफी एरियाज में खेती बरबाद हो गई लेकिन उन गरीबों को उस फसल का कुछ भी मुआवजा नहीं मिला। हिन्दुस्तान के अन्दर सभी सरमायदारों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए एक प्रोविजन है कि अगर उनका कारखाना खत्म हो जाये या बरबाद हो जाये तो उसका सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है लेकिन किसान की खेती बरबाद हो जाती है तो उनको लोन दे दिया जाता है या उसका मालिया सस्पैंड कर दिया जाता है उसकी बाद में रिक्वरी की जाती है लेकिन किसान को किसी प्रकार की ग्रांट नहीं दी जाती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर हरियाणा के किसान को एक करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है तो उसको मुआवजा दिया जान चाहिए। या ग्रांट दी जानी चाहिए। किसान को जो भी इस प्रकार से पैसा दिया जाता है उसकी रिकवरी नहीं की जानी चाहिए।

इसके बाद डिमांड नं013 जो सो ाल वैलफेयर एंड रिहैबलिटे ान की है, इसके अन्दर बच्चों की भलाई के लिए पैसा लगाया जाता है। देहातों में वैलफेयर सैंटर खुले हुए है लेकिन

मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो पैसा उनके लिए आता है उसमें से तीस परसैंट भी पैसा उनकी भलाई पर नहीं लगाया जाता है। उस पैसे का मिस–यूज होता है उस सैंटर्ज के अन्दर कोई प्रैसक्राइब्ड खुराक नहीं है, उसके लिए खेलने का सामान दे दिया, वहां पर कोई झूला लगवा दिया, लेकिन उनकी सेहत के बारे में कोई ख्याल नहीं रखा जाता है उनकी पढ़ाई पर, उनकी खुराक पर और कपड़े पर वह पैसा नहीं लगाया जाता है इसलिए वहां पर सरकार को कंट्रोल होना चाहिए। यह सुनकर भी ताज्जुब हुआ कि वहां पर जितने भी इम्पलाइज लगे हुए है उनकी सर्विस की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे जिले सोनीपज में कथूरा ब्लाक में यह स्कीम चालू की गई है और अभी पिछले दिनों अम्बाला जिलें के ब्लाक में भी आरम्भ की गई है। यह स्कीम सैन्टर की तरफ से पांच साल के लिए लागू की गई है। पैसा भी सैंटर की तरु से आजा है। अब पता नही है कि यह स्कीम कितने दिनों तक चलेगी। जो वहां पर नौकरी करते है वे कितने दिनों तक वहां पर रहेंगे। इस बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। फर्ज करो कि ये सैंटर टूट जायें और ये ब्लाक खत्म हो जायें तो उनको कहां पर नौकरी पर लगाया जाएगा इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके बारे मे कोई प्रावधान किया जाये कि उनको कहां पर नौकरी दी जायेगी।

श्री अध्यक्षः गंगा राम जी आपका समय हो गया। आप खत्म करें।

चौधरी गंगा रामः आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो डेढ़ करोड़ रूपया भ्ागर मिल्ज को दिया है इससे काम नहीं चलता। हरियाण के अन्दर लाखों ऐसे किसान है जिनका पैसा दो दो साल से सरकार के पास पड़ा हुआ है। उसको लेने के लिए जमींदारों को कितने ही चक्कर काटने पड़ते है हजारों रूपसा तो उनका किराये पर लग जाता है, रि वत देने में लग जाता है। होना तो यह चाहिए कि जो किसान का पैसा ब्लाक पड़ा हे अगर तीस साल में मिलता है उस पर ब्याज मिलना चाहिए। यहां तो यह पेाजी ान है कि ब्जयाज तो दूर रहा उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। कितने ही करोड़ों रूपया हरियाणा के मिलों ने किसानों को देना है। मिल से पैसा न मिलने के कारण वे अपना खर्च भी नहीं चला पा रहे है। पैसा न मिलने के कारण कितने ही धरने रखे गए लेकिन फिर भी कोई पैसा नहीं दिया गया। यह जो डेढ़ करोड़ रूपया रखा है यह बहुत थोड़ा है, यह चार करोड़ होना चाहिए। इस सरकार का पहला ध्येय है किसानों कि भलाई की जाए। दूसरी सभी चीजों को छोड़कर किसानों को पूरा पैसा दिया जाए। जितना पैसा किसान को ब्लाक पड़ा है उसका ब्याज मिलना चाहिए चाहे यह पैसा किसी भी मद से देना पड़े, किसान को जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त कीजिए, आपका टाईम हो गया है।

चौधरी गंगा रामः अभी समाप्त कर रहा हूं जी। अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे दे ा के अन्दर आजकल रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान की बात चल रही है। रूलर इंडस्ट्रीज के लिए जो रजिस्ट्री वगैरा करानी पड़ती है उसके लिए जो रजिस्ट्रे ान फीस लगती है, वह माफ करने के लिए सरकार यहां से कुछ पैसा मांग रही है। मैं इस बारे में एक बात कहता हूं कि सरकार रजिस्ट्रे ान फीस को माफ करने के लिए जो पैसा मांग रही है, इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह पैसा जो दिया जा रहा है यह एक मद से निकाल कर दूसरी मद में डाला जा रहा है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि यह पैसा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की मद से, जिनके अधीन छोटी–छोटी इंडस्ट्रीज लगनी है, न निकाल कर हैवी इंडस्ट्रीज की मद से दिया जाए। इन भाब्दों के साथ स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आने समय दिया और यह कहना चाहूंगा कि हम सब इस बात पर गौर करें कि यहां पर खाली बातें कह देने से काम नहीं चलेगा। अन्त में मैं इतना कहूंगा कि जो एक दो बातें मैंने किसानों की भलाई के बारे में कहीं है, उनको सरकार को मान लेना चाहिए।

श्री लहरी सिंह मेहरा(रादौर–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं 5 मिनट से ज्यादा टाईम नहीं लूंगा। सबसे पहले तो मैं ि ाक्षा की डिमांड पर बोलना चाहता हूं। जो ि ाक्षा की

हालत आज हरियाणा के अन्दर है, वह आपकी आंखों से भी छिपी हुई नहीं है। हमारे यहां जो छोटे–छोटे स्कूल हैं, प्राईमरी स्कूल है, मिडल स्कूल है, या हाई स्कूल हैं, उनमें आप जाकर देखिये। मैं यह कहता हूं कि 90 प्रति ात सकूल ऐसे है जिनमें कि बिल्डिंगें टपकती है। बिल्डिंगें ऐसी है कि जिनमें बच्चे बैठ नहीं सकते। मेरे हल्के रादौर के अन्दर तो कम से कम 50 प्रति ात स्कूल ऐसे होंगे जिनमें बच्चे बैठ भी नहीं सकत। अगर बरसात होती है तो वे घरों को चले जाते है और वैसे भी बच्चे स्कूलों में बैठ नहीं सकते क्योंकि जो बिल्डिगें है वह टपकती है। जो यहां पर 65 लाख रूपये की यूनिवर्सिटी के लिए अनुपूरक मांग रखी गयी है, गवर्नमैंट की ओर से, यह मैं समझता हूं कि एक नाजायज मांग है क्योंकि यूनिवर्सिटीज को ग्रान्अस देने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें हमारे दे ा के बच्चे बनते है, दे ा का भविश्य बनता है, उन बच्चों को पढ़ने के लिये, उन बच्चो की बेहतरी के लिये, उनके स्वास्थ्य के लिये, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। यह एजुके ान डिपार्टमैंट की तरफ से एक ज्यादती है कि एग तरफ तो उन बच्चों के स्कूलों के लिये बिल्डिंगें नहीं, अगर है तो वे चूती है, दूसरी तरफ उनके बैठने के लिये फ र्ा भी नहीं है और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज तक कोई भी टीचर किसी भी स्कूल में नहीं गया, मंत्री जी इसका कारण बतायें? हमें बड़ी भार्म आती है जब हम अपने हल्कों में जाते है, लोग कहते है कि आज तक कोई टीचर नहीं आया, क्या कारण है? टीचर न आने की वजह से जो

छोट–छोटे बच्चे है वे यह भी भूल गये है कि वे कौन सी क्लास में है। बच्चे आज यह भी नहीं जानते कि वे पहली में है, दूसरी में हैं, तीसरी में है या चौथी में है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां पर पिछले दो–तीन महीनों से कोई मास्टर नहीं है, वहां के लिये मास्टरों का इन्तजाम होना चाहिए। इसके लिये सरकार के पास अग फन्डज नहीं है तो जो यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट दे रहे हैं, वह ने दें लेकिन वहां पर टीचरों का प्रबन्ध जरूर होना चाहिए ताकि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल या मिउल स्कूल में पढ़ते है, और जो अपनी कक्षा ही भूल गये है, उनका कुछ भविश्य बनाना भाुरू कर दें। मेरी यह डिमांड है। इसके अलावा ऐजुके ान सिस्टम में हमें कुछ चेन्जिज अव य लानी होंगी। जितनी भी तबदीली आज तक टीचर्ज की ट्रांसफर पालिसी में आयी हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि हर टीचर यह चाहता है कि उसके घर में ही स्कूल खुल जायें। इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। जिस आदमी ने नौकरी करनी है उसमे ंनखरा नहीं होना चाहिए। उसकी एक जगह ड्यूटी लग गई तो उसे वह ड्यूटी पूरी करनी चाहिए चाहे उसे कहीं पर भी पोस्ट कर दिया जायें। उसने तो बच्चे पढ़ाने है, और बच्चे पढ़ाने भी चाहिए इसलिए इस बारे में हमें सख्त ऐक ान लेना पड़ेगा कि कोई भी मास्टर अगर उसको 3 मील भी इधर–उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है ो वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं दस एम0एल0ए0 लेकर मिनिस्टर साहब के पास पहुंच जाता है और अपनी बदली रूकवाने की पूरी कोि ा ा करता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें ऐक ान लेना

पड़ेगा। ऐक ान लेने के साथ–साथ हमें ि ाक्षा पद्धति में सुधार करना चाहिए। जब तक हमारी ि ाक्षा पद्धति में सुधार नहीं लाया जाता तब तक कोई बात नहीं बन सकती। इसके साि ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां मिडल स्कूल है या हाई स्कूल है, उनमें कई ऐसे स्कूल है जिनमें साईन्स पढ़ाने के लिये वहां पर टीचर्ज नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिये जब तक साईंस मास्टरों का प्रबन्ध नहीं हो जाता, तब तक वह कैसे पढ़ सकेंगे। जब बच्चे स्कूलों में साईंस नहीं पढ़ सकेंगे, तो ऐग्जाम क्या देंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि जिस विशय के भी टीचर्ज स्कूलों मैं नहीं है, उनका इन्तजाम होना चाहिए और हमारी ि ाक्षा की पद्धति एक अच्छी पद्धति होनी चाहिए ताकि जो हमारे पढ़े हुए बच्चे वहां से निकलैं वे एकेडेमिक तौर पर ही नहीं टैकनीकल तोर पर भी ट्रेंड होन चाहिए। इसके बाद आजी है दूसरी डिमांड रोजगार की। रोजगार के बारे में जो हालत है वह आपको खुद को पता है। रोजगार की क्या हालत है आप इसका अन्दाजा इस बात से लगा सकते है कि कुरूक्षेत्र जिले में 40 वैकेन्सीज निकली है ओर वहां पर 10–12 हजार एप्लीके ान्ज आयी हुई है। आप देखिये बेरोजगारी की यह हालत है। इसके लिये मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जां हन्होंने दो आई0टी0आईज0 खोली है, एक गोहाना में और दूसरी सिरसा जिले में खोली गयी है, यह एक बहुत अच्छी बात है। हम सब इस बात के लिये मुबारिकबाद देते है कि अगर इस प्रकार के सरकार कदम उठायें तो यह समस्या कुछ हद तक हल हो सकती

है। हमारे बच्चे यहां पर ट्रेनिंग लेकर जायें और दस्तकारी भाुरू कर सकते है और अच्छे दस्तकार बन सकते है। इस तर से वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते है और वहां पर ाीखा हुआ काम कर सकते है। इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है। मैं यह चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये और बेरोजगारी खत्म करने के कलये दो आई0टी0आईज0 खोलने का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि हर सब–स्टे ान पर बच्चे ट्रेनिंग ले जायें और वहां से निकल का रूरल इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। इसके अलावा यहां पर यह बात भी कही गयी कि हम रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज खोल रहे है। रूरल इंडस्ट्रीयलाइजे ान के तहत हम जो यूनिट रूरल एरियाज में खोल रहे है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे आदमी है जिन्हें ये यूनिट दिये गये है जोकि असली मजदूर वर्ग के है, गांव के रहने वाले है। जितनी भी नई यूनिट्स रूरल इंडस्ट्रियलाइजे ान के तहत दिये गये है, मेरे ख्याल में वे सारे के सारे भाहरी आदमी ले गये है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि उनहोंने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं जिससे कि यह नये यूनिटस गांव के आदमियों को मिल सकें। इसके बाद, स्पीकर साहब मैं यह कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त कीजिए, आपका टाईम हो गया है।

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। इस तरह से तो मेरी जरूरी बातें रह जायेगी।

श्री अध्यक्षः जरूरी बातें मत रहने दे।

श्री लहरी सिंह मेहराः समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो पैसा रखा गया है, उसका इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह पैसा हरिजनों या बैकवर्ड क्लासिज को मिलना चाहिए। इसके अलावा अपने काम धंधे भाुरू करने के लिये इसमें बहुत थोड़ा बजट है। इसके लिये अगर और ज्यादा पैसा रख देते तो कोई बात नहीं ाी और मेरा ख्याल है कि सारे मैम्बर उस को स्पोर्ट करते अगर आप समाज कल्याण विभग के लिए थोड़ा कम पैसा भी कर देते। मैं यह कहूंगा कि चाहे किसी भी प्रकार से किया जायें लेकिन हरिजन कल्याण निगम को और ज्यादा पैसा दिया जाये ताकि वह गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। इस बारे में सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए था कि जहां पर हरिजनों की चौपालें नहीं हैं वहां पर कैसे वे बनायी जायेंगी। मैं मुख्य मंत्री महोदय को आपके जरिये यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके लिये कोई न कोई सिस्टम बनाया जायें।

श्री अध्यक्षः चौधरी लहरी सिहं जी, चौपालों के लिये 10,000 रूपया पहले ही लीडर आफ दी हाउस ने अनाउन्स कर रखा है जिस गांव में भी चौपाल बनेगी, यह रूपया दिया जायेगा।

श्री लहरी सिंह मेहराः मैं यही चाहता हूं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा चौपालें बनाने में सरकार मदद करे।

वित मंत्री(श्री प्रीत सिंह): आज हाउस के अन्दर पहली इन्स्टालमैंट जो सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस की है, उसके ऊपर डिसक ान इुई और बहुत से आनरेबल मैम्बर्ज ने अपने विचार प्रकट किये। कुछ मैम्बर्ज ने कुछ प्वाएंटस रेज किए है और कुछ मैम्बर्ज ने कुछ डिमांडज की सराहना भी की है। इस सिलसिले मैं मैं जो यहां पर प्वांएटस रेज किए गए है उनका जवाब देने के लिए थोड़ा सा टाईम लूंगा। डिमांड नं0 8 के बारे में कुछ मैम्बर्ज ने एतराज किया कि इतने दिन के बाद इस डिमांड का पैसा क्यों मांगा गया है। इस संबंध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि यह पैसा जमीन के मालिकों को कंपेन्से ान का दिया गया था। जिन मालिको ंकी जमीन एक्वायर हुइ थी वे लोग कोर्ट में चले गए और वहां पर कोर्ट ने ज्यादा कंपेन्से ान देने के लिए उनके हक में फैसला किया। उस सिलसिले में यह पैसा दिया गया था। स्पीकर साहब, 1961 में जब ज्वाएंट पंजाब था उस वक्त ये जमीनें एक्वायर की गई थी। उसके बाद 1966 में हरियाणा बन गया और ज्यादा कंपेन्से ान देने के बारे में हाई कोर्ट का फैसला 1977 में हुआ था। यह डिकिटल अमाउंट थी। हाई कोर्ट के फैसले पर आनर करने के सिवा गवर्नमैंट के पास कोई चारा नहीं था।

अब मैं डिमांड नं0 9 के बारे में कहूंगा। डिमांड नं0 9 में 65 लाख रूपया महर्शि दयानंद यूनिवर्सिटी को दिया गया था। इसके बारे में काफी कुछ आनरेबल मैम्बर्ज ने ऐतराज उठाया है और बहुत से मैम्बर्ज ने इस किस्म के एतराज किए है कि इस यूनिवर्सिटी को इतना पैसा नहीं देना चाहिए जब कि हमारे स्कूलों की हालत इतनी खराब है। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रान्त यह नहीं चाहता कि जो उसके एतुके ानल इस्टीटयू ांज है उनका स्टैन्डर्ड गिरे बल्कि यह कोि ा ा की जाती है कि जो प्रान्त में एजुके ानल इंस्टीटयू ांज है उनको अच्छे सा अच्छा बनाया जाए, उनको अच्छी फैसिलीटीज दी जाएं ताकि जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वह ऊंचा उठे। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि इन यूनिवर्सिटीज का स्टैंडर्ड इस किस्म का न बनाया जाए कि वह अमेरिका या दूसरी यूनिवर्सिटियों से ज्यादा हो। मैं इस सिलसिले में बताना चाहता हूं कि जहां मैम्बरान और बड़े–बड़े आदमी कोि ा ा करते है कि उनके बच्चे कनवैंट स्कूलों या मॉडल स्कूलों मैं पढ़ने के लिए जाए क्या यह अच्छा नहीं होगा कि स्टेट के अन्दर ही कोई अच्छी युनिवर्सिटी हो जिससे उस स्टेट की जनता को अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के लिए अधिक पैसा खर्च न करना पड़े।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्र न है। जो कुछ मैंने या मेरे साथियों ने कहा था और जो विचार ि ाक्षा के बारे में रखे थे मंत्री महोदय उनको तोड़ मरोड़

कर पे ा कर रहे है। हमने यह नहीं कहा था कि वि वविद्यालयों का स्तर नीचे लाना चाहिए। हमने यह कहा था कि जब तक प्राईमरी स्कूलों का स्तर ऊंचा नहीं उठता तब तक वि वविद्यालयों पर अधिक पैसा खर्च न किया जाये। आज ज्यादा जरूरत प्राईमरी स्कूलों पर पैसा खर्च करने की है। अध्यक्ष महोदय, आप भी ि ाक्षा मंत्री रहे है आपके भी ऐसे विचार रहे है.....।

Mr. Speaker: This is no Point of Order, Swami ji. Kindly sit down and let the Minister continue his reply to the debate.

श्री प्रीत सिंहः मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। स्पीकर साहब, जहां तक स्कूलों की हालत के बारे में कुछ कहा गया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट इस प्रोबलम को अच्छी तरह से समझती है और काफी कोि ा ा कर रही है कि इस प्रौबलम पर काबू पाया जाए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस साल ऐजुके ान का जो ओवरआल बजट था उसमें इसी साल दस लाख रूपए ज्यादा का प्रोविजन किया गया है। जहां तक स्कूलों कि मरम्मत आदि का ताल्लुक है और इस बारे में बहुत सी जगहों से ि ाकायतें आई है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट के अंडर कंसीड्रे ान एक प्रोपोजल है कि एक स्पे ाल सैल ऐजुके ान डिपार्टमैंट के अन्दर खोला जाए जो स्कूलों की बिल्डिंग्ज की मेंटीनेंस का ध्यान रखें।

इसके अगली डिमांड आई0टी0आईज0 और आई0सी0डी0एस0 के बारे में हैं। यह वैलफेयर की डिमांड है। उसके बारे में काफी सदस्यों ने सराहना की हैं लेकिन कुछ मैम्बर्ज की भावना ऐसी रही है और उन्होंने कहा है कि ये पर्टिकुलर इलाके या पर्टिकुलर जगह पर खोलकर दूसरे इलाकों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। दूसरे इलाकों के साथ डिस्क्रिमिने ान किया है। इस किस्म की बात यहां पर कही गई है। मैं आनरेबल मैम्बर्ज को बताना चाहता हूं कि गवर्नमैंट अच्दी तरह से इस चीज को ध्यान में रखती है कि जिस इलाके की जैसी भी नसैसटी है उस नसैसटी के मुताबिक और फंडज की अवेलेबिलिटी के मुताबिक कोई भी डिवैल्पमैंट का काम कहीं रोका न जाए। उसे पूरा किया जाए। इस किस्म की धारणा कि उनके इाके के साथ डिस्क्रिमिने ान की गई है या उनके इलाके को इग्नोर किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हाउस को वि वास दिलाता हूं कि सरकार किसी भी इलाके के साथ कोई डिस्क्रिमिने ान नहीं करेगी। स्पीकर साहब, आखिरी टाईम डिमांड नं0 25 है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मजदूर, हमारे किसान जो बड़ी मेहनत के साथ खेती बाड़ी करते है उनकी जो कै ा काप्स या भूगरकेन है उसको उन्होंने तीन चार मिलों को गन्ना दिया। लकिन कुछ कारणों की वजह से गन्ने की मिल में घाटा होने के कारण मिल टाईम पर किसानों को पैसा नहीं दे सकी। इसलिए सरकार ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए डेढ़ करोड रूपया इस

डिमांड के अन्दर दिया है। स्पीकर साहब, मैं और ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि जितनी भी डिमांडज है वे सारी वैलफेयर के लिए है और जो भी काम हैं या जो भी डिमांड है जिन को पहले बजट में कंटेम्पलेट नहीं कर सके थे वे इसमें डाली गई है (व्यवधान) काप इं ाोरैंस के बारे में इसमें कुछ नहीं है। आगे जब कभी होगी तो भाामिल कर लेंगे।

Mr. Speaker: Now I will apply guillotine and put the various demands to the vote of the House.

Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 65,00,000 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 9-Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 1498.000 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 12-Labour and Employment.

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 17,72,000 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending

31st March, 1979 in respect of Demand No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 16-Industries.

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 10,000 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 1,72,100 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 20-Forest.

The motion was carried.

Mr. Speakera: Question is-

That a supplemenatary sum not exceeding Rs. 15000,000 be granted to the Governor of defray the charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March, 1979 in respect of Demand No. 5-Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

आधे घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब हाफ ऐन आवर डिसक ान होगा। अब मैं स्वामी आदित्यवे ा जी और श्री जगजीत सिंह पोहलू जी इस मसले पर बोलने के लिए कहूंगा।

आवाजें: स्पीकर साहब, सभी को बराबर का टाईम मिलें, इस बात का ध्यान रखा जाए।

श्री अध्यक्षः साहिबान, इस मसले के ऊपर, अगर आप सब साहिबान को मंजूर हो तो मैं कहूंगा कि हरेक मैम्बर को पांच–पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए।

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, जो मैम्बर पहले नहीं बोले है उन्हें पहले टाईम दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है, जो मैम्बर साहिबान पहले नहीं बोले है उनको सब से पहले बोलने का मौका दूंगा।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): अध्यक्ष महोदय, 4 जुलाई, 1977 से लेकर जून, 78 तक लगभग एक साल का समय बीत चुका है हमारी जनता सरकार को बने हुए, पर अभी तक सरकार की तरफ से सड़कों की तरफ कोई उचित ध्यान नहीं दिया गया हैं। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में कुछ सड़कों का निर्माण किया गया है

और लगभग 248 गांवों में सड़कों का निर्माण किया गया है, इसको हम मानते है। यह ठीक है कि अगर गांव की संख्या की दृश्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे सभी गांवों के साथ समानता का व्यचवहार किया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर सउ़को की लैन्थ को देखा जाए तो हमें घोर असमानता नजर आएगी। पीछे जो सवाल पूछा गया था वह सड़कों की लैन्थ के बारे मैं पूछा गया था उस बारे में आप को कुछ बता देता हूं कि केवल सिरसा जिला में 54 किला मीटर लम्बी सड़कें बनाई गई है और भिवानी में 35 किला मीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है। इस प्रकार हिसर जिले में 50–52 किलोमीटर सड़को का निर्माण किया गया है और भोश जो जिले बचे है उन सब को इग्नोर किया गया है। कहीं पर एक फर्लांग का टुकड़ा कहीं पर आधे फर्लांग का टुकड़ा और कहीं पर 100 गज का टुकड़ा जोड़ दिया गया है और कुछ वि ोश कार्य नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय हमारे हरियाणा में 1272 ऐसे गांव है जिन्होंने आजादी मिलने के बाद सड़क की भाक्ल तक भी नहीं देखी है और बरसात के दिनों में इन गांवों मैं पानी भर जाता है और फिर लोगों यह सूझता नहीं कि अग कहां से होकर बाहर निकला जाए लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरकार को लोगों की हालत का कोई अहसास तक नहीं होता है कि लोग कितना कठिन समय काट रहे होंगे। अध्यक्ष महोदय इसी प्रकार हमारा बल्लभगढ़ और पलवल का इलाका है, यमुना के साथ का खादर का इलाका है और लगभग वहां पर 100 गांव ऐसे है

जिन्होंने सड़कों की भाक्ल तक नहीं देखी होगी और उन इलाकों में बाढ़ के कारण अभी भी दो–दो, तीन–तीन फुट पानी गांवों में खड़ा है और वहां पर लोगों को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सिरसा, हिसार का जो इलाका है उस इलाके को सड़कों से लैस कर दिया गया है इसी प्रकार का पक्षपात पहली सरकार ने भी किया था। उस सरकार ने भी सारी सड़कों का निर्माण भिवानी और हिसार जिलों में ही किया भोश तकरीबन सभी इलाकों को इग्नोर कर दिया गया और मैं यह देख रहा हूं कि हमारी जनता सरकार है वह लोकतंत्र का ढिंढ़ोरा पीट रही है और कहती है कि हम सब के साथ न्याय करेंगे लेकिन आज कहां है वह न्याय? मैं यह सब बातें सच्चाई की ही बता रहा हूं। इसी प्रकार फिरोजपुर झिरका और नुंह का इलाका है वहां पर लोगों के रहने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां पर भी बरसात के कारण आना जाना लोगों के लिए दुभर हों जाता है लेकिन सरकार का इन सभी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वह सारा इलाका पिछले तीस सालों से सेम की समस्या के कारण खराब पड़ा हुआ है। हमारी बहु बेटियां जब दूर–दूर तक पानी भरने के लिए जाती है तो उनको काफी असुविधाएं होती है। पिछलें दिनों में हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उस इलाके का दौरा भी किया था और जब इन दिनों में उन्होंने उस इलाके का दौरा किया तो पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने सारी सड़कों की पैचिंग कर दी ताकि जब गाड़ी वहां से गुजरे तो कहीं गाड़ी को झटका न लग जाए, उसके बाद

क्या स्थिति हो जाती है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई मैटिरियल ही नहीं रहता है सब कुछ साफ हो जाता है इस प्रकार हम तो यह कहेंगे कि इस सरकार ने सड़कों के निर्माण में बड़ी बेइंसाफी से काम लिया है। अगर यह सरकार इसी तरीकें से चलती रही तो मैं समझता हूं कि इससे कुछ ही लोग राजी हो पाएंगें और इस तरह से सरकार चलेगी भी नहीं। कोई यह सोच ले कि मैं महान अधिकारी हूं बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति हूं और सरकार का सारा पैसा डाईवर्ट करके एक जगह लगा दूंगा तो याद रख ले कि आने वाले समय में एक या दो व्यक्तियों के जीत जाने से यहां पर जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, जब तक कि सारे हरियाणा का पूरी तरह से विकास नहीं होगा तब तक हम अपने इमेज को कायम नहीं कर पाएगें। मेरा एक सुझाव है कि जिन इलाको के मंत्री बने हुए है उन इलाकों को जहां पर कि जनता सरकार हारी है ताकि लोग खु ा हो और यह कहें कि जनता सरकार बड़ी अच्छी सरकार है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप समाप्त करें, आपका समय हो चुका है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, आप भी महेंद्रगढ़ क्षेत्र के रहने वाले है आपको भी सब बातों का पता होगा कि वहां पर भी कितनी सड़कें बनाई गई है। रात के समय अंधेरे में अगर एक आदमी पगडंडी भूल जाए तो अपने गांव में जाना उसके लिए मु कल हो जाता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह

कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इसी धीमी गति से चलती रही तो उसके लिए यह सब निभाना बड़ा मु कल हो जाएगा और चलाना भी दूभर हो जाएगा। इन भाब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): स्पीकर साहब, आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। हमारे मुख्य मंत्री महोदय चौधरी देवी लाल इस हरियाणा के निर्माता है और उन पर सारी हरियाणा की जनता को भरोसा था कि जब वे आये है तो अब वे पिछले 9 साल के राज को बदलेंगे पर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी लोगों को निरा ाा ही मिली है। चौधरी बंसी लाल जाकि पहली सरकार के मुख्य मंत्री थे, उस राज को सारे लोग कोसते रहे और उनके बारे मैं यह म ाहूर था कि वे अपने ही इलाके मैं सारा पैसा लगाते थे और हमारे चौधरी देवी लाल जी हमे ाा ही जुल्मों के खिलाफ लड़ते आए है और सारी उम्र अपोजी ान में ही बैठे लड़ते रहे और हरियाणा की तकलीफों के लिये जेलें भी काटते रहे। मुझे भी सौभाग्य से उनके साथ करनाल जेल में रहने का मौका मिला, उन्होने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ और दूसरा जत्था लाओ, मैं दूसरा जत्था लेकर आया (हंसी) फिर पहला राज बदला और अब हमें उम्मीद थी कि हमें इन्साफ मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बताता हूं कि कल भी यहां पर जो

सवाल डिसकस होता रहा वह सड़कों के बारे में था और आज भी जो सवाल डिसकस हुआ वह भी सड़कों से संबंधित था, इस बारे में मुझे पूरा संदेह है कि जो कागज तैयार किये गये, वे ठीक तरह से तैयार नहीं किये गये (हंसी) अब इस विभाग के वजीर भई मेहर सिंह जी राठी बने है, बड़े समझदार और सियाने आदमी हैं, श्री वीरेंद्र सिंह चले गये भाायद उन्हें पता लग गया कि आज डिसक ान होनी है (हंसी एवं भाोर) असली सड़कों के मालिक तो वे थे। स्पीकर साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, जो हमारे वजी साहब करते है, उन में से आधी बातों का पता तक नहीं हेता कि क्या हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के पास और बहुत काम है, कभी सैंटर से बात करनी होती है, कभी कोई दूसरे मसले उनके सामने होते है तो स्पीकर सापहब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जनता सरकार आने के बाद 228.18 किलोमीटर सड़कें हरियाणा में बनी हैं उनमें से 25 हलके ऐसे होंगे जिल मैं एक मुट्ठी का टुकड़ा भी नहीं बना होगा और सड़कों का वहां पर नामोनि ाान भी नहीं है, तारकोल तक भी नहीं बिछायी गई है। जो 228.18 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है, स्पीकर साहब, मैं आपको उनका अलग–अलग ब्यौरा देता हूं।

नारनोंद में 19.55 किलामीटर

रोड़ी में 17.82 किलोमीटर

ऐलनाबाद में 14.40 किलोमीटर

डबवाली में 12.93 किलोमीटर

दरबाकलां में 8.75 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है।

श्री अध्यक्षः पोहलू साहब, ये फिगर्ज तो हाउस के सामने पहले आ चुकी है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरा कहने का केवल मतलब इतना ही था कि यह तरफदारी तो बहुत ज्यादा हैं। पिछले सै ान ने आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने यह आ वासन दिया था कि सब हलकों में हरेक आईटम पर बराबर खर्च किया जाएगा, हम सारे के सारे चौधरी साहब के साथ है, सारा हरियाणा चौधरी साहब के साथ है। इसलिये स्पीकर साहब, पाई हलके मैं तो बिल्कुल एक ईंट भी नहीं डाली गई है। राठी साहब के पास जो दो गांवों के बारे में फिग्गर्ज है वे गलत है। मेरे हल्के में चार गांव बाकी रहते है जोकि मैटल्ड रोड़ से अभी जुड़े नहीं हैं। उन गांवों के नाम है राड़ा, खेड़ी सन्दल, सिसला और सिधा। मुझे जुबानी याद है इन चारों गांवों में सड़कें नहीं बनी है। राठी साहब ने जिन दो गांवों की फिग्गर बताई, वह गलत है। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। जैसे आनरेबल मैंबर ने अभी कहा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में चार गांव ऐसे है जिनमें सड़कें नहीं है। मैं यह

दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 50 गांव ऐसे है जिनमें सड़क नहीं है। हमारी सरकार का यह फैसला था कि गांवों को सबसे पहले सड़कें दी जाएंगी।

श्री अध्यक्षः यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है। आप त ारीफ रखिए, मैं आपकों बाद में बोलने के लिये टाईम दूंगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, ये सड़कैं जो बनती हैं ये बिल्कुल कमजोर बनती है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि पीछे जो कै ा प्रोग्राम सड़कों का चला था उसमें तकरीबन 90 प्रति ात सड़कें टूट चूकी है। यह हरियाणा के बच्चे बच्चे की आवाज है, आपके पास विजीलैंस है, सी0 आई0 डी0 है ये लोगों की आवाज सुन लें। लोग कहते है कि रोड़ इनस्पैक्टर से लेकर ऊपर तक परसैंटेज बंधी हुई है। जिल ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है उनके साथ परसैंटैज बंधी हुई होती है। इसलिय मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस परसैंटेज की बीमारी को खत्म करो, ठेके की बीमारी को खत्म करो। सरकार खुद काम करवाए और वह यह खुद देखे कि कितनी रोड़ी डाली जानी है और कितनी तारकोल डाली जानी है। अगर सरकार इस तरह से करेगी तो सौ परसैंट मैटिरियल डाला जाएगा। आज कल यह हो रहा है कि अगर किसी सड़क पर दस करोउ़ रूपए खर्च होने हैं तो मु ि कल से पांच करोड़ रूपए खर्च हो पाते है। जो सड़कें पिछलें राज में बनी थी आप उनकी इनक्वारी करवाएं उनमें सब में गड़बड़ हैं अगर अपने राज में भी

गड़बड़ चले तो यह बहुत बुरी बात है। इसलिये चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि ठेका सिस्टम खत्म किया जाए। अब एक वैट्रनरी अस्पताल मेरे भाई चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने देखा है और ठाकुर बीर सिंह जी के नोटिस में भी यह बात लाई गई थी। जखौली के सारे गांव ने यह ि ाकायत की थी कि हमने हस्पताल की बिल्डिंग के लिये पैसा दिया, वह बिल्डिंग बनी और महकमें अभी उसका चार्ज भी नहीं लिया था कि उससे पहले ही वह टूट रही है। इसी तरह से सारी सड़कों में भी गड़बड़ है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि जितने अफसर है, एम0एल0एज और मिनिस्टर्ज है आजादी मिलने के बाद के टाइम से इन सब की इनक्वारी करवाई जाए। मास्टरों को इस लिस्ट में न रखा जाए क्यांकि वे तो बिल्डर आफ दि ने ान है, बच्चों को पढ़ाने वाले है। बाकी सब महकमों की इन्कवायरी करवाओ। ऐसा करने से हरियाण का भला हो सकता है और जो परसैंटेज का पैसा लेकर नाजायज जायदाद बनाए बैठे है उन सब की जायदाद जब्त कर लो। ऐसा करने से हरियाणा का निर्माण जल्दी हो जाएगा। इसके बाद स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे हाउस में यह अ योरेंस दे दें कि सब हल्कों में बराबर बराबर सड़कें बनाई जाएंगी। धन्यवाद।

मास्टर ि िव प्रसाद(अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, सड़कों के बारे में ऐ साथी ने जो बताया कि पक्षपात होता है

इसमें कोई भाक नहीं कि पिछलें वर्शों में कुछ पक्षपात से काम चलाया गयां अकेले भिवानी जिले में 92 प्रति ात काम हुआ और सबसे कम अम्बाला जिला में काम हुआ। अम्बाला भाहर के हल्के में अगर देखा जाए तो वहां पर जीरो परसैंट काम हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अम्बाला जिला का आज तक यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके साथ सोतेली मां का सलूक किया जाता रहा है। बरसात के दिनों में इस जिले की तीन नदियों घग्गर, टांगरी और मारकंडा के बांध टूट जाते है और लोगों को एक जगह से दूसर जगह जाना मु कल हो जाता है। इस बार तो यह हालत हुई कि जो मेन सड़कें थी वे टूट गई। जैसे अम्बाला जगाधरी रोड़ है वह कई दिन तक बंद रही। इसी तरह से अम्बाला भाहर के साथ भी कई ऐसे गांव है जो बारि ा आने की वजह से आज बिल्कुल झील बने हुए है। इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन हल्कों में पिछलें डेढ़ वर्श के अन्दर एक इंच सड़क भी नहीं बनी और उसने साथ–साथ उन हल्कों की हालत भी बहुत खराब हो तो सब से पहले उन हल्कों में सड़कें बनाने में प्रायरिटी दी जाए उसके बाद दूसरे हल्कों की तरफ देखा जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं ।

श्री भागी रामः (एलनाबाद अनुसूचित जाति) अध्यक्ष महोदय, कल से यह चर्चा चल रही है कि सिरसा जिले में ज्यादा सड़कें बनी है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी एलनाबाद सिरसा जिले में ही हैं जिस में 78 गांव है। उन 78 गांवों में 50–55 गांव ऐसे है

जिलको आज तक कोई भी सड़क नहीं मिली है। जितना बरसात का पानी पहाड़ों से आता है वह सरा मेरी कांस्टीच्यूएंसी में जाकर इकट्ठा होकर आगे जाता है। इसलिए सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जिले डिवैल्पमैंट के कामों में सब से पीछे रहे है उनको प्रैफरैंस दिया जाए। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में एक बात और है कि वहां पर केवल चार हाई स्कूल और 5 मिडल स्कूल है जबकि दूसरी कई कांस्टीच्यूएंसी ऐसी है जिनमें यह दिक्कत आई कि कौन सी जगह हाई स्कूल खोलें क्योंकि उन में सब जगह हाई स्कूल है। इसलिये यह जो भेद भाव की भावना चल रही है यह खत्म होनी चाहिये। सिरसा को तो याहं पर केवल नि ाना बना रखा है जो कि नहीं बनाया जाना चाहिये। मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे समय दिया। यहां पर ज्यादातर सड़कों की चर्चा चल रही है क्योंकि.....

आधे घंटे की चर्चा का समय बढ़ाना

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारि ा है कि बहुत से मैंबर बोलना चाहते है, इसलिए हाउस का टाईम 15–20 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई सदस्यः बिल्कुल ठीक है, बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर आप सब साहबान चाहते है तो 15 मिनट का टाईम बढ़ा दिया जाता है।

आवाजें: ठीक है।

आधे घंटे की चर्चा (पुनराम्भ)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, यहां पर हर आदमी इस बात की कोि ा ा कर रहा है कि सरकार के खिलाफ किस तरह से बोला जाए। सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनको बताने की कोि ा ा कोई आदमी नहीं कर रहा। किसी चीज में दोनों बातें होती है, बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है, दोनों चीजों को बताया जाना चाहिए। सरकार की बुराई तो इन्होंने बताई है लेकिन अच्छाई नहीं बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने हमारे जिले के ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि इस वक्त अम्बाला जिले के तीन मिनिस्टर है और दो रिटायर कर दिए गए है। (व्यवधान) इनकी हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है और हमारे जिले को यह सब से बड़ी देन है जो इस सरकार ने दी है। जहां तक पानी का ताल्लुक है, चौधरी साहब ने बाहर से म ीनें मंगवाकर पानी मुहैया करने की कोि ा ा की.....

श्री अध्यक्षः आप सड़कों की बात कहें।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, सड़कों के बारे में मेरी मांग है कि जो सड़कें पिछली सरकार ने बनाई है उनकी इनक्वारी करवाई जाए कि वे कैसे कैसे बनी है, उन पर कितना खर्च हुआ है और आज उनकी हालत क्या है। इस पैसे को क्यों बरबाद किया गया, सड़कों के नाम पर लाखों रूपया क्यों खाया गया। इसकी इंक्वायरी करने के लिए एक सपै ान कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में मुझे जरूर मैंबर रखा जाए। ताकि मैं कमेटी के नोटिस में ला सकूं कि किस तरह से रूपये की बरबादी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब आप समाप्त कीजिए, आपका टाईम हो गया है। (व्यवधान)

(इस समय बहुत से मैंबर बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती भाकुन्तला भागवाड़ियाः स्पीकर साहब, श्री लाल सिंह जी ने बताया कि दो मिनिस्टर रिटायर हो गए है, दो नहीं तीन रिटायर हुए है, सुशमा स्वराज को ये भूल गए हैं..... (व्यधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए, अब चौधरी ई वर सिंह बोलेंग। (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे साथ जुल्म हुआ है (व्यवधान) अगर मुझे समय दिया है तो मुझे बोलने दिया जाए.... .....(व्यवधान) आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप त ारीफ रखिए।

चौधरी लाल सिंहः मेरे साथ धक्का न किया जाए।

श्री अध्यक्षः आप चैम्बर में आ जाए, जो कुछ आप कहना चाहते है, मुझे बता दे, आपके सारे प्वायंट नोट कर लूंगा। (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंहः आप मुझे दो मिनट दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाए चौधरी ई वर सिंह जी बोलेंगे।

चौधरी ई वर सिंह(गूहला अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, सिबर से हरनौला की सड़क सरकार ने मंजूर की है। इस पर सरकार ने ईंट गिराई और रोड़े बिछाए गए लेकिन अगली तारीख को ये उठा लिए गए.....(व्यवधान)

एक सदस्यः यह इलैक ान का टाईम तो नहीं था। (व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंहः टाईम इलैक ान का ही था। तो स्पीकर साहब, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि 34 किलोमीटर की रोड़ है जिसके आस पास गांव है। इन गांवों में से किसी भी गांव को इस रोड के साथ नहीं जोड़ा गया। गूहला–मारिया 5 किलोमीटर की दूरी पर है लोग पैदल चल कर आते हैं व्हीकल

चलने के लिए कोई सड़क नहीं है। इसके इलावा मजले और पे ावर गांव है जो पंजाब बार्डर के नजदीक लगते है और बाडर के नजदीक सड़क है। इन गांवों को इस रोड़ के साथ जोड़ दिया जाए तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। सरकार के प्रोग्राम के मुताबिक (बी) क्लास की सड़कों को गांवों के साथ जोड़ने का इरादा है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि 34 किलोमीटर के अन्दर जो गांव पड़ते है उन को इस रोड़ से जोड़ दिया जाए। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं रखी गई है, कागजात के अन्दर उनका किसी कैटेगरी में नाम नहीं हैं, उनको कागजात में लाया जाए। कुछ सड़कें ऐसी है जिन को बनाने के आर्डर कागजात में हो चुके है लेकिन अभी तक काम भ्रारू नहीं किया गया है। मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इन को (ए) क्लास में या (बी) क्लास में लाकर जल्दी काम भ्रारू किया जाए।

सड़कों के अलावा घग्गर पर पुल बनने की स्कीम है लेकिन यह स्कीम आज तक लागू नहीं हुई है और लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। 17.8 किलोमीटर का चक्कर काट कर लोगों को आना–जाना पड़ता है। तीन पुल और बनने है, सड़क तो बन गई है लेकिन पुल नहीं बने है। अगर सरकार इनको बना दे तो पंजाब में आने–जाने के लिए लोगों को सुविधा मिल सकती हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि इन पुलों का निर्माण किया जाए।

चौधरी हरिचंद हुड्डा(किलोई): स्पीकर साहब, मेरे किलोई हलके में तीन–चार लिंक रोड बननी है। अगर मैं आने गांव के लोगों की मदद से गवर्नमैंट को जमीन दिलवा दू और मिट्टी भी डलवा दूं तो सरकार मेरी क्या मदद करेगी? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं।

चौधरी खुर ीद अहमद(तावडू): जनाब स्पीकर साहब, आपने जो सड़कों के बारे में डिस्क ान भाुरू करवाई.....................
....

....

औचित्य प्र न

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी राम लाल वधवा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, हाफ एन आवर डिस्क ान है और रूल्ज के मुताबिक यह डिस्क ान हाफ एन–आवर तक ही रह सकती है, इससे ज्यादा टाईम नहीं ले सकते। इसके बाद मिनिस्टर साहब ने भी रिप्लाई देना है।

कई सदस्यः हाउस टाईम एक्सटैंड कर सकता है।

श्री अध्यक्षः The House is supreme and if the sense of the House is that that they want the discussion to be extended by 15 minutes, then I think there is no reason for stopping it.

18.00 बजे आधे घंटे की चर्चा (पुनराम्भ)

चौधरी खुर ीद अहमदः मैं दो मिनट में सारी बात कह देता हूं। जून, 1978 से लेकर अब तक जो सड़कें बनी है, वे 228.18 किलोमीटर बनी है। पांच हलके ऐसे है जिनमें 73.45 किलोमीटर बनी है.....

चौधरी संत कंवरः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, ये सारी बातें सप्लीमेंटरी क्वे चन्ज में आ चुकी है, इसलिये ये फिगर्ज न दी जाएं ताकि समय ज्यादा ने लगे और सारे मैम्बरों को बोलने के लिए टाईम मिल सके।

चौधरी खुर ीद अहमदः मैं यह बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यू ान कैसे हुआ, मैं फिगर नहीं बताऊंगा इलाके बताऊंगा। 5 हलकों में 73.45 किलोमीटर बनी है। इन हलकों के नाम अगर आप जानना चाहें तो ये हैः– नारनौंद, रोड़ी, एलनाबाद, डबवाली और दड़बा कलां। अगले आठ हलकों में 52.56 किलोमीटर बनी है जिन में कालका भाामिल है और कालका में 5.85 किलोमीटर सड़कें बनी है।

विकास मंत्री(श्री लछमन सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, यह फिग्गर बिल्कुल गलत है..... (व्यवधान)

चौधरी खुर ीद अहमदः मेरे पास फिगर्ज है, आप इन्कवायरी करवा लें। It is a strange thing that a Minister is challenging the Government's reply.

Mr. Speaker: All this has already come before the House.

चौधरी खुर ीद अहमदः 23 हलकों में 166.20 किलोमीटर सड़कें बनी है। बाकी 67 हलकों में 62.16 किलोमीटर सड़के बनीं है। इनमें से भी 25 हलके ऐसे है जिन में कोई सड़क नहीं बनी है। अगर डिसट्रब्यू ान का यही स्टैंडर्ड रखना है तो मैं समझता हूं कि बहुत से हलके इन पांच सालों में बगैर सड़क के, बगैर डिवैल्पमैंट के रह जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है किह हमारी सरकार के साथी हमको और इस हाउस के बाकी मेम्बरान को यह समझें कि हम सब एक ही कुनबा से है। इकट्ठे मिल कर ही राज बनता है, सिर्फ कैबिनैट का राज नहीं होता। इसलिए स्टेट के रिसोर्सिज के डिस्ट्रीब्यू ान मैं डिसिक्रमिने ान इतना ग्लेरिंग न हो जो मैम्बर्ज के लिए भौकिंग हो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। (विघ्न)

कैप्टन मांगे राम(झज्जर, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, अभी जो सप्लीमैंटरी ग्रान्टस का एप्रोप्रिए ान बिल पास हुआ है और जिसका बहुत से साथियों ने समर्थन किया है, इसकी मुझे बहुत खु ाी है लेकिन रोडज और फ्लड बगैरा का जो जिक हुआ है, उसके बारे में मैं भी अपने हलके झज्जर के संबंध में

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज भी वहां 43 गांव साहबी नहीं की लपेट में है। झज्जर से गुडियानी वाया सुबाना रोड टूट गई है जिसकी वजह से वहां बस भी नहीं चल पाती। इसको जल्दी से रिपेयर करा कर ट्रैफिक चालू किया जाए। झज्जर टू रिवाड़ी सड़क पर ड्रेन नं0 8 पर गांव सिलानी के पास बेली ब्रिज चालू करके रोड़ को ओपन किया गया है। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान दे। इसके अलावा 14–15 रोडज ऐसी है जो बिल्कुल टूटी हुई हैं। इनको भी जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कृपा की जाए। ऐप्रोच रोड औरंगपुर टू जाहिदपुर को रिपेयर किया जाए और इसके बीच में एक पुल बनाया जाए। यह तकरीबन सौ मीटर लम्बा होगा। इस पुल के होने से यह रोड चालू हो सकता हैं। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि नेवला गांव से कनौरी गांव तक वास उस्मापुर विलेज एक ऐप्रोच रोड बनाई जाए ताकि फ्लड के टाईम पर इन लोगौं को आने जाने में आसानी रहे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह एक सैनिक तहसील है लेकिन फ्लड की वजह से यह बिल्कुल तबाह है उसको फुल फलैज्ड आई0टी0आई0 बना दिया जाए ताकि इस इलाके के लोगों की बेरोजगारी दूर हो।

अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपल कमेटी झज्जर की फाइनैन्- ाल पोजी ान बड़ी कमजोर है। इसको फाइनैन ाल एड दी जाए जिससे भाहर की सड़कों, नालियों और बिजली का बन्दोबस्त हो सके। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, फ्लड की वजह से रोड़ खराब होने के कारण वहां बसों की हालत भी खराब हुई है। इस समय झज्जर में बड़ी मुि कल से पांच या छः नई बसें होगी, बाकी सब खराब पड़ी है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे।

स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन जी जो हमारे उद्योग मंत्री हैं, ने कुछ अर्सा पहले झज्जर में भाशण करते हुए उसे इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोशित किया था और कहा था कि ये वहां आई0एम0एम0 की स्कीम भी लागू करेंगे ताकि वहां की बेरोजगारी का मसला खत्म हो लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि झज्जर के इलाके को जल्दी से जल्दी बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया घोशित किया जाए ताकि वहां की कुछ डिवैल्पमैंट हो सके। (विघ्न)

अन्त में स्पीकर साहब, मेरी यह प्रार्थना है कि रेलवे लिंक की जो उस इलाके की पुरानी डिमांड है उसको भी जल्दी पूरा किया जाए।

श्री जय नारायण (कलानौर, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मेरे कलानौर हलके के अन्दर दो तीन रोडज जैसे कटेसरा से निगाना और काहनोर से निगाना ऐसी है जिनके ऊपर आठ दस साल से ईंटे बिछी हुई है और रोड़ी पड़ी हुई है। अगर उस वक्त उनके ऊपर तारकोल भी डाल दिया जाता तो गवर्नमैंट का इतना लौस न होता। वे सड़कें दस साल से उसी तरह

टूटी–फूटी हालत में पड़ी हुई है जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। यही नहीं दो दो महीने तक रास्ता ब्लौक हो जाता है। इसी तरह से काहनौर से सुडाना ऐसी सड़क है जिसकी तरफ भी सरकार को जल्दी ध्यान देने की आव यकता है। ये गांव मीलों तक पानी से धिर हुए है। चारों तरफ से यहां आने जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। पिछले साल भी चार महीने तक यह रास्ता ब्लौक रहा। अगर इस सड़क पर तीन मील का टुकड़ा बना दिया जाए तो जो आज तीस किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है उसकी बचत हो जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से गुजारि ा करूंगा कि कलानौर हलके की इन रोडज की तरफ भी जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाएं।

श्री दीप चंद भाटिया(फरीदाबाद): स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है। मैं हाउस का थोड़ा सा टाईम लूंगा। अर्ज यह है कि जितने भी हमारे मैम्बर साहिबान बोले है, सबने अपने हलके के बारे मैं बात की है। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, चाहे वह सड़कों की बात है, चाहे पानी की बात है, चाहे स्कूलों की बात है और चाहे दूसरे डिपाटमैंटस की बात है हर मिनिस्टर कोि ा ा कर रहा है कि वह चीफ मिनिस्टर को राजी कर ले। (विघ्न) लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम भी और अपोजि ान के एम0एल0एज0 भी जनता के चुने हुए है। मैं तो चाहता हूं कि जब

कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उसको देखना चाहिए कि सारा हरियाणा जो है वह उसका है। हरियाणा में 90 हलके है। सरकार को चाहिए कि यह सारे पैसे को सब हलकों में बराबर बराबर बांटे। चौधरी बंसी लाल की सरकार की तरह गलती मत करे। नहीं तो कहीं जनता सरकार उड़ न जाए। (हंसी)

स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा पानी के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मेरे इलाके मैं सब जगह पानी कड़वा है, खारा है।

श्री अध्यक्षः इस वक्त तो सड़कों की बात हो रही है।

श्री दीप चंद भाटियाः स्पीकर साहब, थोड़ी सी पानी की बात भी करने दो। (हंसी) सरदार लछमन सिंह जी ने कुछ पैसा तो चीफ मिनिस्टर साहब के जिला को दे दिया और कुछ अपने अम्बाला जिला के लिए ले लिया। (ाोर)

श्री लछमन सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मिस्टर स्पीकर।

श्री दीप चंद भाटियाः हम जनता पार्टी के एम0एल0ए0 है।———(विघ्न)

श्री अध्यक्षः भाटिया साहब, आप त ारीफ रखिए। (ाोर) आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री लछमन सिंहः मिस्टर स्पीकर, मेरी मु कल यह है कि बतौर मिनिस्टर मैं बोल नहीं सकता। (विघ्न) आप देखें कि

1734 सड़कें बनी है जिनमें से 184 सड़कें केवल कालका हलके में बननी बाकी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस डिसक ान का जवाब दें।

लोक कार्य मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): स्पीकर साहब, मैम्बर्ज साहिबान ने सड़कों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। मैं उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सबसे बड़ी परे ाानी हमे फ्लड से हुई उसकी वजह से बहुत सारी सड़कें टूट गई। बहुत सी सड़को पर मिट्टी डलवानी पड़ी और बहुत सी सड़कों की मुरम्मत करनी पड़ीर। एक एक सड़क पर काफी खर्च करना पड़ां अगर यह खर्च हमे ंन करना पउ़ता तो बहुत सारी और सड़कें बन जाती। इस वजह से सड़कें थोड़ी सी कम बनी। हमारी सड़कें इस वक्त तीन टाईप की है। ए, बी और सी। ए टाईप वे सड़कें है जिन पर काम भाुरू हो चुका है या जिन पर थोड़े गैप बाकी है ये बहुत जल्दी कम्पलीट हो जाएंगी। बी टाईप सड़कें वे है जिन पर मिट्टी आदि गिरी हुई है। ए टाईप की सड़कें बनने के बाद इन पर काम भाुरू करेंगे। सी टाईप की सड़कें वे है जिन पर कोई काम नहीं हुआ है। जो गांव सड़कों पर मिट्टी डलवा देंगे उनकी सड़कों को सी टाईप की सड़कों से पहले बनवा देंगे।

स्पीकर साहब, कई ढ़ानियां ऐसी है जिनमें रोड नहीं थी। वे विलेज डासरैक्टरी पर नहीं थी। अब हम उन गांवों को भी रोडज की फैसिलिटी देंगे।

कई मैम्बर्ज ने स्पीकर साहब, करप्ान की बात की। इसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कई काम तो महकमा खुद ही करता है जैसे मिट्टी का, तारकोल का और सीलिंग आदि का, लेकिन कई काम बाहर से करवाता है। इस बारे में मैं काफी सख्त हूं। कोई भी िकायत जब कभी मुझे लिख कर आती है या किसी की चिट्ठी भी मुझे आती है तो मैं उस पर पूरा ऐक्ान लेता हूं और आगे भी लूंगा (थम्पिंग) लेकिन मेरी मैम्बर साहिबान से दरख्वास्त है कि वे मेरे पास सिफारि ा के लिए न आए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने करप्ान को खत्म करने का ऐलान कर रखा है। जहां तक इस बारे में मेरे महकमें का संबंध है मैं हाउस को यकीन दिला सकता हूं कि यदि यह मेरे महकमें से पूरी तरह खत्म न हुई तो बहुत हद तक कम जरूर कर दूंगा। (प्र ांसा) लोग महसूस करेंगे कि इस महकमें में किसी ने कोई काम नहीं किया है। (प्र ांसा)

स्पीकर साहब, कई सड़कें है जैसे कोई गांव पहले किसी और जिले में था और अब दूसरे जिलें में चला गया है मजबूरी की हालत में वहां पर सड़क बनानी पड़ी है। कई गांव ऐसे है जिनकी तहसील बदल गई है। अब तहसील बदल जाने से उन लोगों को घूम कर और चक्कर काट कर वहां पहुंचना पड़ता

है। हम नहीं चाहते थे कि वहां पर सड़क बनाई जाती परन्तु बनानी पड़ रही है। जैसे मेरा अपना गांव मैंसरू बहादुरगढ़ तहसील में चला गया और पहले रोहतक तहसील में पड़ता था इसलिए अब वहां जाने के लिए हमे ंकोई सड़क बनानी पड़ेंगी।

कई भाइयों को सिरसा जिले के बारे में ि ाकायत थी कि वहां पर अधिक सड़कें बनाई जा रही है। वहां पर 72.21 परसैंट सड़कें बनी है और हमारी एवरेज स्टेट की 81.10 परसैंट है। इसलिए अभी तक वहां पर पूरी सड़कें नहीं बनी है। जहां तक अम्बाला जिले का संबंध है उसकी सड़कों के लिहाज से ि ाकायत दुरूस्त हो सकती है लेकिन वहां पर जो पुल बनाए हुए है उन पुलों के बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आता हैं। एक पुल के बनाने पर इतना खर्चा हो जाता है कि सारे जिले की सड़कें बन सकती है इसलिए अम्बाला जिले पर पैसा खर्च करने के हिसाब से कोई कमी नहीं की गई है।

चौधरी लाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अम्बाला जिले मैं टांगरी और बेगना का पुल आज तक नहीं बना है।

चौधरी मेहर सिंह राठीः इस बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि जो जिले पीछे रह गए है उन जिलों के लिए भी कोि ा ा करेंगे कि बराबर लाया जाए। अम्बाला जिले के हिस्से में जितनी सड़कें आती है, जरूर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई

भी जिला इग्नोर हो। किसी भी सदस्य को यह महसूस नहीं करना कि उसके हलके में कम सड़कें दी जाएंगी। चाहे कोई अपोजी ान का सदस्य है या रूलिंग पार्टी का सदय है सब को बराबर सड़कें दी जाएगी।

जहां तक भाहरों का संबंध है वहां पर म्युनिसिपल कमेटी बना कर देंगी। हम तो जहां पर पैसा खर्च करना है वहीं पर करेंगे। जिन सड़कों को प्रायरिटी देने की आव यकता है उनको दे रहे है। इसलिए और अधिक न कहते हुए यही कहना चाहता हूं किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी।

Mr. Speaker: Hon. Members, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 30th August, 1978.

18.14 बजे

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 30th August, 1978.)